

ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572



नवीन सामाजिक शोध

अंतराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
NAVEEN SAMAJIK SHODH
International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-11 (कुल अंक-95) जनवरी 2017
मूल्य - 100 रुपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development

नवीन सामाजिक शोध



मासिक शोध पत्रिका

अध्ययन एवं अनुसंधान पर
आधारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने पर

ISSN:0975-4431 प्राप्त हुआ

हम सभी क्षेत्रों विषयों पर वैज्ञानिकों प्रोफेसरों और शोधार्थियों द्वारा तैयार शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं शोधार्थियों द्वारा अपना रिसर्च वर्क प्रारम्भ करने से पूर्व पांच शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी इंगलिश भाषाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

सामान्यतः विज्ञान विषयों के शोध पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं किन्तु हम विज्ञान विषय के शोध पत्र भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित करते हैं। जिससे हमारे मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं।

अतः हमारी पत्रिका में केवल उच्च गुणवत्ता प्राप्त अनुसंधानिक/शोध पत्र ही प्रकाशित किये जाते हैं।

प्रकाशक

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

जर्नल सामाजिक शोध

संस्थापक प्रधान सम्पादक
स्व.डॉ.जी.सी. सक्सेना

प्रधान सम्पादक
राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

संपादक
श्रीमती सविता सक्सेना

उपसंपादक
डॉ.सजय अग्रवाल (चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

शोध अधिकारी
डॉ. ममता दुबे ग्वालियर
श्रीमती रितू मेहरा

ग्राफिक्स
तनवीर कुरेशी

सलाहकार संपादक
राजेश सक्सेना

वर्ष-8 अंक-11 (कुल अंक 95) जनवरी 2017

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572

ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय : 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड,

भोपाल-462041 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

Email : naveensamajikshodh@yahoo.com

Website : www.naveensamajikshodh.com

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक

पो.बॉ. नं. 361, पोस्टल कोड नं. 319, सहम सुलतानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोट (अर्थशास्त्री)

प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन, युनिवर्सिटी शास्त्राह यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,

111, शेख रसीद बिल्डिंग, शेख जायद रोड, यू.ए.ई. दुबई

4. डॉ. प्रिन्स डेविड दंत चिकित्सक

11, अंलब्रेस्ट एवंच्यु, माउंट रास्किल, ओकलैंड 1041, न्यूजीलैंड

5. श्री सजय चतुर्वेदी,

स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी थाईलैंड

6. श्रीमती ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमती प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/- वार्षिक : 1000/-
आजीवन सदस्यता 10000/-

विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर

सारे भुगतान (मनीऑर्डर/चैक/ड्रॉफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से किए जाएंगे। चैक से भुगतान करने पर रु.30-अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक-राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई. आफसेट वर्क्स, 81, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेडी, भोपाल-8 द्वारा मुद्रित एवं 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल-462023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक-श्रीमती सविता सक्सेना

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार हैं। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णतः अवैतनिक एवं अत्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. विभिन्न कालों में महिलाओं की परिस्थिति.....राजश्री साहू - 6
2. मेक इन इंडिया.....आरती श्रीवास्तव - 13
3. अनुसूचित जनजाति विकास में विधिक प्रावधान.....सुश्री ताई चौरसिया - 19
4. भारत में कौशल विकास.....डॉ. सीमा श्रीवास्तव - 23
5. उच्च शिक्षा में परिवर्तन चुनौतियाडॉ. (श्रीमती) अमोल मांजरेकर - 29
6. विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव.....पापिया चतुर्वेदी - 34
7. नोट बंदी का भारतीय समाज पर प्रभाव.....नीलिमा चटर्जी - 40
8. सामाजिक मीडिया और बाजार वादनीलिमा चटर्जी - 47
9. शिक्षा जगत के बदलते मायने.....डॉ. जे.पी. माकवे - 53
10. Arabic studies in India.....Nageena Akhter - 60
11. Importance of Arabic in India.....Imtiyaz Ahmad Wani - 68
12. The Impact of QuranSyed Mohd Amin Shah Bukhari - 74
13. Mahmud Darwish, Distinguishing features.....Mukhtar Ahmed - 79
14. Environment.....D.N. Yadav - 84
15. History of Scindia's.....D.S. Pawar - 93

सलाहकार मंडल

- प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान, पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल-म.प्र.। फोन : 0755-2424777
- प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना, पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.। फोन : 0755-2628055
- प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-म.प्र.।
- प्रो. डॉ. राजपाल सिंह, सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार। मो. 9425028689
- डॉ. के. के. तिवारी शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर मो. 9893014415
- वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान, पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल-म.प्र.। मो. 9826225266
- श्री आई.बी. सिंह, पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट-म.प्र.। मो. 9329138005
- डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल-म.प्र.। मो. 9827007500

संपादक मंडल

- ❖ प्रो. संजय एस. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- ❖ प्रो. अलका डेविड, विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- ❖ प्रो. अरविंद चौहान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- ❖ प्रो. आर.शंकर, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरुचरापल्ली-तमिलनाडु (620024)।
- ❖ प्रो. परवेज अहमद अब्बासी, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- ❖ डॉ० कुमारी चित्रा शर्मा संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- ❖ प्रो. डॉ. कामिनी जैन, प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- ❖ प्रो. आभा चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- ❖ डॉ. वंदना बक्शी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- ❖ डॉ. दिनेश परमार, अनुवाशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- ❖ डॉ. आस्ती श्रीवास्वत, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरुल्लागंज।
- ❖ डॉ. जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैंकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, जी.जी. डी.एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- ❖ डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- ❖ श्री अजय बिसारिया, व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि., अलीगढ़-उ.प्र.।
- ❖ डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- ❖ डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- ❖ इंजि. रोहन गुप्ता, एम-2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- ❖ डॉ. अमित कुल्हार, जिला पंचायत भोपाल
- ❖ मो. अनवर संवाददाता दैनिक पत्रिका भोपाल

सम्पादकीय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज कराने वाले गरीब मरीजों की ऑनलाइन गिनती करने की एम्स प्रशासन की योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। एम्स प्रशासन को ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सीमित बजट में सभी गरीब मरीजों का इलाज करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस योजना का मकसद गरीब मरीजों के इलाज पर आने वाले खर्च का ब्योरा तैयार कर संबंधित राज्य सरकारों को भेजना है ताकि वह उनसे आर्थिक मदद की अपील कर सके। यह सही है कि एम्स देश का सबसे बेहतर सुविधाओं वाला अस्पताल है। दुनियाभर के डॉक्टर यहां के चिकित्सकों का लोहा मानते हैं। इस संस्थान के डॉक्टरों ने अनगिनत ऐसे मरीज ठीक किए हैं, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे। इसके अलावा कई दुर्लभ ऑपरेशन भी इस संस्थान के डॉक्टरों के नाम दर्ज हैं। यही वजह है कि देश के कोने-कोने से इलाज की चाह में मरीज इस संस्थान का रुख करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो एक दिन में इस संस्थान में करीब 10 हजार मरीज ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) की सेवा लेते हैं। दरअसल, 15 राज्यों ने अपने बीपीएल कार्ड को ऑनलाइन कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए एम्स गरीब मरीजों की ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा ट्रायल के रूप में शुरू कर चुका है। इससे मरीजों को जल्द इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि या संस्थान के बजट से पैसा मिल जाएगा। साथ ही यह पता चल सकेगा कि कोई मरीज किसी दूसरे विभाग या अस्पताल से कोई आर्थिक मदद तो नहीं ले रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य सरकारों ने बजट मुहैया कराने से इन्कार कर दिया तो क्या होगा? ऐसे में तो गरीब मरीज ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन दूसरी ओर यह भी सही है कि आखिर एम्स खुद के बजट से कितने मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। हर राज्य सरकार स्वास्थ्य के लिए जब अलग से बजट प्रावधान करती है तो फिर वह उसी में से कुछ हिस्सा क्यों नहीं एम्स को देती है, जिससे उसके यहां से आने वाले मरीजों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्स प्रशासन की इस कवायद के बाद शायद ऐसा मुमकिन हो पाए तो संस्थान के पास गरीब मरीजों का इलाज करने के लिए और संसाधन उपलब्ध हो जाएगा।

विभिन्न कालों में महिलाओं की परिस्थिति

राजश्री साहू

सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र विभाग

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

करौंदी कटनी (म.प्र.)

परिचय – वैदिक काल के प्रारम्भिक समय में स्त्रियों का स्तर बहुत उच्च था क्योंकि उन्हें 'देवी' का पद दिया गया था और ऐसा मानते हुए उनकी पूजा की जाती थी। स्त्री परिवार में अपने पति के साथ सयान अधिकार और उत्तरदायित्यों की अधिकारिणी होती थी। वह अपने पति के साथ समान अधिकार और उत्तरदायित्यों की अधिकारिणी होती थी। वह अपने पति का एक अंग मानी जाती थी और प्रत्येक धार्मिक कार्य, यज्ञ आदि में उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। ऐसा आभास होता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की विचारधारा के विकास के साथ ही स्त्रियों ने अपनी स्वतन्त्र स्थिति को धीरे-धीरे खो दिया।

“बचपन में पिता के द्वारा युवावस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्था में पुत्रों के द्वारा स्त्री की रक्षा की जाती है। स्त्रियाँ कभी-भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती हैं।” यह मनु-संहिता में कहा गया है। जो हिन्दु-धर्मशास्त्र का एक आवश्यक अंग है।

भारतीय इतिहास के मध्यकाल में मुस्लिम शासन का अधिक प्रभाव था उसमें स्त्रियों की स्थिति का और भी पतन हुआ। समाज में व्यापक दशाओं के कारण मुसलमानों की दृष्टि से स्त्रियों को दूर रखने की कोशिश की गई, जिससे 'पर्दा' प्रथा प्रारम्भ हुई, जिससे उनकी उन्नति का मार्ग और भी बन्द हो गया। स्त्री के अस्तित्व और व्यक्तित्व को लूट कर समाज ने उसको सती बताया जो परम्परागत रूप से महान त्याग का सूचक है इसी समय में वेश्यावृत्ति स्त्री जाति की बालत्या, बहुविवाह, कलीनता और बाल-विवाह आदि कुरीतियाँ भी अधिक प्रबल हो चली थी।

अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ ही एक नवीन सामाजिक युग का प्रारम्भ हुआ। धर्म-प्रचारक

ईसाई संस्थाओं ने हिन्दू सामाजिक ढाँचे में व्याप्त दोषों और अभावों को प्रकाश में लाकर समाज में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। उन्होंने विधवा विवाह प्रारम्भ करने के लिए भी प्रयास किए।

राजा राममोहन राय पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सती-प्रथा को समाप्त करने का सफल समर्थन किया और इस सम्बन्ध में सन् 1829 में एक कानून पास किया गया। अन्य समाज-सुधारकों ने भी स्त्रियों के उत्थान अधिक प्रयास किये परिणामस्वरूप कुछ सामाजिक सुधारों से स्त्रियों की दुखदायी स्थिति में कमी आई।

जिन समस्याओं का समाधान किया जा चुका था, वह इस प्रकार है।

विधवाओं का पुनर्विवाह, उनकी शिक्षा, पर्दा-प्रथा बाल-विवाह, सम्पत्ति पर उनके अधिकार और आभागी स्त्रियों के कल्याण के लिए कुछ अन्य कार्य भी किये गये।

अधिनियम जो स्त्री कल्याण में सहायक सिद्ध हुए वह निम्नलिखित हैं-

विवाह अधिनियम, 1861 बालविवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 हिन्दू स्त्री सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 1937 दहेज प्रथा अधिनियम।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम समय में और आगे भी कल्याणकारी संस्थाओं ने 'सेवा सदन' और 'विधवा गृह' व्यापक अनैतिक व्यापार को रोगने के लिए भी सन् 1923 में एक कानून पास किया गया। आजादी के बाद स्वतन्त्र भारत के संविधान ने भी हिन्दुस्तान की आधी आबादी के प्रति अपने कर्तव्य की रसम अदायगी की और उसे "वीकर सेक्शन ऑफ सोसायटी का दर्जा देकर, उसके कल्याण के लिए उसे बच्चों व अपंग वर्गों के साथ जोड़कर केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के हवाल कर दिया। कुछ अधिनियमों को पारित करने की खानपूर्ती भी की गई, जैसे हिन्दू विवाह एवं विशेष विवाह अधिनियम को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, गोद लेने व भरण-पोषण सम्बन्धी अधिनियम, बाल विवाह तथा दहेज निशेध अधिनियम इत्यादि।

स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद असम्य महिलाएँ अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाता है। उनका अपहरण किया जाता है। उनके साथ बलात्कार किया जाता है। उनको जला दिया जाता है। उनको उत्पीडित करने वाले और हिंसा के अपशयकर्ता कौन लोग हैं ? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मूल कारण क्या है।

महिला कल्याण की दिशाएँ -

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 49.87 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 48.2 प्रतिशत है।

स्वतन्त्रता के बाद से ही महिलाओं की उन्नति विकास योजनाओं का केन्द्र-बिन्दु नहीं है पिछले 55 वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में नीति-निर्माण में कई परिवर्तन आए हैं। जिसमें 70 के दशक तक 'कल्याण' की संकल्पना से 80 के दशक तक 'विकास' की नीति और 90 के दशक में 'अधिकार' व 21 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में 'सशक्तिकरण' पर जोर दिया गया है। महिलाओं और बाल विकास विभाग प्रारम्भ से ही महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर को सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम लागू करता रहा है। जिनमें उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम लागू करता रहा है। विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा ग्रामीण व शहरी विकास आदि जैसे लागू अन्य विकासोन्मुखी कार्यक्रम और महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

महिला कल्याण का क्रमिक इतिहास -

1971 में महिला परिस्थिति के अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और नौकरियों के संवैधानिक कानूनों और प्रशासनिक प्रावधानों को देखना था इन प्रावधानों का पिछले 20 वर्षों में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तथा उनके उत्थान के लिए प्रभावत्मक योजना पर विचार करना था।

उस समिति ने छः छोटी क्वेश्चरियों और दो अध्ययन समूह बनाए जो कि विधि, सेवा नियोजन, शिक्षा आर्थिक जीवन के पहलू, राजनीति में सहभागिता, सामान्य सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य, समर्याएँ में परिवर्तन को देखेंगे।

समिति की कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ इस प्रकार थी -

1) भारत सरकार को महिलाओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति संवैधानिक निर्देशों और प्रावधानों के आधार पर अपने देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए समय समय पर बनानी चाहिए।

2) बाल विवाह अधिनियम का विस्तृत उल्लंघन होता है। विशेषरूप से गाँवों में गुजरात सरकार ने इसको ज्ञात अपराध बना दिया तथा एक बाल विवाह अवरोधक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। जैसे कि यू. एन. ने संस्तुति की कि विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाना चाहिए।

3) 1961 का दहेज निवारण कानून अकेला अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। दहेज के निरन्तर बढ़ते रहने पर भी इस कानून के अन्तर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी। कि इसमें कोई भी वस्तु भेंट और उपहार के रूप में स्वीकृत थी।

4) महिला परिस्थिति (जंजने व विउमद) - पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की 25वीं रिपोर्ट में राष्ट्रीय आयोग या इसी प्रकार की अन्य समिति की नियुक्ति की संस्तुति की गई है। जिससे कि स्त्रियों की

शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा योजना आदि की नीति का पुनरावलोकन किया जा सके।

पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएँ – (बीमरुमे जवर्त वउमद मसजतम न्दकमत जीम थपअम त्मत च्सदे) –

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1978-83)– महिला कल्याण योजना के अन्तर्गत सामाजिक और गरीबता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। 1978-83 वर्षों के दौरान ग्रामीण और नागरिक कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए शिशु-सदन और बालवाडी केन्द्रों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

छठवीं पंचवर्षीय योजना – महिला कल्याण का एक विशिष्ट अध्याय जोड़ा गया है। स्कूलों में लड़कियों के उच्चतर नामांकन तथा बने रहने के लिए स्कूलों के समीप बालवाडी-शिशु सदन खोले गए जिससे कि लड़कियाँ माँ की नौकरी पर जाने के समय में शिशुओं की देखभाल में न लगी रहें। अन्य प्रोत्साहन जैसे- स्कूल की यूनीफार्म ड्रेस तथा किताबें-स्टेशनरी आदि देने की भी आवश्यकता रही है।

1) ग्रामीण महिलाओं का विकास और अधिकारिता (सर्वशक्ति) परियोजना – (त्ततस वउमदरे कमअसवचउमदज दक म्चवूमतउमतज डूँजप चतवरमबज) केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में इसे 16 अक्टूबर 1998 को पाँच वर्ष के लिए मंजूर किया गया तथा इसके लिए 186.21 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक और बिहार के 35 जिलों में यह परियोजना चलाई जा रही है।

2) महिला समृद्धि योजना (डीपसै उतपकीप त्वरद)– देश की ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालने के उद्देश्य से सन् 1993 में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी। अब यह योजना इन्दिरा महिला योजना में सम्मिलित कर दी गई है।

3) राष्ट्रीय महिला आयोग (छंजपवदस बउउपेपवद जवर्त वउमद) – राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था।

महिला कल्याण और सहायता सेवाएँ (वउमद मसजतम दकीमसचै मतअपबमे)– वर्ष 2001-02 के दौरान 840 कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 अतिरिक्त होस्टलों की मंजूरी दी गई। इस प्रकार कुल होस्टलों की संख्या 881 हो गई है जिससे 62,308 कामकाजी महिलाएँ लाभान्वित हुईं।

महिला रोजगार और प्रशिक्षण – महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के मदद देने का कार्यक्रम

1987 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, हाथकरधा, हस्तशील, कुटीर और ग्राम उद्योग तथा रेशम कीटपालन सामाजिक, वानिकी और बंजर भूमि जैसे महिलाओं की प्रधानता वाले परम्परागत कार्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके हुनर में और सुधार करना है।

अब तक 5,63,983 महिलाओं को 131 परियोजनाओं के जरिये इससे लाभ हुआ है। सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के जरिये इन संगठनों की पहचान की जाती है। वर्ष 2001-02 के दौरान 556 स्वयंसेवी संगठनों के जरिये 1,17,222 लाख रुपये मंजूर किए गए, जिससे 24,830 महिलाओं को लाभ पहुंचा।

लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन – माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2006 को आयोजित महिला पंचायत के अवसर पर यह घोषणा की गई कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कल्याणों के जन्म के समय उनके नाम से राशि जमा करने की योजना तैयार की जायेगी जिसके तहत कन्या की आयु 21 वर्ष होने पर उसे एक लाख रु. मिलेगी। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू की जायेगी।

योजना का स्वरूप –

- 1) जिसका जन्म दिनांक 1 जनवरी 2006 या उसके पश्चात् हुआ हो, योजना हेतु पात्र होगी।
- 2) यदि बालिका का योजना में पंजीकरण, बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अन्दर किया गया हो, या यदि बालिका अपनी माता-पिता की प्रथम सन्तान है, तो द्वितीय सन्तान के जन्म के 1 वर्ष के अन्दर किया गया हो।
- 3) परन्तु यदि प्रथम एवं द्वितीय का जन्म 1 अप्रैल 2007 के पूर्व हो चुका है। तो ऐसी बालिकाओं का पंजीयन, योजना प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के अन्तर अर्थात् 31 मार्च 2008 तक कराया जा सकेगा।
- 4) बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय रुपये 600/- तथा उसके पश्चात् लगातार 4 वर्षों तक रु. 6000 के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जायेंगे। इस प्रकार कुल राशि रु. 30,000 के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम, क्रय किये जायेंगे।

योजना से अपेक्षित लाभ –

- 1) बाल विवाह में कमी।
- 2) बालिकाओं के शिक्षा के स्तर में सुधार।
- 3) बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार।

4) लिंगानुपात में सकारात्मक परिवर्तन।
5) परिवार नियोजन को प्रोत्साहन, विशेषतः दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म की चाह में कमी।

6) जनसंख्या वृद्धि दर में कमी।

योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया -

1) योजना में पंजीकरण हेतु, आवेदन पत्र का प्रारूप डाकतार विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

2) आवेदन पत्र वर्ष में एक बार या एक ही अधिक बार आमंत्रित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा।

3) परियोजना अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को, उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि के अनुक्रम में पंजी में दर्ज करेगा।

4) बालिकाओं के पक्ष में ऐसे जारी किये गये राष्ट्रीय बचत पत्रों को गणसन के पक्ष में निर्धारित नियमों के तहत प्लेज किया जायेगा, एवं राष्ट्रीय बचत पत्र हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना क्रियान्वयन की समीक्षा -

1) योजना की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश गणसन, महिला बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में एक स्थाई सशक्त समिति गठित की जायेगी, जिसमें सचिव, मध्यप्रदेश गणसन, वित्त विभाग, प्रतिनिधि डाकतार विभाग, सदस्य एवं आयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। समिति योजना की प्रवर्तन नियमों में संशोधन तथा सुधार योजना के अन्तर्गत अंशदान की राशि का पुनर्निर्माण योजना की निरन्तरता समाप्ति के संबंध में, अनुशंसा करने हेतु सक्षम होगी। योजना के किसी भी नियम एवं प्रवर्तन के निर्वहन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(पी. नरहीर)

उपसचिव

मध्यप्रदेश गणसन

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल

निष्कर्ष - आज के इस तथा कथित आधुनिक युग में तो औरत पर दोहरी भार पड़ रही है। एक

ओर तो उसे सामन्ती परम्पराओं, वर्जनाओं और कठियों से जूझना पड रहा है। तो दूसरी ओर भूमण्डलीकरण की भौतिकवादी चकाचौध ने महिलाओं के वस्तुकरण की प्रवृत्ति को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है। पूँजीवाद की घोर बाजारवादी होड में लगे मुनाफाखोरों द्वारा महिलाओं के जीवन पर नियन्त्रण बढ़ता जा रहा है महिला सशक्तिकरण के इस युग में भी समाचार पत्रों की सुर्खियाँ नारी के प्रति दिनों दिन बढ़ती हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्याओं और उत्पीडन की दिल दहलाने वाली खबरों से भरी रहती है। हर जनगणना के साथ स्त्रियों का प्रतिशत पुरुशों की अपेक्षा गम्भीर रूप से घटता जा रहा है। बालिकाएँ कुपोशण की शिकार हो रही हैं।

सन्दर्भ सूची –

1) विवके प्रकाशन :- समाज कार्य, डॉ. जी. आर. मदन

पृष्ठ :- 112, 113, 115, 117, 120, 122

2) मध्यप्रदेश गसन – महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पृष्ठ :- 06, 07, 08, 09, 10, 11

3) कैलाश पुस्तक सदन – समाज कार्य, डॉ. डी. एस. बघेल।

मेक इन इंडिया

आरती श्रीवास्तव

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग

शा. महाविद्यालय नसरुल्लागंज जिला सीहोर

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान एक नयी योजना है, जिसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्ययसायों में पैसा लगाने के लिये एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुदेशीय कंपनियों को प्रसन्न करने के लिये भारतीय सरकार द्वारा ये एक शुरुआती अभियान चलाया जा रहा है। भारत में रोजगार लाने के लिये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये एक प्रयास है। नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गयी थी।

पीएम नरेन्द्र मोदी के द्वारा शुरू हुआ मेक इन इंडिया एक ऐसा अभियान है जो भारत में व्यापार की इच्छा रखने वाले पूरे विश्व भर के बड़े व्यापारिक निवेशकों को सहज बनाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम के द्वारा 25 सितंबर 2014 हुई। देश के युवाओं के द्वारा सामना किये जा रहे हैं बेरोजगारी के स्तर को घटाने के लिये भारतीय सरकार के द्वारा ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंगल मिशन के एक दिन बाद इस अभियान की शुरुआत की गयी थी जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी यूएसए के अपने पहले दौरे पर जाने वाले थे।

इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर का उत्पादन का पावरहाऊस बनाने है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े मुद्दे का समाधान करने में जरूर मदद करेगी। मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष), अजीम प्रेमजी (विप्रो के अध्यक्ष) आदि सहित भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ नयी दिल्ली में सफलतापूर्वक विदेशी निवेशकों के लिये नये समझौते के साथ इस पहल की शुरुआत हुई।

नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गयी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ ही एक प्रभावशाली लक्ष्य की ओर भारत को मुख्य भूमिका निभाने के लिये इस अभियान को चलाया गया। ये देश के युवाओं के लिये रोजगार का एक सफल रास्ता उपलब्ध कराता है जो निश्चित ही भारत में गरीबी के स्तर को घटाने और दूसरे सामाजिक मद्दों में मदद करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूरे विश्व के प्रमुख निवेशकों के लिये मेक इन इंडिया एक आह्वान है, कि भारत आओ और यहाँ उत्पादों के निर्माण के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाओ। भारत के पीएम ने निवेशकों से कहा कि इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस देश में अपने उत्पाद को बेच रहे हैं हालाँकि आपको भारत में उत्पादन करना चाहिये। लक्ष्य को पाने के लिये भारत के युवाओं में प्रचुर मात्रा में योग्यता, कौशल, अनुशासन और प्रतिबद्धता है।

मेक इन इंडिया अभियान सभी मुख्य निवेशकों को एक लाभदायक अवसर उपलब्ध कराता है कि आप भारत आये और उपग्रह से पनडुब्बी, ऑटोमोबाइल से कृषि मूल्य योग, विद्युत से इलेक्ट्रॉनिक आदि किसी भी व्यवसाय में निवेश करें। नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, साइरस मिस्त्री, अजीम प्रेमजी आदि शिखर के उद्योगपतियों की मौजूदगी में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये मेक इन इंडिया योजना के संदर्भ में पीएम ने एक घोषणा की।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में 2015 में उभरने के लिए विश्व स्तर पर कार्यक्रम की दीक्षा के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका में श्रेष्ठ चीन की पीपुल्स गणराज्य के रूप में रूप में अच्छी तरह आशा व्यक्त की।

इलेक्ट्रॉनिक 2020 तक अमेरिका + 400 अरब के लिए तेजी से वृद्धि की उम्मीद हार्डवेयर के लिए मांग के साथ, भारत संभावित एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनने की क्षमता है। ख6, सरकार ने एक स्तर के खेल मैदान बनाने और एक अनुकूल माहौल प्रदान करके 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध शून्य आयात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

भारत में बनाओ अर्थव्यवस्था के निम्न पच्चीस क्षेत्रों पर केंद्रित हैरू गाडियां ऑटोमोबाइल अवयव विमानन जैव प्रौद्योगिकी रसायन निर्माण रक्षा विनिर्माण इलेक्ट्रिकल मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों खाद्य प्रसंस्करण सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन चमड़ा मीडिया और मनोरंजन खनिज तेल और गैस फार्मास्यूटिकल्स बंदरगाहों और शिपिंग रेलवे नवीकरणीय ऊर्जा सड़क और राजमार्ग अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान कपड़ा और परिधानों तापीय ऊर्जा पर्यटन और आतिथ्य कल्याण नई सरकार के अनुसार। नीति 100 : एफडीआई, सब से ऊपर क्षेत्रों में अनुमति दी है अंतरिक्ष (74:), रक्षा (49) और समाचार मीडिया (26) के लिए छोड़कर।

भारत, व्यापार सूचकांक जून 2014 और जून 2015 में भारत से इस अवधि को कवर करने के लिए विश्व बैंक के 2016 आराम में 189 देशों की 130 से बाहर 2015 सूचकांक में 134 वें स्थान पर था शुमार है। भारत 2009 की रिपोर्ट में विश्व बैंक की ड्रूइंग बिजनेस में 17 भारतीय शहरों के एक सर्वेक्षण में भारत में व्यापार करने के लिए शीर्ष पांच सबसे आसान शहरों के रूप में लुधियाना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुडगांव, अहमदाबाद और स्थान पर रही।

जनवरी से जून 2015 जनवरी 2015 में, स्पाइस समूह ने कहा कि यह 5 अरब (अमेरिका + 74 मिलियन) के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश में एक मोबाइल फोन विनिर्माण इकाई शुरू होगा। एक समझौता ज्ञापन पर स्पाइस समूह और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

जनवरी 2015 में, ह्यून बच्चों हॉंग, राष्ट्रपति और सैमसंग दक्षिण एशिया के सीईओ, कलराज मिश्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई), के साथ मुलाकात की एक संयुक्त पहल है जिसके तहत 10 एमएसएमई-सैमसंग तकनीकी स्कूल चर्चा करने के लिए भारत में स्थापित किया जाएगा। फरवरी में सैमसंग ने कहा है कि नोएडा में अपने संयंत्र में सैमसंग 1 निर्माण होगा।

फरवरी 2015 में, हिताची ने कहा कि यह पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहा जाता है कि यह 13,000 करने के लिए 10,000 से भारत में अपने कर्मचारियों में वृद्धि होगी और यह 210 अरब करने के लिए 2013 में 100 अरब से भारत से अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है एक ऑटो घटक संयंत्र 2016 में चेन्नई में स्थापित किया जाएगा।

फरवरी 2015 में, हुआवेई बेंगलुरु में एक नए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परिसर में खोला गया। यह अमेरिका के + 170 मिलियन का निवेश किया था अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए। यह चेन्नई में एक टेलीकॉम हार्डवेयर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है, जो अनुमोदन की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा फरवरी में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा है कि यह पहल के तहत भारत में झींगा किसानों को झींगा अंडे की आपूर्ति करने में दिलचस्पी थी। फरवरी 2015 में, ग्पंवउप श्री सिटी में एक फॉक्सकॉन रन की सुविधा में विनिर्माण उततजचीवदमे शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ प्रारंभिक वार्ता शुरू किया।

11 अगस्त 2015, कंपनी ने घोषणा की है कि पहली विनिर्माण इकाई परिचालन किया गया था और ग्पंवउप त्मकउप 2 प्रधानमंत्री, कि एक स्मार्टफोन की सुविधा में इकट्टा किया गया था की शुरुआत की। उप भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु जैन ने कहा, हम घोषणा की भारत में हमारे मेक इस वर्ष 2015, हमने सोचा कि यह हमारे दो साल लेने के लिए इस विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की शुरुआत में योजना बना रही है। लेकिन हैरत की बात है कि हम स्थापित करने में सक्षम थे सब कुछ है और

हमारे उत्पादन सात महीने के भीतर शुरू कर दिया।

जून 2015, फ्रांस स्थित एलएच उड्डयन भारत में विनिर्माण संयंत्र ज़ोन के निर्माण के लिए स्थापित करने के लिए OIS उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जुलाई से दिसंबर 2015 8 अगस्त को 2015, फॉक्सकॉन घोषणा की कि वह अमेरिका + 5 अरब पांच साल से अधिक का निवेश करेगी एक अनुसंधान और विकास और महाराष्ट्र में उच्च तकनीक अध्यात्म विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए। 2013, 2014, एक सप्ताह पहले, जनरल मोटर्स ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका + 1 अरब राज्य में ऑटोमोबाइल के निर्माण शुरू करने के लिए निवेश होगा की तुलना में कम है।

18 अगस्त 2015, लेनोवो घोषणा की कि वह चेन्नई के निकट श्रीपेरंबुदूर में एक संयंत्र, सिंगापुर स्थित अनुबंध निर्माता फ्लेक्सट्रॉनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा चलाए में मोटोरोला स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र शुरू हो गया था लेनोवो और मोटोरोला के लिए अलग लाइनों के निर्माण, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन दिया है, और उत्पाद परीक्षण। सुविधा में निर्मित पहला स्मार्टफोन मोटोरोला मोटो ई (2 पीढ़ी) की 4 जी संस्करण था। 16 अक्टूबर 2015, बोइंग के चेयरमैन जेम्स डबल्यूमटदमल ने कहा है कि कंपनी के लड़ाकू विमानों को इकट्ठा और भारत में अपाचे या चिनूक हेलीकाप्टर रक्षा या तो कर सकता है।, कंपनी ने भारत में एफ 16 -18 सुपर हॉर्नेट निर्माण करने के लिए यदि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) इसे खरीदने के लिए थे तैयार है।

नवंबर 2015 में, ताइवान के अज़गर कॉर्प, जो इस तरह के ब्लैकबेरी, एचटीसी और मोटोरोला जैसी कंपनियों के लिए उपकरणों बनाता है, घोषणा की कि वह नोएडा में एक नया कारखाना, उत्तर प्रदेश में उपकरणों के निर्माण शुरू होगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, सरकार के अभियान, देश की बढ़ती खपत के साथ मिलकर श्मेक इन इंडिया, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र सेक्टरों में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक उत्कृष्ट मामला बन गया है।

दिसंबर 2015 में, क्वालकॉम ने घोषणा की कि यह एक भारत में डिजाइन कार्यक्रम में मदद करने के लिए क्षमता के साथ दस भारतीय हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऊपर संरक्षक अभिनव समाधान के साथ आते हैं और उन्हें पैमाने तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। क्वालकॉम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वे सितंबर 2015 में सिलिकॉन वैली के उत्तरार्ध की यात्रा के दौरान ऐसा होता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कंपनी बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब की स्थापना की चयनित कंपनियों के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करने के लिए होगा। एबीसी ही महीने में, माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि यह होगा 3 अरब (अमेरिका + 45 मिलियन) की लागत से

राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नए विनिर्माण इकाइयों। पौधों 2016 में कामकाज शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक 3,000-3,500 लोगों को रोजगार देगा।

दिसंबर 2015 में भारत को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की यात्रा के बाद यह घोषणा की गई है कि जापान को एक अमेरिकी शजापान-भारत मेकअप में भारत-विशेष वित्त सुविधा षकहा जाता है भारत से संबंधित परियोजनाओं में मेक के लिए + 12 अरब षोष की स्थापना की जगएगी।

एक रक्षा सौदा दिसंबर 2015 में रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो कामोव केए-226 बहु-भूमिका हेलीकाप्टर भारत में बनाया जा रहा है देखेंगे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह व्यापक रूप से पहले रक्षा सौदा वास्तव में भारत अभियान में मेक के तहत हस्ताक्षर किए जाने के रूप में देखा जाता है।

अगस्त 2015 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत कार्यक्रम के तहत मेक सुखोई एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान के 332 घटकों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए रूस के प्तानज कॉर्प के साथ वार्ता शुरू की। इन घटकों को भी बुलाया लाइन बदलने की इकाइयों (LRUs) दोनों महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण घटकों को देखें और इस तरह के रेडियो और रडार के रूप में चार प्रमुख सिर में गिर जाते हैं य इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम य यांत्रिक प्रणाली और उपकरण प्रणाली है।

रक्षा मंत्रालय के एक ष 600 अरब (8.9 अरब अमेरिकी +) अनुबंध के लिए डिजाइन और भारत में एक लड़ाई पैदल सेना का मुकाबला वाहन (षट्ट) के निर्माण के लिए नीलामी की जाती है। अनुबंध 2016 में सम्मानित किया जाएगा

फरवरी 2016 पद, लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि यह था भारत में एफ-16 के निर्माण और भारत पहल में मेक का समर्थन करने के लिए तैयार है, हालांकि यह किसी भी समय सीमा की घोषणा नहीं की। 2015 में, भारत अमेरिका एफडीआई में 63 अरब + प्राप्त किया।

शून्य दोष शून्य प्रभाव ष एक नारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्पादन तंत्र जिसमें उत्पादों कोई दोष है और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो उत्पाद शून्य प्रतिकूल पर्यावरण और पारिस्थितिक प्रभाव है बना है का प्रतीक द्वारा गढ़ा गया है। नारा भी वैश्विक बाजार द्वारा अस्वीकार कर दिया जा रहा से भारत से विकसित उत्पादों को रोकने के लिए करना है।

झारखंड, गुमला के Aarisa Pitha, कश्मीर के ळनीजई, पंजाब, Khakhra और गुजरात के Khandvi, बांस भाप मछली, वड़ा और कर्नाटक, खाजा और बिहार और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पूरन पोली का कबाब की प्दतें की मेधु वड़ा का चिकन करी किया गया है पारंपरिक क्षेत्रीय भोजन

के रूप में चयनित अभियान में पदोन्नत किया जाना है। खूब,

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के 35 वें संस्करण नवंबर 2015 में प्रगति मैदान में आयोजित किया है, अपने विषय के रूप में भारत में बनाने के लिए किया था।

सन्दर्भ

<http://www.hindikiduniya.com/essay/make-in-india-essay-in-hindi/>

"Look East, Link West, says PM Modi at Make in India launch". Hindustan Times. 25 September 2014.

<http://www.thehindu.com/news/national/centre-states-to-ready-make-in-india-plan/article6731594.ece?ref=relatedNews>

http://www.business-standard.com/article/government-press-release/focus-on-make-in-india-114092501206_1.html

अनुसूचित जनजाति विकास में विधिक प्रावधान

सुश्री ताई चौरसिया

स्टेट लॉ कालेज, भोपाल

संक्षेपिका :

विधि का निर्माण समाज की अनुकूलता के अनुसार किया जाता है। आज के परिवेश में कल्याणकारी राज्य के नागरिक है जिसका कर्तव्य है कि जनसाधारण के सुरक्षा एवं समृद्धि को अभिवृद्धि करना है। समाज के दुर्बल वर्ग में शामिल अनुसूचित जनजाति समुदाय का भी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास हो ताकि वे अपना योगदान देश के विकास के मुख्यधारा में जोड़ सकें इसलिए केन्द्र व राज्य सरकार उनके चहुँमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। उनकी रक्षा व विकास के लिए अधिनियमों को लागू किया जिसमें प्रथम भारतीय संविधान 1950, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, पंचायत अधिनियम 1996, म.प्र. भू-राजस्व अधिनियम 1959 लागू किये व समय-समय पर संशोधन भी किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आदर्श ढांचे की संकल्पना है।

प्रस्तावना—

अनुसूचित जनजाति का इतिहास जहाँ एक ओर उनकी वीरता और समृद्धिशाली होने का प्रमाण प्राप्त होता है। वहीं उन्होंने मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किया, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए नये नीतियों का कानून कर निर्माण कर इन वर्गों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का

प्रयास किया है। ताकि विभिन्न अधिनियम एवं कल्याणकारी योजनाओं का सही रूप से समुचित क्रियान्वयन अनुसूचित जनजाति समुदाय में परिवर्तन व विकास कर सकें और अपना योगदान देश के विकास में दे सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रावधान—

अनुसूचित जनजाति संबंधित विधिक प्रावधान—

1. भारतीय संविधान 1950

संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए संवैधानिक सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान कर उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया।

अनुसूचित 14—विधिक के समक्ष समता

अनु. 15— धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जलस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनु. 15(4) 16(4) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के

अनु. 46— समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी प्रावधान सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

अनु. 259 क. अनुसूचित जनजातियों से प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपलब्ध।

अनु. 243 घ (1) अनुसूचित जनजातियों के पंचायत स्तर पर आरक्षण।

अनु. 349 – 342 = अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां को परिभाषित किया।

अनु. 330 – लोकसभा में आरक्षण अनु. 332 विधानसभा में आरक्षण।

अनु. 338 (क) में अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जायेगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989 का उद्देश्य— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध को करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उसके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

• धारा 3(2) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति झूठा साक्ष्य गढ़ेगा या फंसाने का प्रयास कराना है मिथ्या साक्ष्य पर यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है उसे भी मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो सकेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े हुए लोगों को जो मौसमी बेरोजगारी और आजीविका के लिए वनों एवं टेकेदारों द्वारा जमींदारों पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें सुनियोजित रूप से रोजगार की गारंटी हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 भारत शासन द्वारा पारित किया गया।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी

अधिनियम 2006 वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में पीड़ितों से निवास कर रहे हैं वन अधिकारों को अभिलेखित करने के लिए संरचना का और वनभूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम लंबे समय से चला आ रहा है भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुँच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए। परम्परागत वननिवासियों को उनके अधिकारों की संरक्षित करने के लिए इन अधिकारों की मान्यता दी है।

राज्य स्तरीय विधिक प्रावधान –

मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक आवादी वाला प्रांत है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के शैक्षिक, बौद्धिक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, चहुँमुखी विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा कई अधिनियम को लागू किया गया।

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम 1997

देशी मदिरा के विनिर्माण उसके कब्जे तथा साथ आदिवासियों के द्वारा देशी मदिरा का निर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और आर्थिक इस प्रकार देशी मदिरा के कब्जे को अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति परिवार 15 लीटर विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा आर्थिक समारोह के अवसर पर प्रति परिवार 45 लीटर होगी परन्तु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1959

धारा 165(6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ने उस संबंध में अधिसूचना द्वारा उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसकी यह कोड लागू होता है आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करती है।

भू-अर्जन एवं पुनर्वास (राजस्व) 1996

अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवस्थापन एवं पुनर्वास से पूर्व समुचित स्तर को पंचायत या ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा तभी भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये।

बाधित श्रम पद्धति (उत्सादन) 1976

उस अधिनियम का उद्देश्य समाज के दुर्बल वर्गों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश से बाधित श्रम पद्धति के उत्सादन का अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए बनाया गया है।-

म.प्र. अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 में पड़े जनजातीय परिवारों को तुरंत सहायता प्रदान करने संबंधी नियम।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993- संविधान ने अनु. 243 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सत्र 1993 के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने का संकल्प किया गया संशोधित 1996 किया गया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियम 1995- मध्यप्रदेश जनजाति आयोग का गठन किया गया है अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए हितप्रहरी की भूमिका निर्वाह कर रहा है।
निष्कर्ष-

भारत का संविधान संपूर्ण नागरिकों के साथ समानता एवं व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रदान करती है। वहीं जनजातियों के समुचित विकास के लिए विशेष प्रावधानों के संकल्पना को भी समाहित किया है। मध्यप्रदेश शासन ने भी इन वर्गों के बेहतर विकास एवं शोषण एवं अत्याचार से युक्ति के लिए म.प्र. राजस्व अधिनियम 1959, म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1996 भूमि अर्जन अधिनियम 1994 पुनः 2014 में नया भूमि-अर्जन अधिनियम पारित किया गया इससे इस वर्गों के सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होने की आशा है इनके विकास के लिए पर्याप्त विधियाँ अधिनियमित की जा चुकी उनका दृढ़ता से क्रियान्वयन किया जाय ताकि अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों को पिछड़ेपन गरीबी अशिक्षा, शोषण से मुक्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :-

1. भारत की संविधान जयनारायण पाण्डेय 2014 47वाँ संस्करण सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद।
2. वन अधिनियम 1927
3. श्रीवास्तव डॉ. ए.आर.एन. जनजातीय भारत म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2006

“भारत में कौशल विकास”

डॉ. सीमा श्रीवास्तव
सहा. प्राध्यापक— समाज शास्त्र
शासकीय कला महाविद्यालय कटंगी
जिला— बालाघाट

भारत विश्व में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिये आवश्यकता है— युवाओं में कौशल विकास दक्षता की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की जनसंख्या लगभग 60.5 करोड़ है जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने की क्षमता रखती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार युवा में वह जोश व क्रियाशीलता होती है जो विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। वर्तमान में भारत को विश्व में शिखर पर पहुँचे देशों में अपना नाम शामिल करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले हुनरमंद लोगों की आवश्यकता है। भारत के युवाओं में अपार क्षमता है इस क्षमता को सही दिशा देने के लिये उन्हें प्रशिक्षित करने व उनके कौशल को निखारने की आवश्यकता है। श्रम ब्यूरो की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का केवल 2 प्रतिशत ही उपलब्ध है। अतः एक बड़ी संख्या में लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत में कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय को कौशल प्रशिक्षण के लिये एक निश्चित कार्ययोजना बनाने का दायित्व सौंपा गया है। जो देश की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराये। पहले से ही प्रारंभ 20 अलग-अलग मंत्रालयों के 60 विभिन्न कार्यक्रम अब कौशल विकास मंत्रालय के अधीन आ गये हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 159

भागीदारों के साथ 27 राज्यों और पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों के 356 जिलों में 1408 केन्द्रों के 82 लाख लोगों के प्रशिक्षण की क्षमता विकसित की है।

शिक्षा और कौशल विकास दोनों का ही मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। भारत में प्रचलित वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं को डिग्रीधारी बनाने में तो सक्षम है किन्तु उन्हें कौशल दक्ष बनाने में हम कहीं बहुत पीछे रह गये हैं। कौशल दक्षता का वैश्विक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ब्रिटेन में 70 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत व दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत कार्यबल कुशल कार्यबल है जबकि इनकी तुलना में भारत में वर्ष 2014 की श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 प्रतिशत प्रशिक्षित कार्यबल है। इस स्थिति की जिम्मेदार हमारी शिक्षा व्यवस्था ही है। शिक्षाविदों व सरकारों ने इस विषय पर विचार करने के बाद यह पाया कि केवल सिद्धांतों का-ज्ञान होना ही काफी नहीं है इसके लिये प्रायोगिक क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है यह क्षमता कौशल विकास प्रशिक्षण द्वारा संभव है। वर्तमान परिदृश्य में आज देश के विश्वविद्यालयों से अनेक ऐसे डिग्रीधारी युवा रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं जो प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन उनमें योग्य कौशल की कमी है। आज विश्व में भारत की बौद्धिक क्षमता का लोहा सभी मानते हैं लेकिन शिक्षा को कौशल विकास के साथ न जोड़ने के कारण आज हम कहीं बहुत पीछे रह गये हैं। अतः वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षा के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

कौशल विकास की अवधारणा व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें आई.टी.आई. के माध्यम से औद्योगिक कुशलता प्रदान किया जाता था। बाद में वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा "स्किल इण्डिया" के रूप में एक महत्वाकांक्षी मिशन प्रारंभ किया गया।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:- यह युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा युवाओं को बेहतर शिक्षण व व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 10वीं, 12वीं की पढाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने पर अधिक जोर दिया गया है। इसके लिये वर्तमान में छंजपवदंस अपसस कमअमसवचउमदज बवतचवतंजपवद के लगभग 2300 केन्द्रों पर 187 प्रशिक्षण साझेदारों के साथ मिलकर प्रशिक्षण का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-

लक्ष्य - 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना।

बजट - 120 करोड़ रुपये।

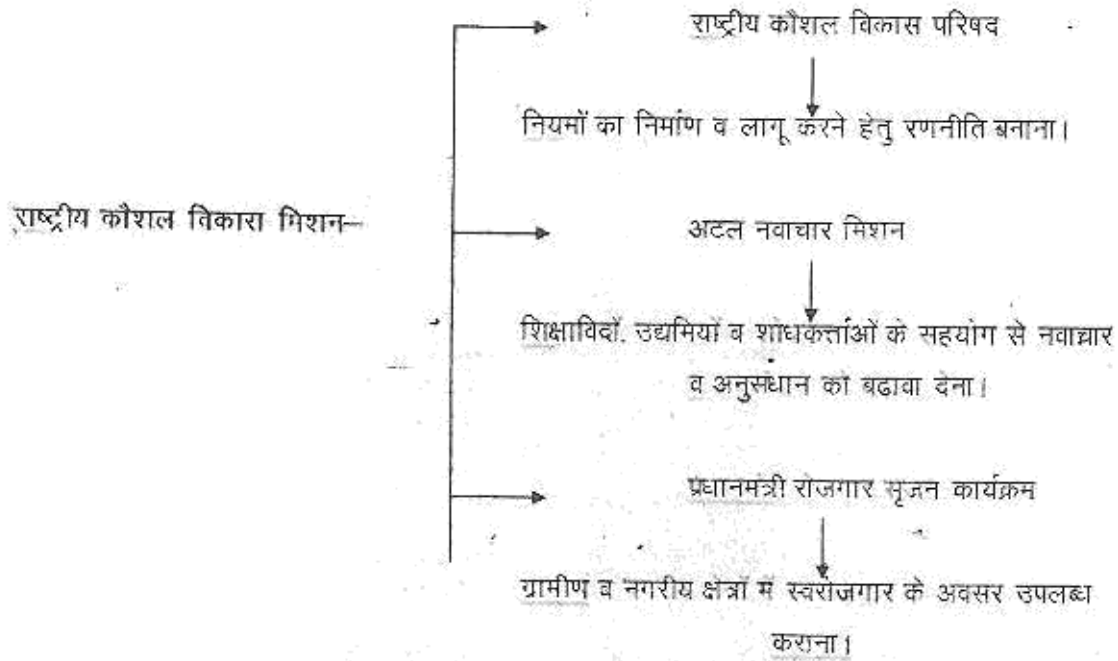
माध्यम- ऑनलाईन नागरिक पोर्टल, बायोमीट्रिक सिस्टम, वीडियो रिकार्डिंग।

बाधा - शिकायत निवारण केन्द्र।

प्रचार – स्थानीय स्तर पर कौशल मेलों का आयोजन।

राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यम विकास नीति:— “भेक. इन इन्डिया अभियान को पूरा करने के लिये कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने हेतु वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षित करना है। इस हेतु कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय के द्वारा “राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति” बनाई गई है, जिसमें वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:— प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कार्य कर



क्षेत्रों में निवास करती है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों के युवाओं के कौशल विकास व स्वरोजगार हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि— 1. इसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. अनिवार्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत व 33 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जायेगा।

3. लगभग 75 प्रतिशत प्रशिक्षितों के रोजगार की गारंटी होगी।

कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य:— “स्किल इण्डिया” देश के युवाओं को विभिन्न कार्यों में

प्रशिक्षित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:-

युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिये प्रेरित करना।

कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार योग्य बनाना।

देश को प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराना जिससे विभिन्न क्षेत्रों में देश की उन्नति हो।

अन्य देशों की माँग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि देश के युवाओं को अधिक संख्या में रोजगार मिल सके।

कौशल दक्षता से युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त हो।

युवाओं को बेहतर रोजगार मिलने से देश का सामाजिक आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

नये छोटे उद्यमी और रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना।

नवाचारों को प्रोत्साहित करना।

चुनौतियाँ:-

कौशल विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रचार प्रसार हो साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कौशल विकास प्रशिक्षकों को भी आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण से अपडेट होते रहना होगा। देश के वर्तमान परिदृश्य में कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। वर्तमान में रोजगार के अवसरों में 90 प्रतिशत व्यवसायिक योग्यता की आवश्यकता है जबकि इसके विपरीत 90 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं में केवल किताबी शिक्षा दी जाती है। विगत दशक में रोजगार के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुआ है। परंपरागत माँग से हटकर आई.टी., आई.टी. आधारित उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी, डिजायन, वित्त, बीमा, सत्कार, ट्रेवल, मीडिया के क्षेत्र में तेजी से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं किन्तु यदि हम बड़े नगरों के प्राइवेट संस्थानों को छोड़ दे तो नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत शिक्षा पाठ्यक्रम ही प्रचलित हैं। अतः उपरोक्त क्षेत्रों में बढ़ती हुई माँग को पूरा करना कठिन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु संस्थान की स्थापना व नये पाठ्यक्रम लागू कर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें देश की युवा जनसंख्या को देश के साथ-साथ विदेशों में भी अच्छे रोजगार प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को स्थापित करने के लिये हमें अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी होगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत के वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था को कौशल विकास के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसे निरंतर आगे बढ़ाना होगा। यदि हम वर्ष 2014 की श्रम

ब्यूरो की रिपोर्ट को आधार बनाये तो भारत में आवश्यक कुशल कार्यबल का केवल 2 प्रतिशत ही प्रशिक्षित कार्यबल प्राप्त होता है। यह स्थिति तब है जबकि देश में वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लगभग 31 लाख लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निश्चित ही इसके लिये हमें बड़े स्तर पर दृढ़इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। देश के वर्तमान परिदृश्य में कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:-

सबसे बड़ी चुनौती एक बड़ी जनसंख्या को प्रशिक्षित करना।

बड़ी जनसंख्या को प्रशिक्षित करने हेतु एक बड़ी संख्या में कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता। प्रशिक्षण हेतु तकनीकी संसाधन की अनुपलब्धता।

कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिये युवाओं को प्रोत्साहित करने की निश्चित योजना का अभाव।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो व्यक्ति को डिग्री प्राप्त करने के लिये वो प्रोत्साहित करती है किन्तु कौशल विकास के लिये नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था।

ग्रामीण जनसंख्या में शिक्षा की स्थिति।

युवाओं को उनकी योग्यता व रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें देश की युवा जनसंख्या को देश के साथ-साथ विदेशों में भी अच्छे रोजगार प्राप्त हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वंय को स्थापित करने के लिये हमें अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी होगी।

आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिये अलग-अलग क्षेत्रों के लिये पाठ्यक्रम में ऐसे मॉडल बनाने की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र विशेष में दक्षता प्राप्त कर ले।

भारतीय शिक्षा पद्धति को पुस्तकीय ज्ञान से बाहर लाने की आवश्यकता है।

भारत में कौशल विकास का तात्पर्य है आई.टी.आई. जहाँ ऐसे पाठ्यक्रम प्रचलित हैं जो चलन से बाहर हैं और जो चल भी रहे हैं तो आई.टी.आई का चयन अंतिम पायदान पर होता है जब विद्यार्थी के सामने कोई विकल्प नहीं बचता।

भारत के वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा को व्यवसायिक दक्षता यानि की कौशल विकास से जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। साथ ही इसमें सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन निजी क्षेत्रों को मिलकर कार्य योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करना होगा। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि युवाओं को इस तरह का

कौशल प्रशिक्षण दिया जाये जो वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ बदलते परिदृश्य में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भी हो। वर्ष 2015 के बजट में प्रत्येक पाँच किलोमीटर पर एक उच्च विद्यालय से लेकर उच्च तकनीकी संस्थान के साथ-साथ कौशल विकास संस्थान खोलने की बात कही गई है। आज हमारे पास विचार करने का समय नहीं है बल्कि यह निर्णय लेने का समय है कि शिक्षा को कौशल विकास के साथ इस तरह समायोजित कर दिया जाये कि युवा वर्ग रोजगार के लिये यहाँ वहाँ न भटके बल्कि स्वयं दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हो।

संदर्भ :-

कुरुक्षेत्र - सितंबर 2016, मार्च 2014

जून 2015, अक्टूबर 2014

मार्च 2015, अक्टूबर 2015

अप्रैल 2015

योजना - सितंबर 2013

मार्च 2015

अक्टूबर 2015

दिसंबर 2015

उच्च शिक्षा में परिवर्तन, चुनौतियां एवं उपलब्धियां

डॉ. (श्रीमती) अमोल मांजरेकर

प्राध्यापक – अर्थशास्त्र

शा. कन्या महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.)

वर्तमान समय निरंतर समृद्धि एवं विकास का है। आज सम्पूर्ण विश्व आधुनिक तकनीक एवं इन्टरनेट से जुड़े होन के कारण हर क्षेत्र में प्रतिफल नई गतिविधियों से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। समग्र विकास की आधारशिला या नींव की दिशा में विचार करने पर परिलक्षित होता है कि उत्कृष्ट शिक्षा एवं संस्कार ही इसके प्राथमिक सोपान है जिनको आधार बनाकर सफलता के अपने ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न सोपानों में उच्च शिक्षा विद्यार्थी के व्यक्तित्व को आकार देने और उसे साकार करने में अपना योगदान देती है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी महत्ता को हम अपने वास्तविक जीवन में कितना उतार पाने में सफल होते हैं। एक विद्यार्थी को अपने समग्र जीवन में स्वयं को समर्थ एवं योग्य बनाने हेतु उच्च शिक्षा प्रवेश द्वार है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे गुणवत्ता परक बनाया जाए।

गुणवत्ता किसी भी योजना या क्रियान्वयन के तरीकों को थोपने से नहीं आती, बल्कि नैतिक मूल्यों की स्थापना, उनकी रक्षा एवं सतत प्रयत्नों से प्राप्त होती है। शासन का उद्देश्य भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विकसित करने के लिए अपेक्षित वातावरण सुलभ कराने का है। शिक्षा के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए यदि आधुनिक शिक्षा पर विचार किया जाए तो शिक्षा प्रणाली को अद्यतन बनाने हेतु गुणवत्ता को बढ़ाना या गुणवत्ता परक बनाना आज की तीव्रतम आवश्यकता है इस हेतु इसे विभिन्न आयामों की कसौटी पर खरा उत्तरना होगा। शासन द्वारा इस हेतु एक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की गई है जो महाविद्यालयों में एक निश्चित समय के उपरांत (5 वर्ष) कुछ पहलुओं

के अन्तर्गत उनका मूल्यांकन करती है। विद्यार्थियों हेतु सुलभ रोजगार की प्राप्ति के लिये स्वद्वितीय पाठ्यक्रम महाविद्यालयों द्वारा संचालित किये जाते हैं। अध्ययन और अध्यापन के तरीकों में नवाचार अपनाए जा रहे हैं। म.प्र. में इसके अन्तर्गत सेमेस्टर पाठ्यक्रम लागू किया गया है इसमें सतत समग्र मूल्यांकन के सी.सी.ई द्वारा विद्यार्थियों के अध्ययन का मूल्यांकन किया जाता है। सत्र में दो बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती है। अध्यापन प्रश्नोत्तर, संवाद पद्धति, ग्रंथालय में जाकर अध्ययन में मदद, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना आदि के माध्यम से सम्पन्न किये जाते हैं।

प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को रचनात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरणा देने हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन, सहभागिता, आलेख प्रस्तुत करना, शोध पत्र देना जैसे कार्य किए जाते हैं। पत्रिकाओं में भी शोध पत्र भेजे जाते हैं जो कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होती है।

अकादमिक पक्ष के साथ-साथ महाविद्यालय अधोसंरचनात्मक स्तर से भी समृद्ध हो अधोसंरचना में महाविद्यालय के भवन, पुस्तकालय, वाचनालय, क्लॉस रूम, खेल के मैदान, फर्नीचर आदि का आवश्यकतानुसार सुलभ होना अनिवार्य है। उनका समुचित उपयोग एवं देखरेख आवश्यक है।

विद्यार्थियों में समग्र विकास हेतु पाठ्येत्तर गतिविधियां, उनका समुचित संचालन होना भी आवश्यक है। महाविद्यालय में ये कार्य वार्षिकोत्सव, युवा उत्सव, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रास, क्रीड़ा गतिविधियां, विभिन्न साप्ताहिक कार्यक्रम, पखवाड़े, महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय दिवस, कार्यशाला आदि के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रीड़ा गतिविधियों में जिला स्तर, संभाग स्तर, विश्वविद्यालय स्तर एवं राष्ट्रीय पर सहभागिता विद्यार्थी द्वारा किये जाने पर रोजगार प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं।

महाविद्यालय का प्रबंधन और प्रशासन के तौर-तरीके शासन के नियमानुसार, स्पष्ट सरल, आसान एवं पारदर्शी हो इस बात का ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास हो इस हेतु विद्यार्थियों को मंच पर लाकर व्याख्यान देने हेतु प्रेरित किया जाता है। पूर्व विद्यार्थियों से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो इसलिए पूर्व छात्र संगठन का गठन किया जाकर पूर्व छात्रों को गरिमायुक्त वातावरण में आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान छात्रों से रूबरू होकर अपने अनुभव वर्तमान छात्रों में साथ साझा करने में पूर्व छात्र स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नवाचारी प्रयोगों में विद्यार्थियों से कुछ नये विचार असेम्बली में बुलवाए जाते हैं। एक प्रश्न पुस्तकालय में लिखवाया जाकर उन्हें दूसरे दिन उसका उत्तर देने हेतु कहा जाता है। इस हेतु उन्हें पुरुस्कृत भी किया जाता है।

बदलती व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हमारी नैतिकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण व व्यक्तित्व-निर्माण केंद्रित शिक्षा-पद्धति

कहाँ तक अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ है— विचारणीय प्रश्न है। निस्संदेह हम मैकाले की शिक्षा-पद्धति को पानी पी-पीकर कोसने से बाज नहीं आते, पर आज तक मैकाले की भूतात्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसके लिए मैकाले कहीं से भी जिम्मेदार नजर नहीं आते। भूमंडलीकरण के इस दौर में हम अपनी ही पहचान खोते जा रहे हैं। पूरे विश्व में जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसके तीन घटक हैं— छात्र, अध्यापक और अभिभावक। इन तीनों के समन्वय के बगैर शैक्षणिक त्रिभुज के निर्माण की परिकल्पना ही बेमानी है। विद्यालयी पढ़ाई करने वाले नौ छात्रों में से एक ही कॉलेज पहुँच पाता है। उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण कराने वालों का अनुपात हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम 11 : है, जबकि अमेरिका में यह 83 प्रतिशत है। इस अनुपात को 15 प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत को 2,26,410 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा, जबकि 11वीं योजना में इसके लिए केवल 77,933 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया।

हमारे यहाँ चारों तरफ अनास्था का माहौल पनप रहा है। गुरु-शिष्य संबंध का घनत्व घट रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ तो जरूर, पर आज कुलपति का दायित्व संभाल रहा व्यक्ति भी अपने पद की गरिमा के साथ न्याय नहीं करता। कुछ लोग जेल जा चुके हैं और कुछ जाने की राह पर हैं। अगर स्थिति यही रही, तो विश्वविद्यालय जैसी स्वायत्त संस्था की विश्वसनीयता संदेहास्पद होती चली जायेगी। आज शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का जितना प्रतिशत खर्च होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बकौल भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव, अशोक ठाकुर, "शोध पर 0.8 : खर्च हो रहा है, जबकि कम-से-कम 2 प्रतिशत खर्च होना चाहिए। रक्षा और अन्य मंत्रालयों का बजट लम्बा-चौड़ा होता है, पर शिक्षा की अनदेखी होती है। समय पर प्राध्यापकों को वेतन नहीं मिलता, फलतः हड़ताली संस्कृति विकसित होती चली जा रही है, जिसका खामियाजा अन्ततः छात्रों को भुगतना पड़ता है"। शिक्षा मंत्रालय की जगह भारत सरकार ने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में भी इसे 'शिक्षा और कौशल मंत्रालय' तथा ऑस्ट्रेलिया में 'शिक्षा, रोजगार व कार्यस्थल संबंध मंत्रालय' कहा जाता है। उच्च शिक्षा पर बहस तब बेमतलब लगने लगती है, जब यह तथ्य जेहन में उभरता है कि तीन साल पहले बिहार के विश्वविद्यालयों में एक ही जाति के छह कुलपति नियुक्त थे और इसके पीछे की कहानी सबको मालूम है। हर सियासतवां अपने इलाके के वि.वि. में अपनी ही जाति का कुलपति नियुक्त करवाने के लिए पैरवी करता है। राज्यपाल जैसे वैधानिक व जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी की इतनी किरकिरी पहले कभी नहीं हुई थी, जिनसे विधान पार्षद कुलपति पद की कधीमत पूछकर उनके कुकृत्यों की विधानमंडल के संयुक्त सत्र में बखिया उधेड़ी हो। कुछ साल पहले पांडिचेरी के शिक्षा

मंत्री के स्थान पर कोई अन्य विद्यार्थी उनके लिए माध्यमिक परीक्षा दे रहा था । ऐसे में उच्च शिक्षा में सुधार की संभावना को आघात लगता है ।

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कोठारी आयोग, प्रोफेसर यशपाल कमिटी आदि का गठन हुआ, रिपोर्टें भी आयीं । 1986 ई. में रोजगारोन्मुखी नयी शिक्षा नीति भी लायी गयी, पर आज भी हम एक अदद मूल्यपरक शिक्षा-नीति की बाट जोह रहे हैं । नैसकॉम और मैकिन्से के ताजा शोध के मुताबिक मानविकी में 10 में एक और अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त 4 में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं । राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (नैक) का शोध बताता है कि इस देश के 90 फीसदी कॉलेजों एवं 70 : विश्वविद्यालयों का स्तर बेहद कमजोर है । आजादी के पहले 50 सालों में 44 निजी संस्थानों को डीम्ड वि.वि. का दर्जा मिला । पिछले 16 वर्षों में 69 और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गयी । शिक्षा के वैश्वीकरण के इस दौर में महँगे कोचिंग संस्थान, किताबों की बढ़ती कीमत, डीम्ड वि.वि. और छात्रों में सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की एक आम अवधारणा का पनपना आज की तारीख की अहम उच्च शैक्षिक चुनौतियाँ हैं । उर्दू कविता के एलेक्जेंडर पोप कहे जाने वाले अकबर इलाहाबादी ने इस स्थिति को भाँपते हुए कहा था

अस्तु, हमें गुणात्मक शिक्षा को अपनाना होगा, जिसमें नैतिकता का पुट हो । हमारे यहाँ तो विद्या खुद में ही एक अर्जन है, उसे अलग से भुनाने की जरूरत नहीं है । इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमें 'स्व' से अलग कर दिया है, खुद से संवाद की संभावना का लोप हो गया है और बाजार-निर्देशित-नियंत्रित-केंद्रित व्यवस्था ने शिक्षा को सबसे ज्यादा लपेटा है । इस शिक्षा-पद्धति का जिस्म तो बुलंद है, पर रूह नासाज हो चली है । इस रूग्णात्मा की तीमारदारी के ठोस हल जल्द ढूँढने होंगे । युवा पीढ़ी के अंदर की बेचौनी व छटपटाहट को समझते-परखते हुए उसे भटकाव से रोकना होगा । मस्तिष्क, हृदय और हाथ के सुंदर समन्वय से मुकम्मल शिखरयत के निर्माण की प्रक्रिया का द्वार खोलना होगा । अच्छे कॉलेजों, जैसे- एस.आर.सी.सी. में नामांकन हेतु सौ फीसदी तक कट आफ चले जाने से छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए मौजूदा 300 वि.वि. नाकाफी हैं । स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले महज 15: छात्र वि.वि. पहुँच सकें, इसके लिए 1500 नये वि.वि. खोलने होंगे ।

डीयू जैसे प्रतिष्ठित ज्ञान-केंद्र में, जहाँ पूरे देश की प्रतिभा आकर केंद्रित होती है, उसकी अपनी भी कोई मौलिक समझ होती है, खास अभिरुचि होती है य इन तथ्यों से सरोकार न रखते हुए फाउण्डेशन कोर्स के नाम पर उनका वक्त व स्पिरिट जाया कराया जा रहा है । आखिर डीयू प्रशासन की ऐसी कौन-सी बाध्यता थी, एक साल में ऐसा कौन-सा पहाड़ टूटा जा रहा था कि बिना किसी

गंभीर मानसमंथन और सार्थक बौद्धिक विमर्श के हड़बड़ी में इस अनपेक्षित एवं गैरजरूरी बदलाव से बच्चों का साक्षात्कार कराया गया ? ध्यातव्य है कि सारे बच्चे आगे चलकर एम.बी.ए. करने के उद्देश्य से डीयू नहीं आते, न ही सबको विदेश जाकर पढ़ाई करनी होती है कि उन पर स्नातक के दौरान एक अतिरिक्त वर्ष का बोझ डाला जाय । पाठ्यक्रम में परिवर्तन तो तब किया जाता है, जब उसमें कोई गुणात्मक दिक्कत हो । पिछले पाठ्यक्रम में तो ऐसी कोई गड़बड़ी थी ही नहीं । सब कुछ भला-भला सा सामान्य चल रहा था । यहाँ भी बड़ी सूक्ष्मता से बाजारवाद का डंडा चला । नामांकन लेने के लिए सभी छात्रों को लैपटॉप का सब्जबाग दिखाया गया, ताकि इस लालच में विद्रोह का स्वर थोड़ा धीमा हो जाय । पर पिछले एक साल से अनवरत इस चतुर्धर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की बड़ी तीखी भर्तस्ना होती रही । प्रतिबद्ध छात्र व सुधी शिक्षक-समुदाय के निरंतर जुझारूपन व भगीरथ प्रयास तथा यूजीसी के सार्थक हस्तक्षेप के आगे मजबूर होकर आखिरकार कुलपति को अपने फैसले वापस लेने पड़े, जिससे दिल्ली वि.वि. की चिरस्थापित मर्यादा व शैक्षिक रौनक एक बार फिर लौटने की आस जगी है । पर, उन बच्चों का क्या, जिनका एक साल इस अवांछित पाठ्यक्रम की भेंट चढ़ गया ।

अब जबकि फिर से त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने की बात स्वीकार कर ली गयी है, तो ऐसे में अभियंत्रण के वैसे बच्चे परेशान हैं, जिन्हें बी.एस.सी. की नहीं, बल्कि चार साला बी.टेक. की डिग्री चाहिए । इस बीच काफी मेलोड्रामा हुआ । पहले तो खग्वर आयी कि कुलपति ने यूजीसी के हस्तक्षेप को वि.वि. की स्वायत्ता पर चोट बताते हुए इस्तीफा दे दिया है । फिर नाटकीय मोड़ तब आया, जब पता चला कि कुलपति के पक्षधर प्राध्यापक उन्हें मनाने में लगे हुए हैं । काफी समय तक कुलपति सामने आकर कुछ बोलने से परहेज करते रहे । फलतः असमंजस की स्थिति बनी हुई थी । हालाँकि दिल्ली वि.वि. शिक्षक संघ की अध्यक्षा प्रो. नंदिता नारायण ने स्पष्ट किया कि बी.टेक. के छात्रों का भविष्य अधर में लटकने नहीं दिया जायेगा । आलम तो ये हुआ कि इस सत्र के नामांकन की प्रक्रिया बहुत देर से आरंभ हो पायी । ऐसी उथल-पुथल पहले शायद ही कभी देखी गयी हो ।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. उच्च शिक्षा विभाग में गुणवत्ता प्रबंधन - उच्च शिक्षा विभाग
2. रचना - मई जून 2009 - म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
3. जयन्त जिज्ञासु - (भारतीय जनसंचार संस्थान, नयी दिल्ली से रेडिओ व टेलिविजन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि-पत्र)

विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

पापिया चतुर्वेदी

सहायक प्राध्यापक

शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा छग.

सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं की अखिर नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण है क्या ?

उद्देश्य : काला धन और जाली नोटों को खत्म करने के लिए विमुद्रीकरण लागू किया जाता है।

प्राचीन काल के आचार्य चाणक्य से लेकर आधुनिक काल के भीमराव अम्बेडकर तक ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था का एक मुख्य चरण बताया है जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नवजीवन की उत्पत्ति होती है

"जब किसी भी देश में कालेधन की एक सामानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा हद से अधिक बढ़ जाती है तब नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण की जाती है जिसके अन्तरगत मुद्रा को तुरंत प्रभाव से बंद कर, नई मुद्रा जारी की जाती है"

मोदी सरकार ने जब से नोटबंदी की घोषणा की है तबसे पुरे देश में अफरातफरी का माहौल है, वैसे इसमें कोई शक नहीं की किसी भी देश में नोटबंदी समय समय के अंतराल में की जाती रही है जिससे उस देश में कालेधन पर सबसे बड़ी चोट लगती है और कालेधन की समस्या से निजात मिलती है।

इस समय सम्पूर्ण विपक्ष जिस तरह से एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है इससे उनके अन्दर चल रही खलबली का पता चलता है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है की इस समय विपक्षी पार्टियों का अरबों रुपयों का कालाधन बेकार हो चुका है और उनका भविष्य भी दांव पर है तो यह देश में कुछ भी कर सकते है, यहाँ तक की दंगे, लूटमार, हड़ताल भी करवा सकते है हालांकि भारत की जनता इस मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ है और यही वजह है की विपक्षी दल अभी तक

अपनी किसी भी चाल में सफल नहीं हो पाए है।

वैसे तो पाठको कालेधन और नोतेबंदी के नफे-नुक्सान विपक्षी पार्टियों के शोर में दब गए हैं और मीडिया को भी जूझ पर लगी भीड़ के अलावा कुछ और भी नजर नहीं आ रहा लेकिन आज हम आपको नोटेबंदी अर्थात् विमुद्रीकरण के वह लाभ बताने जा रहे हैं जो आप सबको जरूर पता होने चाहिए।

कब-कब हुआ विमुद्रीकरण दो बार- पहली बार जनवरी 1978 में 1000, 5000 और 0000 का विमुद्रीकरण हुआ। दूसरी बार 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1000 के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की।

सिक्के जो बंद हुए 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे मूल्यवर्ग के सिक्के 30 जून, 2011 से संचलन से वापिस लिये गये, अतः वे वैध मुद्रा नहीं रहे।

विशेष भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में मुद्रा संबंधी कार्य संभालता है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर जारी किये जाने वाले विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के संबंध में निर्णय लेता है।

अन्य जानकारी वर्तमान में, भारत में 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी किये जा रहे हैं। 5 मूल्यवर्गों के नोटों का मुद्रण बंद किया गया है क्योंकि इनका सिक्काकरण हो चुका है। तथापि, पहले जारी किये गये ऐसे नोट अभी भी वैध हैं।

22 नवम्बर 2016 (IST)

विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को प्रचलित करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

भारतीय मुद्रा

भारत की अपनी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। नये प्रतीक चिह्न के आने से पहले रुपये को हिन्दी में दर्शाने के लिए रु और अंग्रेजी में टे का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक भारतीय रुपये को 100 पैसे में विभाजित किया गया है। सिक्कों का मूल्य 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे और 1, 2, 5 और 10 रुपये भी है। बैंकनोट 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 के मूल्य पर हैं। भारतीय करेंसी को भारतीय रुपया (INR) तथा सिक्कों को पैसे कहा

जाता है। एक रुपया 100 पैसे का होता है।

भारतीय रुपये का प्रतीक है— यह डिजाइन देवनागरी अक्षर र (ra) और लैटिन बड़ा अक्षर R के सदृश है जिसमें ऊपर दोहरी आड़ी रेखा है। भारतीय रुपया चिह्न (?) भारतीय रुपये (भारत की आधिकारिक मुद्रा) के लिये प्रयोग किया जाने वाला मुद्रा चिह्न है। यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था मूलतः यह नया चिह्न देवनागरी अक्षर 'र' पर आधारित है किन्तु यह रोमन के कैपिटल अक्षर R का बिना उर्ध्वाकार उण्डे का भी आभास देता है। अतः इस चिह्न को इन दोनों अक्षरों का मिश्रण माना जा सकता है। मूल रूप से तमिल भाषी इसके अभिकल्पक उदय के अनुसार जब वो इसका डिजाइन सोच रहे थे तो उन्हें लगा कि सिर्फ देवनागरी लिपि से संबंधित कोई चिह्न ही भारतीय भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। ऊपर की तरफ समान्तर रेखायें (उनके बीच में खाली जगह समेत) भारतीय झण्डे तिरंगे का आभास देती हैं।

भारतीय मुद्रा का निर्माण

प्रारंभ में छोटे राज्य थे जहां वस्तु विनिमय अर्थात् एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान-प्रदान संभव था। परंतु कालांतर में जब बड़े-बड़े राज्यों का निर्माण हुआ तो यह प्रणाली समाप्त होती गई और इस कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा को जन्म दिया गया। इतिहासकार के. वी. आर. आचंगर का मानना है कि प्राचीन भारत में मुद्राएं राजसत्ता के प्रतीक के रूप में ग्रहण की जाती थीं। परंतु प्रारंभ में किस व्यक्ति अथवा संस्था ने इन्हें जन्म दिया, यह ज्ञात नहीं है। अनुमान यह किया जाता है कि व्यापारी वर्ग ने आदान-प्रदान की सुविधा हेतु सर्वप्रथम सिक्के तैयार करवाए। संभवतः प्रारंभ में राज्य इसके प्रति उदासीन थे। परंतु परवर्ती युगों में इस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मुद्रा निर्माण पर पूर्णतः राज्य का अधिकार था। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में मुद्राओं का प्रचलन विदेशी प्रभाव का परिणाम है। वहीं कुछ इसे इसी धरती की उपज मानते हैं। विल्सन और प्रिंसेप जैसे विद्वानों का मानना है कि भारत भूमि पर सिक्कों का आविर्भाव यूनानी आक्रमण के पश्चात् हुआ। वहीं जॉन एलन उनकी इस अवधारणा को गलत बताते हुए कहते हैं कि प्रारंभिक भारतीय सिक्के जैसे 'कार्षापण' अथवा 'आहत' और यूनानी सिक्कों के मध्य कोई सम्पर्क नहीं था।

मुद्रा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें

सिक्का -

वर्तमान में भारत में, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्यवर्गों में सिक्के जारी किये जा रहे हैं। 50 पैसे तक के सिक्के "छोटे सिक्के" और 1 रुपये तथा उसके ऊपर के सिक्कों को

“रुपये सिक्के” कहते हैं। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे मूल्यवर्ग के सिक्के 30 जून 2011 से संचलन से वापिस ले लिये गये हैं, अतः वे वैध मुद्रा नहीं रहे।

दस पैसे, पाँच पैसे, पच्चीस पैसे और एक पैसे के भारतीय सिक्के (बांये सो दांये)

करेंसी-

वर्तमान में, भारत में 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी किये जा रहे हैं। क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा जारी किये जाते हैं, इसलिए इन्हें “बैंकनोट” कहा जाता है। 1, 2 और 5 मूल्यवर्गों के नोटों का मुद्रण बंद किया गया है क्योंकि इनका सिक्काकरण हो चुका है। तथापि, पहले जारी किये गये ऐसे नोट अभी भी संचलन में पाये जा सकते हैं और ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का विमुद्रीकरण

10000 रुपये के नोट विमुद्रीकरण सन् 1978 में हुआ

मुख्यतः अघोषित धन पर नियंत्रण रखने के प्रयोजन से, जनवरी 1946 में उस समय संचलन में मौजूद 1000 और 10000 के बैंकनोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। वर्ष 1954 में 1000, 5000 और 10000 के उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को फिर से जारी किया गया और भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में जनवरी 1978 में इन बैंकनोटों (1000, 5000 और 10000) को एक बार फिर विमुद्रीकृत किया गया। 8 नवंबर, 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कच्यम उठाते हुए 500 और 1000 के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की।

एक रुपया भारत सरकार की देयताओं में-

करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के अंतर्गत जारी एक रुपये के नोट भी विधि मान्य मुद्रा हैं और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के सभी प्रयोजनों हेतु रुपये सिक्के के रूप में माना गया है। क्योंकि सरकार द्वारा जारी रुपये सिक्के भारत सरकार की देयताओं में आते हैं, इसलिए सरकार द्वारा जारी एक रुपया भी भारत सरकार की देयता है।

मुद्रा प्रबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका निर्धारित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा संबंधी कार्य संभालता है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक की सलाह पर जारी किये जाने वाले विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के संबंध में निर्णय लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक सुरक्षा विशेषताओं सहित बैंकनोटों की रूपरेखा (डिजाइनिंग) तैयार करने में भी भारत सरकार के साथ समन्वय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकनोटों की मूल्यवर्ग-वार संभावित

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनकी मात्रा का आकलन करता है और तदनुसार, विभिन्न मुद्रण प्रेसों को अपना मांगपत्र प्रस्तुत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता के नोट प्रदान करना है। इसके लिए, संचलन से वापिस प्राप्त होने वाले बैंकनोटों की जाँच की जाती है और पुनरुजारी करने योग्य बैंकनोट फिर से संचलन में डाल दिये जाते हैं तथा गंदे और कटे-फटे बैंकनोटों को नष्ट कर दिया जाता है जिससे संचलन में बैंकनोटों की गुणवत्ता बनी रहे।

मुद्रा विमुद्रीकरण

5000 रुपये के नोट विमुद्रीकरण सन् 1978 में हुआ

मुद्रा विमुद्रीकरण के तहत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चलाती है। यानी पुरानी मुद्रा की वैधता नहीं रहती। वह अवैध हो जाती है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में काले धन पर काबू पाने के लिए यह कदम यानी विमुद्रीकरण उठाया जाता है। जब काला धन अर्थव्यवस्था के लिये खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिये विमुद्रीकरण अपनाया जाता है। जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

नकली नोट तथा काला धन बनाम विमुद्रीकरण—

देश में नकली नोट का सम्बन्ध 1991 से प्रारम्भ आर्थिक सुधार से माना जा रहा है। उदारवाद के बाद चार कम्यूनिस्ट पार्टी एवं काँग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चे की सरकार को सन 1996-97 में 3,35,900 करोड़ रुपये की नयी मुद्रा छपवाने की आवश्यकता पड़ी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने काले धन की समाप्ति के लिए स्वैच्छिक आय उजागर योजना (वीडीआईएस) शुरु की। वीडीआईएस में लगभग 33,000 करोड़ रुपये का काला धन सामने आया। आरबीआई के टकसाल की क्षमता 2,16,575 करोड़ रुपये की थी, जिससे विदेशों से 1,20,000 करोड़ रुपये के नोट छपवाने माँग हुई। भारतीय मुद्रा छापने वाली विदेशी कम्पनियों को स्पष्ट निर्देश था कि वे भारतीय नोट की प्लेट, स्याही, वाटरमार्क कागज भारत सरकार को सौंपेंगी। वैसे, इंग्लैण्ड की कम्पनी डेलारू देश-विदेशों की सरकारों के नोट छापती है।

500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण

8 नवंबर, 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 500 और 1000 के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की। यानी 9 नवंबर से कुछ तय जगहों—पेट्रोल पंप, अस्पताल, रेलवे स्टेशन इत्यादि को छोड़कर देश में कहीं भी 500 और 1000 के नोटों से लेन-देन पर रोक लग गई। इन जगहों पर भी इन नोटों के प्रयोग को तय समय सीमा (अब 24 नवंबर) तक ही इजाजत दी गई है। जिन लोगों के पास 500 और 1000 के नोट पड़े हैं वो उन्हें 30 दिसंबर

तक देश के किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं। सरकार ने पुराने नोटों की जगह 500 और 2000 के नए नोट जारी किए हैं जो लोगों को बैंकों और एटीएम के माध्यम से मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि लेन-देन के पूरी तरह सामान्य होने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। इस फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरबीआई के वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल का समर्थन हासिल है। उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को "बहुत साहसिक कदम" बताया है। हालांकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन विमुद्रीकरण को कालाधन बाहर लाने के लिए ज्यादा कारगर नहीं मानते हैं। कई अन्य विशेषज्ञों ने भी इस कदम पर सवाल उठाए हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के प्रोफेसर अभिरूप सरकार के अनुसार काला धन रखने वाले ज्यादातर लोग अपने पैसे विदेशी बैंकों में रखते हैं इसलिए देश में विमुद्रीकरण करने से ज्यादा बड़े मछलियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट बाजार में थे जिसमें से करीब 14.18 लाख रुपये 500 और 1000 के नोटों के रूप में थे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कुल देश में तब तक मौजूद कुल 9026 करोड़ नोटों में करीब 24 प्रतिशत नोट (करीब 2203 करोड़ रुपये) ही प्रचलन में थीं।

संदर्भ :

भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण रू एक बार फिर (हिन्दी) प्रवक्ता डॉट कॉम। अभिगमन तिथिरू 19 नवंबर, 2016।

जानिए क्या है विमुद्रीकरण, क्यों लेती हैं सरकारें इसका फैसला और अब तक भारत में कब-कब ऐसा हुआ है? (हिन्दी) जनसत्ता डॉट कॉम। अभिगमन तिथिरू 20 नवंबर, 2016।

नोट बंदी का भारतीय समाज पर प्रभाव

डॉ. नीलिमा चटर्जी

सहायक प्राध्यापक

समाजशास्त्र विभाग

शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

नोट बंदी के संदर्भ में सामाजिक प्रभाव की व्याख्या करने के पहले तीन बातों या तीन अवस्थाओं का जिक्र करना लाजिमी है। ये अवस्थाएँ हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज की। जिस दिन रात में यानी आठ नवम्बर की रात में उन्होंने हजार और पांच सौ के नोटों का चलन बंद किये जाने की घोषणा की उस दिन वे काफी प्रतिबद्ध और साहसी दिख रहे थे। उन्होंने उत्साह और आत्मविश्वास से भर कर माइक्रोफोन की डंडी पकड़ ली थी। दूसरा दृश्य गोवा में सोमवार की शाम उनके भाषण का था। उनकी आंखें भर आयीं थीं और गला रुध गया था। वे अपने परिवार को त्यागने का हवाला दे रहे थे। ये इमोशनल क्षण उनके आत्मविश्वास के हतोत्साहित होने का प्रत्यक्ष क्षण था। तीसरा दृश्य था सोमवार की रात कैबिनेट मीटिंग का। जहाँ कैबिनेट ने लोगों की पीड़ा का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मौन रहे। वित्तमंत्री अरुण जेटली बार बार कह रहे हैं कि दो तीन हफ्तों में सारी मुश्किलें खत्म हो जायेगी। लेकिन सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि यह झूठा आश्वासन है और इस आश्वासन की हकीकत समझ कर ही मोदी जी हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक हजार और पांच सौ के नोट अर्थ व्यवस्था में 86 प्रतिशत थे। यानी सौ, पचास, दस और पांच के नोट महज 14 प्रतिशत हैं। अब आप ही कहिये कि 86 प्रतिशत की अतिरिक्त कमी 14 प्रतिशत से कैसे खत्म होगी? जबकि उस चौदह प्रतिशत का चलन पहले से था। इसका साफ अर्थ है कि यह चौदह प्रतिशत अपना काम करते हुये बाकी के 86 प्रतिशत की कमी भी पूरी करेंगे। क्या यह संभव है? अब जरा इसका समाज वैज्ञानिक पक्ष देखें। कोलकाता के स्लम में या बंद हो गयी जूट मिलों

के लाइनों में या फुटपाथों पर बसर करने वाले लोगों में या छोटे छोटे रोजगार करने जैसे सब्जी बेचने वाले या हाथ रिक्शा खींचने वाले लोगों में आधे से ज्यादा के बैंक खाते नहीं हैं और वे क्या करेंगे यह बात समझ में नहीं आती। यही नहीं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कुल लोगों में से तीन चौथाई लोग फाइनेंशियल सिरस्टम से नहीं जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जान बूझ कर ऐसा किया है बल्कि उनके पास इतना बचता ही नहीं कि वे इससे जुड़ पायेंगे। औरतों की छिपायी गयी रकम को छोड़ भी दें तब भी इसके तीन समाजवैज्ञानिक पहलू हैं। इस महान घटना की फितरत आर्थिक है और मध्यवर्ग जहां खड़ा होकर अपनी नैतिकता की दुहाई देता है यह फितरत उस आधार पर आघात करती है। फिजूलखर्ची के इल्जाम, सार्वजनिक जीवन से अलग रहने के आरोप और अनुपाती न्याय के आदर्श के मुकाबले यह आर्थिक उद्धत राष्ट्रवाद (इकोनॉमिक जिंगोइज्म) तना हुआ है। आर्थिक तर्क तो यह कहते हैं कि जिस देश में आयकर छापों में कुल अघोषित सम्पति का केवल 6 प्रतिशत ही पाया जा सका और कालाधन उपार्जन की प्रक्रिया चालू है वहां इस तरह के महान कदम कुछ ज्यादा कर पायेंगे इसमें संदेह है। भारत में मध्यवर्ग का आविर्भाव एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। आज इसका एक नया स्वरूप बनता दिख रहा है। इसके तीन पहलू तो स्पष्ट हैं। इनमें पहला है कि समाज में गरीब विरोधी भाव उत्पन्न हो रहा है। राजनीतिक आदर्श बाजारवाद का टहलुआ होता जा रहा है और जनता उपभोक्ता बनती जा रही है। ऐसे समीकरण में गरीबों और उनके दैनिक जीवन के प्रति एक अलगाव बोध सा बढ़ता दिख रहा है। इनपर आरोप है कि ये बिजली चुराते हैं, शहरी जमीन पर कब्जा जमा कर झोपड़ियां बनाते हैं और कारपोरेट क्षेत्र को अपने कारखाने लगाने या खान खोदने के जमीन देने से इकार करते हैं। ये घटिया लोग हैं तथा इनकी पसलियों से निकला एक नैतिक मध्यवर्ग अपनी मेधा तथा कठोर परिश्रम के बल पर इस समाज में जगह बनाता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हर बात का उत्तर तकनीक या टेक्नोलॉजी में देखा जा रहा है। शहरी समस्याओं को केवल स्मार्ट सिटी, कम्प्यूटर के जरिये ही हल किया जा सकता है। तकनीक स्वच्छता है और नैतिकता स्वच्छता में है। नोटों पर लिखा 'स्वच्छ भारत की ओर' इसी तकनीक की ओर संकेत है। तीसरा बदलाव जो दिख रहा है वह है कि हिंसा की भाषा बदल रही है। राष्ट्रीय भावनात्मकता के गिलफ में लिपट कर वित्तव्यवस्था को युद्ध और मुद्रा को सैनिकीकरण के चश्मे से देखा और दिखाया जा रहा है। हिंसा की भाषा में राष्ट्रवाद का प्रक्षेपण नैतिक प्रक्रिया बनती जा रही है। ऐसा लगता है कि पहले हम भारतीय कायर थे और अब जहंसा के सामान्यीकरण में नये लोग बन गये हैं। कालाधन एक गंभीर प्रक्रिया का लक्षण है और यह जो नयी व्यवस्था हुई है वह सार्वजनिक हित के सिकुड़ते दायरे से नैतिकता को परिभाषित करने के गंभीर और आंतरिक गंदगी का बिम्ब है। यह व्यवस्था केवल पैसे से नहीं जुड़ी है।

आज बंद हो गयी जूट मिलों से बेकार होने पर के सड़क पर सोने वाले लोग और घोड़ों की तरह जुत कर रिवशा खींचने वालों की पीड़ा से बाहर का राष्ट्रीय अंतर आज नैतिकता का संदर्भ है। यह संदर्भ मानसिक रुग्णता की निशानी है और यह रुग्णता आज सामूहिक तौर पर देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो इसका विरोध किया वह बिल्कुल सही है। सियासत में आज एक आध्मी तो ऐसा है जो नैतिक अपराधबोध से ग्रस्त गरीब (अनैतिक) लोगों के पक्ष में खड़ा है।

8 नवम्बर 2016 को राष्ट्र के नाम सन्देश में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा ५०० और १००० के नोटों की कानूनी वैधता समाप्त कर दी गयी, मोदी जी द्वारा नोट बंद करने के दो मुख्या कारण हैं, पहले देश में काले धन पर प्रहार और दूसरा कारण सीमा पर से होने वाली नकली नोटों की आपूर्ति, जिसके सहारे पाकिस्तान भारत में अपने आतंकी नेटवर्क को चलता है।

भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किये गए संबोधन के द्वारा की गयी। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा में 8 नवम्बर की आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था।

यह योजना छह महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग थे— मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। योजना को लागू करने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हुई थी।

इतिहास और सांख्यिकी

इससे पहले, इसी तरह के उपायों को भारत की स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था। जनवरी 1946 में, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को वापस ले लिया गया था और 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नए नोट 1954 में पुनः शुरू किया गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था ताकि जालसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके।

28 अक्टूबर 2016 को भारत में 17.77 लाख करोड़ (यूएस+260 बिलियन) मुद्रा सर्कुलेशन में थी। मूल्य के आधार पर 31 मार्च 2016 को आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार, सर्कुलेशन में नोटों की कुल कीमत 16.42 लाख करोड़ (यूएस+240 बिलियन) है, जिसमें से 86: (अर्थात 14.18 लाख करोड़ (यूएस+210 बिलियन) 500 और 1000 के नोट हैं। वॉल्यूम के आधार पर रिपोर्ट अनुसार, 9,026.

6 करोड़ नोटों में से 24 प्रतिशत (अर्थात् 2,203 करोड़) बैंक नोट सर्कुलेशन में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक घोषणा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सभी मूल्यवर्ग के नोटों की आपूर्ति में 2011 और 2016 और बीच में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 500 और 1000 पैसों में इस अवधि में क्रमशः 76 और 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस जाली नकदी को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप नोटों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था।

अतीत में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नोटबंदी का जोरदार विरोध किया था। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने 2014 में कहा था कि आम औरत और आदमी, जो लोग अनपढ़ हैं और बैंकिंग सुविधाओं तक जिनकी पहुँच नहीं है ऐसे लोग इस तरह के उपायों से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मुख्य रूप से कुछ समय के अंतराल में स्वयं जनता 2000 के नोट को चलन से बाहर कर देगी, क्योंकि जहाँ कम मूल्य की वस्तु खरीदनी हो तब दुकानदार आपसे 2000 के नोट नहीं लेगा। परिणाम स्वरूप 2000 के नोट की या तो जमाखोरी होगी अथवा 'काले धन' का ही सृजन करेंगे। सरकार को इस विषय पर प्रारंभिक समय से सचेत रहने की आवश्यकता है।

विभिन्न अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। काला धन विभिन्न रूपों में मौजूद है, जैसे कि बेनामी संपत्ति, सोना और आभूषण, शेयर, हवाला और नगदी। अपुष्ट अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का काला धन नगद में रूप में मौजूद है। यद्यपि वास्तविक स्थिति तो समस्त पुराने नोटों के बैंकिंग प्रणाली में आने के बाद ही ज्ञात होगी, प्रधान मंत्री का एक लक्ष्य इसी काले धन पर प्रहार है। ये भी सत्य है कि काले धन के नगद रूप पर ही प्रहार करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, इसके अन्य रूपों पर भी प्रहार करना होगा।

नगद के रूप में काला धन आम जनता के पास नहीं होता है, भारत में चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं और जनता मानती है कि चुनाव में काल धन बहुतायत में खर्च होता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो जनता मानती है कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के पास काला धन होता है, प्रधान मंत्री द्वारा बड़े नोटों को प्रक्षालन से बाहर करने पर आम जनता की खुशी का एक कारण राजनीतिक काले धन की समाप्ति की उम्मीद भी है।

काल धन का एक भंडार रियल एस्टेट का काम करने वाले भी हैं, जिस कारण एक जरूरतमंद बेघर के लिए जमीन या फ्लैट की कीमत आसमान तक पहुँच जाती है, आम नागरिक इन सबसे त्रस्त रहता है, जो कि भविष्य में जमीन या फ्लैट की कीमत कम होने की आशा कर रहा है।

टैक्स चोरी करने वाले छोट और बड़े कारोबारी और पेशेवर भी काले धन का संग्रहण करते हैं. इसके अतिरिक्त शक्तिशाली पदों पर आसीन अधिकारी भ्रष्ट आचरण जैसे रिश्वत के रूप में भी काला धन जमा करते हैं.

काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था समाप्त होने के बहुत से लाभ हैं. पहला लाभ समस्त नगदी बैंकिंग प्रणाली में आ जायेगी इससे बैंको की जमा की लागत घटेगी और जनता को ऋण भी कम रेट पर उपलब्ध होगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी. रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और क्योंकि व्यवसायी को कम रेट पर ऋण मिलेगा तो देर सबीर उसकी लागत कम होने का लाभ भी जनता को मिलेगा.

दूसरा लाभ ये होगा कि टैक्स चोरी रुकेगी और सरकार के खजाने में ज्यादा राजस्व आएगा. इससे सरकार देश में आधारभूत ढांचा विकसित कर सकेगी. किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है की आवागमन के साधन जैसे सड़को का जाल, रेल नेटवर्क का विस्तार और हवाई सुविधाओं में वृद्धि, विद्युत उत्पादन और वितरण में सुधर, दूर संचार सेवाओं का विस्तार, इन्टरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार आदि में वृद्धि और विस्तार हो. इन सब सुविधाओं के होने से बाजार की गतिविधियां भी प्रभावित होंगी.

तीसरा लाभ ये होगा कि सरकार के पास नागरिक सुविधाओं जैसे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जैसी सेवाओं के विस्तार के लिए अधिक धन होगा. जिसका सीधा लाभ देश के आम नागरिकों को मिलेगा.

नोट बंदी से एक लाभ यह भी होगा की हमारा समाज और अर्थव्यवस्था नगदी विहीन होगी. यद्यपि इसमें समय लगेगा. क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षित और अर्ध शिक्षित जनसँख्या काफी है.

अब हम दूसरी मुख्य समस्या नकली मुद्रा की तरफ आते हैं. भारत में लगभग 99 यलाख करोड़ की मुद्रा प्रचलन में है. इसमें 500 और 9000 की मुद्रा का मूल्य लगभग 95 लाख करोड़ है. अपुष्ट खबरों के अनुसार हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगभग 92 लाख करोड़ से ज्यादा मूल्य की नकली मुद्रा छाप चुका है, जो की नेपाल और बंगला देश के रास्ते भारत में आनी थी. प्रधान मंत्री द्वारा बड़े नोटों को प्रचलन से बाहर करने के कारण पाकिस्तान द्वारा छपी गयी मुद्रा व्यर्थ हो गयी है. इसका परिणाम हम कश्मीर में देख सकते हैं. धन की कमी के कारण कश्मीर में आतंकवाद थम गया है, क्योंकि आतंकवादी और उनके आकाओ के पास उपद्रवियों को देने के लिए धन नहीं है.

पिछले सत्तर सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की ये पहले बार सफाई हो रही है. सन 1978 में तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा की गयी नोट बंदी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती. 1978 में जो नोट प्रचलन से बाहर किये गए थे, जैसे 1000, 5000 और 10,000, वो नोट आम जनता के पास

नहीं होते थे, और उस समय जाली नोट भी प्रचलन में नहीं थे. इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले बार किसी सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सफाई अभियान चलाया जा रहा है.

यदि हम केवल उपर्युक्त लाभों को ही देखें तो कह सकते हैं की नोट बंदी एक आवश्यक कदम है. जिसका दीर्घ काल में हमारे समाज और विशेषकर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होगा.

केंद्र सरकार के इस निर्णय से सबसे बड़ा असर फिलहाल आम लोगों पर पड़ा है। लोगों ने घर में रख रखे जमा रकम को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैंकों के बाहर लंबी कतार में वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे में देश में मुद्रा की तरलता पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश जमा हो रहा है। असंगठित क्षेत्रों मसलन लघु उद्योग में हलचल मच गई है। बड़ी करेसी बंद हो जाने से काम प्रभावित हो रहा है। हालांकि, कैश मुहैया होने के बाद इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। धीरे-धीरे इसका असर भी सकारात्मक तौर पर दिखने लगेगा। हालांकि, दिहाड़ी मजदूरों की दिनचर्या पूरी तरह से चरमरा गई है। इन हालातों में यह कहना उचित है कि बजट सत्र के इस क्वार्टर में इसका नकारात्मक असर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर देखने को मिलेगा। मगर इस क्वार्टर के बाद लघु उद्योगों में आने वाली तेजी से जीडीपी में अगला तिमाही उछाल लेगा, जिससे हाल में दिखने वाली नकारात्मकता लोग भूल जाएंगे।

शेयर मार्केट पर हमेशा ही बाजार की अस्थिरता का व्यापक असर देखने को मिलता है। हालांकि, इस बीच अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने का भी व्यापक असर शेयर बाजार पर पड़ा है। मगर इस बीच भारत सरकार के फैसले से शेयर पर बाजार पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण किया जाए तो देखने को मिल रहा है कि हर वह सेक्टर जो लघु उद्योग यानी असंगठित अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, इस गिरावट को लोग कुछ दिनों बाद सामान्य होने वाली परिस्थितियों में भूल जाएंगे। इस बीच ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े शेयर में लाभ दर्ज किया जा रहा है क्योंकि लोगों ने मुद्रा की तरलता कम हो जाने के बाद से ई-वॉयलेट को अपनी पसंद में शुमार किया है। इससे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

आज के समय में जब सभी बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब असंगठित क्षेत्र पर जब नकारात्मक असर पड़ रहा हो तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विस के क्षेत्रों में मध्यम व दीर्घ दोनों ही समय के लिए चढ़ान देखने को मिल रहा है। यदि इस बात को अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार लागू करके देखा जाए तो मिलेगा कि कमोडिटी और कृषि क्षेत्र के साथ ही अन्य संलग्न बाजार काफी प्रभावित हुए हैं। छोटी खरीदारी के लिए भी ई-वॉयलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, रिटेल सेक्टर

पर इसका व्यापक असर पड़ा है। रियल सेक्टर में एक ही सम्पत्ति को लेकर कैश की अधिकता के कारण बार-बार खरीदा और बेचा जाता है। इस कारण कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जरूरतमंद लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और कालेधन के दम पर लोगों ने अकूत व बेनामी सम्पत्तियां अर्जित कर रखी हैं। इन हालातों में जब देश में कालाधन की तबाह हो चला है तो प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में कमी आएगी और रियल इस्टेट में छाई महंगाई पर अंकुश लग सकेगा। यहां तक कि महंगी (लक्जरियस) कारें, जवाहरात, एसयूवी, नग, सोना और उच्च ब्रांड की चीजों की खरीद में कमी आएगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कम पूंजी वालों को वरीयता मिलेगी। हालांकि, इसके लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा।

गृहस्थों के घरों में रखी रकम जब बैंकों में जमा रही है तो जाहिर है कि इससे आने वाले दिनों में आरबीआई के पास कैश पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाएगा। इससे यह परिणाम देखने को मिलेगा कि भविष्य में आरबीआई रेपो रेट में अंतर करके देश में व्याप्त महंगाई को काबू कर सकने में सक्षम होगा।

संदर्भ :

छह लोगों को थ्री 500 और 1000 के नोटों के बंद किए जाने की जानकारी – नवभारत टाइम्स – 9 नवम्बर 2016

Gopika Gopakumar] Vishwanath Nair (8 November 2016)- "Rs500, Rs1000 notes may be back] if history is a guide"- Live Mint- अभिगमन तिथि : 9 November 2016-

Kumar Uttam ¼12 November 2016½- "The measure is anti & poor: When BJP opposed demonetisation during UPA 2016-

<https://ogaleshwarstory.com>

Web Title: experts analysis on the impact of demonetization of 1000 and 500 rupees notes

(Latest News in Hindi from inKhabar)

http://khojkhbar-pandeyhariram.blogspot.in/2016/11/blog-post_15.html

सामाजिक मीडिया और बाजार वाद

डॉ. नीलिमा चटर्जी

सहायक प्राध्यापक

समाजशास्त्र विभाग

शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

सामाजिक मीडिया विपणन संगठनों के एकीकृत विपणन संचार योजनाओं का एक नवीन घटक है। एकीकृत विपणन संचार अपने लक्षित बाजारों के साथ जुड़ने के लिए संगठनों द्वारा पालन किया जा रहा एक सिद्धांत है। एकीकृत विपणन संचार ग्राहक केंद्रित संदेश तैयार करने के लिए मिश्रित प्रचार तत्व—यथा विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, जन संपर्क, प्रचार, प्रत्यक्ष विपणन और बिक्री प्रोत्साहन को समन्वित करता है। पारंपरिक विपणन संचार मॉडल में, सामग्री, आवृत्ति, समय, संगठन द्वारा संचार माध्यम एक बाहरी एजेंट, यानी विज्ञापन एजेंसियां, विपणन अनुसंधान फर्म और जन संपर्क फर्म के सहयोग के साथ हैं। तथापि, सामाजिक मीडिया के विकास ने ग्राहकों के साथ संगठनों की संप्रेषण पद्धति को प्रभावित किया है। वेब 2.0 के उद्भव में इंटरनेट, लोगों को ऑनलाइन सामाजिक और व्यापार संबंध बनाने, सूचना साझा करने और परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए उपकरणों का एक सेट उपलब्ध कराता है।

सामाजिक मीडिया विपणन कार्यक्रम आम तौर पर ऐसी सामग्री तैयार करने के प्रयासों पर केंद्रित होते हैं जो ध्यान आकर्षित करें, ऑनलाइन संवाद जनित करें और पाठकों को अपने सामाजिक नेटवर्क के साथ उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। संदेश उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता के बीच फैलता है और संभवतः प्रतिध्वनित होता है, चूंकि यह ब्रांड या कंपनी के बजाय एक विश्वसनीय स्रोत से आ रहा है।

जन सामान्य तक पहुँच होने के कारण सामाजिक मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुँचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाता है। हाल ही के कुछ एक सालों में इंडस्ट्री में ऐसी क्रांति देखी जा रही

है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाता है जिसमें उनकी आयु, रुचि, लिंग, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं साथ ही साथ आलोचना भी की जा रही है।

सामाजिक मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जो आसानी से इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है, जो संगठनों को अपने ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अवसर देते हुए, ग्राहकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक मीडिया संगठनों को अपने विपणन अभियान को कार्यान्वित करने के लिए एक अपेक्षाकृत सस्ते मंच के रूप में कार्य करता है। संगठन अपने ग्राहकों और लक्षित बाजारों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

सामाजिक मीडिया विपणन ग्राहक की मदद के लिए अतिरिक्त माध्यम, ग्राहक और प्रतिस्पर्धी अंतर्दृष्टि पाने का साधन और ऑनलाइन उनकी प्रतिष्ठा के प्रबंधन की विधि उपलब्ध कराते हुए संगठन और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। उसकी सफलता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं उसका अपने ग्राहक के लिए प्रासंगिक होना, उनको वह जो मूल्य प्रदान करता है और उस नींव की मजबूती जिस पर वह निर्मित है। एक मजबूत नींव एक आधार या मंच का कार्य करता है जिस पर संगठन अपनी सूचना को केंद्रीकृत कर सके और लेख तथा प्रेस विज्ञापितियों के प्रकाशन जैसे अन्य सामाजिक मीडिया प्रणालियों के माध्यम से अपने हाल के विकास की ओर ग्राहकों को निर्देशित कर सके। ख, एक मजबूत नींव का लक्ष्य एक ऐसे मंच का निर्माण है जो अपने ग्राहकों को संगठन के साथ संप्रेषण का मौका देते हुए उन्हें आकर्षित करता और समर्थ बनाता है। यह मंच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठन को अपने ग्राहकों पर संगठन के प्रभावों को मापने और उन पर निगरानी रखने का भी अवसर देता है। सभी मंच हर संगठन के प्रयासों के लिए अनुकूल बनाए गए हैं, जहां मंच द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण अवसरों और चुनौतियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिक जनसांख्यिकी को लक्षित किया जा रहा है और अपने ग्राहकों से प्राप्त सूचना के आकलन के लिए मीट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मंचों द्वारा प्रस्तुत उपकरण उनके ग्राहकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में दूसरों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।

संगठन सामाजिक मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं

संगठनों द्वारा विपणन के लिए अधिक प्रभावी रूप से सामाजिक मीडिया का उपयोग करने के लिए, उन्हें यह समझना और स्वीकार करना होगा कि उभरते मंच वर्तमान विपणन पहल के प्रतिस्थापन के बजाय, उनके समग्र विपणन साधनों के अनुपूरक और विस्तार हैं। वे लक्ष्य, जिनके लिए सामाजिक

मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है

संगठनों को सफलता के लिए सामाजिक मीडिया हेतु अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने की जरूरत है। नंचों के बीच लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक सेवा और प्रसारण अद्यतनीकरण के लिए थ्रमइववा का इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि प्रचार के लिए जूपजजमत का उपयोग हो सकता है। YouTube संगठन के परदे के पीछे का नजारा दिखा सकता है। सफलता कारक लक्ष्यों पर निर्भर करता हैरू एक लक्ष्य हो सकता है प्रचार के परिणामस्वरूप नए ग्राहकों की एक विशिष्ट संख्याय एक और लक्ष्य हो सकता है किसी ग्राहक सेवा स्थिति में एक निर्दिष्ट समय के अंदर सभी ग्राहकों की शिकायतों का जवाब.

चूंकि सामाजिक मीडिया तेज गति से उभर रहा है (और समग्रतः अभी हाल ही का है), संगठन अक्सर सामरिक के बजाय स्वभावगत उपस्थिति स्थापित करते हैं।ख, ज्यादातर मामलों में, यह विकास उस हद तक उपयुक्त है जहां संगठन को अपने सामाजिक मीडिया के उपयोग और समग्र विपणन योजना में एकीकरण के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

सामाजिक मीडिया आबादी के क्रांतिक जनसमूह द्वारा अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि सामाजिक मीडिया में उपस्थिति संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है।ख,ख, आम तौर पर, बिलकुल नहीं की जगह थोड़ी बहुत आधिकारिक उपस्थिति बेहतर है, भले ही एक विशेष रणनीति परिभाषित नहीं की गई हो। रणनीति और योजना के साथ या उसके बगैर—अन्य विपणन पहल के समान ही—सामाजिक मीडिया के प्रयास सफल या असफल हो सकते हैं।

अधिकांश संगठनों के पास उनके विपणन प्रयासों के लिए कर्मचारी मौजूद हैं। जनसंपर्क, विज्ञापन, वेब और मुद्रित संचार ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रति कार्मिक और संसाधन समर्पित हैं। हालांकि सामाजिक मीडिया, विपणन रणनीतियों में हाल ही का क्षेत्र है, तथापि अधिक सफल संगठनों ने सामाजिक मीडिया से समन्वय स्थापित करने और उसके उपयोग में मदद के लिए समर्पित कर्मचारियों को रखा है। इन व्यक्तियों को संप्रति लोकप्रिय उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जब भी नए साधन आए और विकसित हों, उन नए उभरते साधनों के साथ प्रयोग करने की उन्हें छूट रहेगी.

कुछ संगठन ग्राहकों और सामान्य लोगों के मन में ब्रांड को ताजा रखने के लिए अपनी विपणन योजना में सामाजिक मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। एक सामाजिक मीडिया साइट पर संगठन के साथ जुड़ने से, संगठन को ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है, जो उनके ग्राहक हो भी सकते हैं या नहीं भी, बजाय इसके कि जब उन्हें अतिरिक्त सूचना की तलाश हो तभी उनसे संपर्क के लिए उस पर निर्भर हों.

सामाजिक मीडिया एक विशाल विज्ञापन मंच है। संगठन सामाजिक मीडिया पर साझा विशिष्ट दिलचस्पियों के आधार पर व्यक्तियों को लक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति जॉगिंग के बारे में एक YouTube वीडियो देखता है, एक जूता कंपनी एक विज्ञापन दे सकती है, या एक कॉफी कंपनी ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करते हुए विज्ञापन दे सकती है, जो सामाजिक मीडिया साइटों पर पोस्ट करते हैं कि वे थके हैं। सामाजिक मीडिया ने विज्ञापनदाताओं को अत्यंत संकीर्ण रूप से विज्ञापन जाल परिष्कृत करने का मौका दिया है।

कुछ संगठनों ने सामाजिक मीडिया विपणन पहल कार्यान्वित करते समय फायदे से अधिक नुकसान ही पहुंचाया है अन्य नए मीडिया मंच पर बहुत सफल रहे। उनकी सफलता की कुंजी थी, द्वार पर ही कॉर्पोरेट रवैया का परित्याग। सामाजिक मीडिया विपणन में, ग्राहकों की नजर प्रामाणिकता और संगठनों के साथ एक विश्वसनीय संबंध पर है, जिसके साथ वे रिश्ते बना रहे हैं।

Nestlé (नेस्ले)

Nestlé पर्यावरणवादियों के साथ विवादास्पद स्थिति में फंसा है, जो जल्द ही थंबइववा पर उनसे चिढ़ गए और Twitter पर एक "twitstorm" की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, एक YouTube वीडियो बनाया गया जो छमेजसत्र द्वारा ताड़ के तेल के निरंतर प्रयोग और वर्षा-वन के विनाश के कारण उन पर प्रहार करता है। Nestlé ने अपने प्रशंसकों से अपने वॉल पर केवल सकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करने के अनुरोध के साथ इस नकारात्मकता के प्रति जैसे-तैसे प्रतिक्रिया जताई। Facebook ने इन जनसांख्यिकी का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करने का निर्णय लिया। Facebook कानूनी तौर पर अपने वेबसाइट पर पोस्ट की गई सूचना पर सर्वाधिकार रखता है और उसने एक विज्ञापन कार्यक्रम तैयार किया जो उस सूचना के समूहन द्वारा थंबइववा के प्रयोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से और उनको आकर्षित करने वाले विज्ञापन द्वारा हर व्यक्ति को लक्षित करता है। इस रणनीति ने विज्ञापन की दुनिया में एक सनसनी फैलाई। इस प्रकार के विज्ञापन से पहले, पॉप-अप और बैनर में तत्व की कमी के कारण ऑनलाइन विज्ञापन कभी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे। इंटरनेट का उपयोग करते समय अधिकांश लोगों ने इसे कष्टप्रद और ध्यान भंग करने वाला पाया। Facebook द्वारा 400 मिलियन प्रयोक्ताओं से मजबूत अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक व्यक्ति को लक्षित करने के साथ, उसने हर कंपनी के लिए एक लक्ष्य बाजार तैयार किया। इसलिए अगर एक ब्रांडल कंपनी थंबइववा पर विज्ञापित करना चाहती थी तो वह सचमुच सुनिश्चित कर सकती थी कि उनके विज्ञापन केवल वे लोग देख सकें जिनकी सगाई हुई है या जो डेटिंग पर हों, इस आधार पर कि वे कितने आगे जाना चाहते हों। इसने Facebook को प्रति-विलक-भुगतान रणनीति के उपयोग की शुरुआत करने का

मौका दिया कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव की कमी की वजह से अधिकांश विज्ञापनदाता संकोच करते हैं।

Facebook के लिए पे-पर-क्लिक रणनीति के परिणामस्वरूप, जब भी कोई Facebook प्रयोक्ता एक विज्ञापन पर क्लिक करता है, तो हर बार कंपनी विज्ञापन के लिए थंबइववा को भुगतान करती है। अध्ययनों से पता चला है कि उनसत्तर प्रतिशत से अधिक ऑनलाइन खरीदार थंबइववा जैसे सामाजिक मीडिया का उपयोग न केवल लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं, बल्कि साथ ही यह भी देखने के लिए कि क्या लोकप्रिय है और क्या फैशनबल चीज है। मूल प्रति-क्लिक-भुगतान रणनीति प्रभावी नहीं थी क्योंकि उपयोगकर्ता नहीं चाहते थे कि उन्हें एक और पृष्ठ पर ले जाया जाए और वहां पर वे ऐसी कोई चीज देखें जो उनके लिए आकर्षक ना हो। Facebook की नई लक्ष्यीकरण प्रणाली के जरिए प्रति उपयोगकर्ता क्लिक का उनका अनुपात, किसी अन्य प्रतियोगी की तुलना में, यहां तक कि व्यवहसम से भी, ज्यादा है। यह समझ में आता है क्योंकि विज्ञापन इस तथ्य के लिए आकर्षक बन जाता है कि उनकी सगाई हो चुकी है या वे फैशन में रुचि रखते हैं।

Facebook ने न केवल अपने विज्ञापनदाताओं तक पहुंच के लिए, बल्कि Facebook उपयोगकर्ता के लिए भी एंगेजमेंट ऐड्स कहलाने वाले विज्ञापन भी तैयार किए। यह थंबइववा प्रयोक्ता और सामाजिक मीडिया को तीन अद्वितीय अनुभव अनुमत करता है। पहले आप विज्ञापन पर टिप्पणी कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता को यह कहने की छूट देता है कि उसे विज्ञापन या उत्पाद में क्या पसंद या नापसंद है। ये टिप्पणियां Facebook प्रयोक्ता के अन्य मित्र देख सकते हैं। जिससे उनके सामाजिक समूह को यह पता चलता है कि यह या तो बेकार है या बहुत खूब है और उन्हें उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरे, मित्रों को ऑनलाइन छोटे उपहार, मुफ्त ई-तौहफे देना एक लोकप्रिय बात हो गई है। विज्ञापनदाता अब मुफ्त ई-उपहार बना सकते हैं जो उपयोगकर्ता अपने दोस्तों को दे सकते हैं। अन्त में, उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा उत्पाद और संगठनों के मित्र बन सकते हैं, जो उन्हें अपने पसंदीदा कंपनी के थंबइववा पृष्ठ से जोड़ सकता है। यह उन्हें दुनिया भर में ऐसे लोगों के समूह में डालता है जो इसी तरह के उत्पादों का आनंद उठाते हैं और Apple जैसी कंपनियों को यह देखने का मौकघ देता है कि दरअसल उनके लक्षित दर्शक कौन हैं।

Facebook पर एक और प्रमुख विपणन संयोजन है अनुप्रयोग। आज तक थंबइववा पर सबसे अधिक प्रयुक्त कुछ मदों में से एक है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का एक बढ़िया उदाहरण है Farmville-Farmville] जिसके 80 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जो Twitter की वेबसाइट पर संप्रति मौजूद प्रयोक्ताओं से ज्यादा है। Facebook और उसके विज्ञापन पर इस तरह के अनुप्रयोग की

शक्ति अब तक कभी सुनी नहीं गई। संगठन इन-गेम मर्दों को तैयार कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता के फार्म की मदद करते हैं और जो कोई व्यक्ति उस फार्म का दौरा करता है वह उस व्यक्ति के फार्म पर मदद, कंपनी का विज्ञापन देख सकता है। यह एक प्रभावी विपणन रणनीति है क्योंकि कई लोग इसे विपणन के रूप में नहीं लेते, बल्कि मानते हैं कि कंपनी इस खेल में आपकी मदद कर रहा है। यह इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि Farmville के उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है और उनके साइट का दौरा करने वाले हर कोई विज्ञापन को देखेंगे।

सन्दर्भ -

डब्ल्यू ग्लिन मैनगोल्ड, डेविड जे. फॉल्ड्स, सोशल मीडियारू द न्यू हाइब्रिड एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, बिजनेस होराइजन्स, जर्नल ऑफ द केल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियाना विश्वविद्यालय
डब्ल्यू ग्लिन मैनगोल्ड, डेविड जे.फॉल्ड्स, सोशल मीडियारू द न्यू हाइब्रिड एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, बिजनेस होराइजन्स, जर्नल ऑफ द केल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियाना विश्वविद्यालय

<http://online-wsj-com/article/SB122884677205091919-html>

Imediaconnection

<http://www-stephanmiller-com/organic&social&media&marketing/> Stephan Miller-

http://www-marketing&online-co-uk/wiki/Social_Media_Usage_Statistics

<http://www-facebook-com/press/info-php/statistics>

<http://marketingprofs-com>

<http://www-dirjournal-com/articles/starbucks&social&media/>

<http://mashable-com/2010/07/15/old&spice&stats/>

<http://mashable-com/2010/07/14/old&spice&proposal/>

[http://www-youtube-com/watch?v\(JvuYcbgZl&U](http://www-youtube-com/watch?v(JvuYcbgZl&U)

शिक्षा जगत के बदलते मायने

डॉ. जे.पी. माकवे

एसोसियेट प्रोफेसर शिक्षा विभाग

राजीव गांधी कालेज भोपाल

दुनिया में अर्थव्यवस्था के विकास के साथ वर्कफोर्स यानी कामगारों और काम चाहने वालों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस मामले में अमेरिका और यूरोपीय देश आदर्श स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां वर्कफोर्स में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में फर्क लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार के साथ काम करने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से गिर रही है। विश्व बैंक के 2015 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 29 फीसदी है यानी भारत में हर सौ में 71 महिलाएं ऐसी हैं, जो वर्कफोर्स में शामिल नहीं हैं और ऐसी स्थितियां भी नहीं हैं कि उन्हें सहजता से काम मिल सके। दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चीन से भारत की तुलना करें तो चीन में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 70 पसैंट है। इस अंतर से समझा जा सकता है कि चीन भारत से पांच गुना से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है। सांस्कृतिक सवाल पब्लिक स्पेस में महिलाओं की गैर, मौजूदगी हमारे समाज की संरचनात्मक दिक्कत बन चुकी है, सबसे पहले तो इसे समस्या मानना बहुत जरूरी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 22 करोड़ और महिलाओं को वर्कफोर्स में होना चाहिए, लेकिन वे वर्कफोर्स से लापता हैं। इन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाना जरूरी है। पिछले दस सालों में जितनी तेजी से नौकरियों में पुरुषों की संख्या बढ़ी है, अगर महिलाओं को भी उतने ही मौके मिलते तो जीडीपी रेट में करीब 1.4 प्रतिशत का इजाफा हो सकता था। इस जादुई आंकड़े के साथ भारत इस समय चीन से भी तेजी से तरकी कर रहा देश बन चुका होता लेकिन, भारत अपने कई पड़ोसी देशों से फिसड्डी है।

म्यांमार में 79 पसैंट महिलाएं काम करती हैं तो नेपाल भी 83 प्रतिशत से ज्यादा भागीदारी के साथ हमसे कहीं आगे हैं। इस मामले में हमारी बराबरी पाकिस्तान के साथ है, जहां यह आंकड़ा 26 फीसदी है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं

की गैर, मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह लैंगिक असमानता है जो देश की प्रगति को भी खा रही है। भारत के पुरुषवादी समाज में आज भी महिलाओं को नौकरी करने से रोका जाता है।

सदियों से चली आ रही दकियानूसी परंपराएं आज भी अर्थव्यवस्था को पीछे घसीटने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां आधी आबादी के घर बैठने के बाद राष्ट्र ने तरकी के झंडे गाड़े हों? एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलना भी बड़ा मुद्दा है। सैलरी में भेदभाव के अलावा कुछ सेक्टरों की नौकरियों में महिलाओं से भेदभाव भी कार्यक्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व घटाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुषों को नौकरी में तरजीह दी जाती है। जैसे, जैसे महिलाएं करियर में पायदान पर ऊपर जाती हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है। ऐसा तब है जब महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। देश के दोनों सबसे बड़े निजी और सरकारी बैंकों में महिलाएं शीर्ष पदों पर बैठी हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े पदों पर महिलाएं मौजूद हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं।

भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का शादी के बाद घर बैठ जाना बहुत बड़े स्तर पर टैलेंट की बर्बादी है। जिस काम को एक अनस्किल्ड लेबर से कराया जा सकता है, वही काम एक उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च पद पर बैठ चुकी महिला नौकरी छोड़कर करती है। भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की अनुपस्थिति आर्थिक से कहीं ज्यादा सांस्कृतिक सवाल है। अगर यह सिर्फ आर्थिक मसला होता तो महिला वर्कफोर्स की अनुपस्थिति के मामले में बिहार और दिल्ली लगभग एक पायदान पर न होते। बिहार में वर्कफोर्स में जेंडर गैप 42.5 पसेंट है तो दिल्ली में यह 43.7 पसेंट है। यह साबित करता है कि मामला गरीबी और अमीरी से कहीं ज्यादा, परिवार और समाज में महिलाओं की हैसियत से जुड़ा है। पर्वतीय और उत्तर, पूर्वी राज्यों में महिलाओं को बेहतर दर्जा दिया जाता है तो वहां कार्यक्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति भी ज्यादा है। असुरक्षित माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहरी महिलाओं के नौकरियों से दूर रहने की वजह माना जाता है। आईएमएफ चीफ क्रिस्टीना लार्गेट ने इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि साउथ अफ्रीका में सार्वजनिक इलाकों में विद्युतीकरण से महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी करीब 9 पसेंट तक बढ़ गई। भारत भी इस अनुभव से सबक ले सकता है।

सवाल यह भी उठता है कि देश में बारहवीं और ग्रेजुएट होने वाली लड़कियों की संख्या में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये आंकड़ा महिलाओं की रोजगार में हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ रहा? सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब अगर आजादी के करीब सात दशक बाद भी समाज से नहीं निकले तो आगे भी इसकी उम्मीद कम ही है। कानून का सहारा तो क्या वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का रास्ता कानून से होकर गुजरेगा? देश में अब तक यही परंपरा रही है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए कानून ही बनाना पड़ता है। माना जा सकता है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी हमें सरकार का ही रुख करना पड़ेगा। पॉलिसी लेवल पर बदलाव ही शायद हालात में सुधार ला पाए। नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देना एक उपाय हो सकता है।

उम्मीद है कि महिला सशक्तीकरण को तरजीह देने वाली मौजूदा सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझेगी और आधी आबादी को देश की तरक्की में शामिल करने के लिए कदम उठाएगी। आधी आबादी को पीछे छोड़कर कोई देश बाकी दुनिया से बराबरी तक नहीं कर सकता, महाशक्ति बनना तो दूर की बात है।

डिग्रीयों की बंदरबाट ने प्रतिभा को छोड़ा पीछे

अच्छी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का सविधान प्रदत्त अधिकार है, हालांकी आज के माहौल में शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों और उन प्रयासों से प्राप्त सफलता को देखते हुए लगता है की सविधान निर्माताओं ने 'राइट टू एजुकेशन' देकर सविधान को ना केवल नीरस होने से बचाया है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने हास्य बोध का भी परिचय दिया है। इस तरह से सविधान और इसके निर्माताओं ने ना केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को सुरक्षित रखा है बल्कि हमारे मनोरंजन का भी ख्याल रखा है।

आज के समय में 'मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया' हो या ना हो लेकिन हाथ में डिग्री होना बहुत जरूरी है और हाथ में डिग्री होने के लिए आपका हाथ 'ढाई किलो' का होना भी जरूरी नहीं है, हां लेकिन हाथ में डिग्री के लिए थंडी 'हाथ की सफाई' मददगार होती है। आजादी के बाद से ही हमने ज्यादातर समय समाज और देश का भला करते हुए 'हाथ' की सफाई देखी है। डिग्री और मार्क्स को लेकर हम भारतीयों का दीवानापन, विजय माल्या और ललित मोदी की तरह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर इंसान अंक के पंख लगाकर सफलता की उड़ान भरना चाहता है। हम बचपन से सुनते आये हैं की हर मां-बाप का एक ही सपना होता है (जिसे वो खुली आंखों और कई बार खाली जेब से भी देखते है) की उनके बच्चे पढ़-लिखकर, कोई बड़ी डिग्री लेकर, अच्छी नौकरी करे, उनका नाम (ऋतिक) रोशन करे, लेकिन हर प्रोफेशन में डिग्रीयो की बंदरबाट ने प्रतिभा की वाट लगा दी है। वैसे डिग्री लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है की अगर डिग्री लेकर अच्छी नौकरी मिले जाये तो पैसे मिलने लगते हैं और डिग्री लेकर नौकरी ना भी मिले तो घरवालों और रिश्तेदारों के ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब वृत्त ना कुछ तो मिलने ही लगता है और इस तरह डिग्री अगर बेस्ट ना भी निकले तो उसे बिलकुल वेस्ट तो नहीं बना जा सकता है क्योंकि आजकल डिग्री बनाने में अच्छे कागज का इस्तेमाल हो रहा है जो समोसा से लेकर बरत-पाव तक, सबका तेल सोख सकता है। शौक बड़ी चीज है इसीलिए हम सफलता को डिग्रीयों से मापने के शौकीन हैं कोई इंसान भले ही बिना किसी डिग्री के मंगल ग्रह पर पहुंच कर पानी की खोज कर दे लेकिन शर्म से पानी पानी हुए बिना, हम भारतीय उसके मंगल की कामना उसकी दसवी और बारहवीं की मार्कशीट में विज्ञान और गणित के अंक खोजने के बाद ही करेंगे। भले ही कोई बंदा चंदा मामा तक पहुंच जाये लेकिन उसकी तारीफ करने से पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे की उस बन्दे ने कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना चंदा दिया था। जहां चाह, वहां राह इसीलिए जिनको पढ़ लिख कर डिग्री नहीं मिलती वो डिग्री खरीद लेते हैं, चूंकि पैसा बिना स्पीकर के ही बोलता है इसलिए डिग्री के साथ कभी कभी थर्ड डिग्री भी बोनस स्वरूप मिल

सकती हैं। डिग्री खरीदने वाले लोग, खुद्द होते हैं, वो अंको और डिग्री के लिए पढाई-लिखाई पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो खुद तय करते हैं उन्हें कितने अंक, कौनसी डिग्री और कौनसी यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए। देश का स्वाभिमान और खुदारी बचाए रखने में ऐसे लोग अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव के समय बुद्धिजीवी और जातिवाद विरोधी पत्रकार भले ही गांव-गांव जाकर लोगो की जाती पूछते हो लेकिन लड़की वाले तो सदियों से लड़के के घर का पता और लड़के की डिग्री ही पूछते आ रहे हैं। वैसे जमाना भी पूछ-पूछ कर पूंछ हिलाने वालो का ही हैं। लड़की वाले पहले डिग्री मांगते हैं और उसके जवाब में फिर लड़के वाले दहेज मांगते हैं और बाद में लड़की वाले पनाह मांगते हैं। ये मांगने का सिलसिला मंगनी तक चलता रहता हैं। डिग्री का दीवानापन ऐसा, मानो लड़का शादी के समय लड़की के गले में वरमाला नहीं डिग्री पहनाएगा और लड़की, लड़के के बदले डिग्री के साथ 7 फेरे लेगी। हमारे यहां शादियों में काली, मेंहदी से लेकर दलेर मेंहदी और डिग्रियों का प्रयोग भूतकाल से प्रचलित हैं। हमारे देश में मांगने वाले हमेशा से गलतफहमी और चर्चा में रहते हैं। मांगने वालो ने काले धन वाले 15 लाख, आजाद देश में आजादी, फ्री वाई-फाई और क्या क्या नहीं मांगा, लेकिन मांग कभी पूरी नहीं होती, हां भर जरूर दी जाती हैं। अब तो अपने झूठे वादों से जनता को पानी पिलाने वाले लोग भी चाय पिलाने वालो की डिग्री मांग रहे हैं। अपने राज्य की सारी समस्याओं और उनके समाधानों से कोसो दूर, सबको कोसते हुए एक आईआईटी पास आउट, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, मुख्यमंत्री, एमए. पास प्रधानमंत्री की डिग्री चेक करना चाहता हैं यहीं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती हैं, इससे हमारा संघीय ढांचा मजबूत होता हैं और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध मधुर होते हैं जो जनता से किये हुए वादे पूरे करने से कभी नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री प्रामाणिक निकलने से ना केवल देश का निर्यात और विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेगा बल्कि डॉलर के मुकाबले रूपया भी मजबूत होगा। साथ ही साथ गरीबी और भ्रष्टाचार पर भी ठीक उसी तरह से लगाम लगेगी जिस तरह से पावर प्ले खत्म होने पर चौके-छक्कों पर लगती हैं। इसके ठीक उलट, डिग्री फर्जी निकलने पर देश में अराजकता फैल सकती हैं और आपातकाल जैसा माहौल बन सकता हैं। समय के साथ हमारे राजनेता के विचारों ने भी करवट ली हैं पहले वो सीधा इस्तीफा मांगते थे लेकिन अब पहले डिग्री मांगते हैं फिर इस्तीफा, मतलब उन्होंने ना केवल अपने विचारों को ऊपर उठाया हैं बल्कि इस्तीफे का मूल्य भी बढ़ा दिया हैं। लोकतंत्र में 5 साल का समय बहुत लंबा होता हैं लेकिन अगर इसी तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे की डिग्री चेक करते रहे तो 5 साल का समय हंसते-खेलते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीत जाएगा और डिग्रियों की प्रामाणिकता भी बढ़ेगी। शिक्षक बच्चों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। पहले से यह परंपरा रही है कि बच्चों को नैतिक मार्ग पर ले जाने के लिए माता-पिता के बाद शिक्षक ही एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है। यही कारण है कि शिक्षकों पर बिना किसी सदेह के विश्वास किया जाता रहा है। परन्तु समय बदलता गया, गुरुकुल प्रथा सरकारी स्कूलों में परिवर्तित हुई तथा आज यह शिक्षा संस्थान व्यापार व अराजकता की दुकानों में बदल गये

हैं। न तो गुरु शिष्य का बेमिसाल सम्बन्ध रहा है और न ही शिक्षा का नैतिक उद्देश्य।

कारण कोई भी हो लेकिन नैतिक मूल्यों में यह गिरावट भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पब्लिक स्कूल पैसा कमाने के स्रोत बन गये हैं तथा सरकारी स्कूल अनुशासनहीनता के केंद्र। न तो शिक्षकों में वो गुण रहे जो गुरुकुल के गुरुओं में होते थे और न ही शिष्यों में वह भाव जो अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करता हो। अतः समाज का निर्माण करने वाला यह स्तंभ ज़र-ज़र हालत में पहुँच चुका है। यदि समय रहते इसे गिरने से नहीं रोका गया तो सारा भवन धराशायी हो जायेगा।

शिक्षा जगत की कुछ ऐसी ही कहानी है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने की जगह साक्षरता दर को सुधारने का प्रयास सरकार करती रहती है जिससे लड़के-लड़कियाँ साक्षर तो बन रहे हैं परन्तु उनमें संस्कारों का अभाव होता जा रहा है। अच्छे शिक्षक अच्छी शिक्षा व दीक्षा प्रदान कर सकते हैं परन्तु आज के समय में अच्छे शिक्षकों की भी कमी अखर रही है। पहले जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते थे, उनमें से ज्यादातर शिक्षक बनना अपना लक्ष्य बनाते थे लेकिन आज पैसा कमाने की होड़ में वे बच्चे निजी कंपनियों में काम करना पसंद करते हैं जिससे शिक्षा जगत में शिक्षकों की भारी कमी हो गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज की तारीख में 5.8 लाख प्राथमिक स्तर के शिक्षक व 3.5 लाख अप्पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 5 लाख शिक्षक विश्वविद्यालयों के लिए वाँछित है। ऊपर से सरकार शिक्षकों को पूरा वेतन व नौकरी की सुरक्षा देने के बजाय उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट पर रख रही है जिससे शिक्षा जगत में शिक्षक अपने करियर के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि आज अच्छे शिक्षक मिलना दुर्लभ हो गये हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल एक सपना मात्र होगा।

सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के बच्चों के बराबर लाने के लिए शिक्षा विभाग कई प्रकार के कदम उठा रहा है लेकिन जब तक शिक्षक खुद शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारते तब तक विभाग के वे कदम निर्थक साबित होंगे। शिक्षकों को पहले यह समझना होगा कि वे समाज के निर्माता हैं। अतः उन्हें समाज को किस ओर ले जाना है इस पर विचार करना होगा। सरकारी स्कूलों का यह हाल है कि अधिकतर स्कूलों में शिक्षक स्वयं बच्चों को परीक्षा के दौरान नकल करवाते हैं तथा बच्चों के माता-पिता व स्कूल प्रबंधन समितियाँ इस कार्य के लिए उन्हें सहयोग देते हैं। इसका प्रमाण यदि विभाग को चाहिए तो जिन स्कूलों का रिजल्ट 90 प्रतिशत से ऊपर रहता है या स्कूल सड़क से बाहर स्थित है, में परीक्षा के दौरान अचानक जाकर देखें कि नकल का कैसा रूप वहाँ देखने को मिलता है। दुर्गम स्थाओं पर स्थित स्कूलों में तो परीक्षा एक ढोंग मात्र रह गया है। साल 1999 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड के अनुरोध पर बतौर एस.डी.एम. चौपाल मैंने स्वयं यह प्रयोग करके देखा तो शत-प्रतिशत रिजल्ट देने वाले 9 स्कूलों का रिजल्ट जीरो से दस प्रतिशत तक रहा जो शिक्षा विभाग की आँखें खोलने के लिए पर्याप्त है। ये वही स्कूल थे जिन्हें पिछले सालों अच्छा रिजल्ट देने के लिए शिक्षा विभाग पारितोषिक देता रहा था।

यदि नकल रोकनी है तो जिस स्कूल में मास कोपिंग पाई जाये उसके ड्यूटी पर तैनात सभी शिक्षकों के खिलाफ एंटी-कोपिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए तथा उस दिन की परीक्षा रद्द घोषित की जानी चाहिए। यह प्रयोग नकल रोकने के लिए कारगर साबित हुआ था। यह बात अलग है कि इस सारे अभियान को सफल बनाने की कीमत मुझे जानलेवा हमले से चुकानी पड़ी थी। देखना यह भी आवश्यक है कि औचक निरीक्षण करने वाले कितने शिक्षक व अधिकारी इस प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और जो ऐसा जोखिम उठा कर सराहनीय कार्य करते हैं उनके लिए सरकार के पास सुरक्षा एवं प्रोत्साहन हेतु क्या योजना है? ऐसी सूरत में केवल शिक्षा निर्देशालय से फ़रमान जारी करना पर्याप्त नहीं है अपितु धरातलीय स्थिति को समझते हुए शिक्षा में सुधार लाने होंगे। कार्यवाही बच्चों के खिलाफ ही नहीं अपितु शिक्षकों के खिलाफ भी होनी चाहिए। रद्द की गयी परीक्षा जिम्मेवार अधिकारी की निगरानी में करवानी चाहिए ताकि बच्चों को भी अपना चेहरा आईने में नज़र आ सके। इस सम्बंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाये गये उड़नदस्ते केवल अपनी ड्यूटी निभाने तक सीमित रहते हैं। नकल कारगर तरीके से रोकना उनका धेय्य नहीं होता। उड़नदस्ते में शामिल कुछ सदस्य पहले ही सम्बंधित स्कूलों को आने की सूचना दे देते हैं या फिर सरेआम जा कर स्कूल में अपनी हाजिरी दिखा कर अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था में नकल जैसी पनप रही बुराई को रोका जा सकता है?

यह कहना भी सही नहीं कि सभी शिक्षक नकल करवाना चाहते हैं। परन्तु जो इस प्रथा के विपरीत चलते हैं उनको न तो स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है और न ही स्कूल के मुखिया का। इसलिए ऐसे अध्यापक कई बार परीक्षा ड्यूटी से अपना मुंह मोड़ना ही उचित समझते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की पहचान की जाये, उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जाये तथा सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाये। ऐसे शिक्षकों के लिए सरकार या विभाग के पास क्या योजना है जो पढ़ाते भी ईमानदारी से हैं और नकल जैसी सामाजिक बुराई को न पनपने देने के आरोप में स्कूल प्रबन्धन समितियों के प्रतिनिधियों के कोप के भाजन भी बनते हैं? सम्मान उन शिक्षकों को मिले जो धरातल पर अच्छा काम करते हैं न की उनको जो विभिन्न स्तरों से प्रमाण पत्र इकट्ठे करके अवार्ड के लिए अपनी झोली फैलाकर सरकार के पास आते हैं। इस बात की भी आवश्यकता है कि शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के बजाय रेगुलर नौकरी पर रखा जाये ताकि वे लगन से कार्य करें। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों पर समय-समय पर दूसरे विभाग जैसे- चुनाव, जन-गणना आदि का काम भी सौंपा जाता है जिससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ता है। अतः इस प्रकार के कार्य शिक्षकों को न सौंपे जायें। शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट रिजल्ट प्रतिशत के आधार पर नहीं अलबत्ता बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर लिखी जानी चाहिए तभी भवन के इस जूर-जूर हुए स्तंभ को टूटने से बचाया जा सकता है। निर्देशालय से शिक्षकों को ताजा दायित्व यह मिला है कि उन्हें देश-विदेश के घटनाक्रम के सम्बंध में प्रश्न बच्चों से तैयार कराने होंगे। निर्देशों में यह भी है कि स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान उप-निदेशक

विद्यार्थियों से सवाल पूछेंगे। विभाग की यह पहल तो अच्छी है लेकिन स्कूलों की बुनियादी जरूरतों व खामियों की तरफ भी ध्यान देना होगा अन्यथा निर्देश केवल हवाई आदेश बनकर ही रह जायेंगे।

संदर्भ

शिक्षा - मरिअम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोष से परिभाषा

यूनेस्को, शिक्षा सभी को लिए - मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2008, प्राथमिक शिक्षा का नेट नामांकन दर

मैसाचुसेट्स के शिक्षा विभाग की वैकल्पिक शिक्षा की परिभाषा

विषयों का उदाहरण ...

दुन और दुन

रेंजुली का जीवनी लेखक

थॉमस आर्मस्ट्रांग की वेबसाइट एकाधिक समझों का विस्तृतीकरण

किसेय वेब साइट

चित्रकार प्रकार विवरण

स्वस्सिंग, र. ह., बर्बे, व. बी., × मिलोने, म. न. (1979). स्वस्सिंग - बर्बे रूपात्मकता सूचकांक- ज़नेर - ब्लोसेर सूचकांक कित .कोर्लबस, ओ ह = ज़नेर - ब्लोसेर .

ARABIC STUDIES IN INDIA

Nageena Akhter

Research Scholar Deptt. Of Arabic

Barkatullah University Bhopal (M.P)

Arabic language is the language of the Qur'an. Today, it is the most important language of the Semitic group spoken by millions of people and understood by many more. It is the strongest language in terms of anatomical structure; sentences structures, i.e., the strongest in terms of the potency of its grammars, style, idiom and literature. It is the holy language of Islam and as such, it has been studied in the four corners of the world as a language of a great religion and civilization.

India has been one of the most well-known non-Arab states where Arabic language and literature grew, developed and flourished on a large scale. Various Arabic madrasahs and cultural institutions of higher learning under the personal guidance and scholarly interest of the Sultans were set up during the medieval India, which produced a good number of poets, writers, Islamic thinkers, commentators of the holy Qur'an, scholars of the Hadith etc. Their noble works can be compared to any work of any great Arab scholar. Mention may be made here in this regard about the following scholars. Allamah Sighani Lahori (d. 1252), the author of the great book al-'Ubabuz-Zakhir wa al-Lubabul-Fakhir" on grammar and lexicography. Gulam Ali Azad Bilgrami (1116- 1200A.H.), who has penned many outstanding Arabic books on history and literature like "Subhatul-Marjan". Besides, he is regarded to be

the greatest Indian Arabic poet and is well known as Hassanul-Hind. About 11,000 verses composed by him are the living proof of his extraordinary poetic talent. Shah Waliullah Dihlawi (1114-1176 A.H.), who has produced the great book Hujjatullahil-Balighah?, on the science of Hadith. Abdul Hai al-Hasani (1286-1341 A. H.), the writer of the famous book "Nuzhatul-Khawatir" on the great Indian scholars in different fields from 622 .A.D.up to the time of the author. Zainuddin bin Abdul Aziz who produced an authentic prose work entitled ?Tuhfatul Mujahidin? on the struggle of the Zamorins of Calicut against the Portuguese. Siddiq Hasan Khan (1248-1307 A.H.) who besides being a poet, was a great scholar of Hadith, and authored a good number of valuable books on Arabic philology like ?Abjadul-Uloom?. Muhammad ?Ala al-Thanawi, composer of the outstanding dictionary ?Kash-shaf Istilahat al-Funun? on technical terms. Abul Faid Faidi (954-1004 A.H.), the author of the undotted tafsir "Sawatiul-Ilham?. Abdul Haqq Dihlawi (958-1052 A.H), the pioneer of Hadith studies in the Indian subcontinent who produced many pearls and gems in Hadith literature like ?Lamatut-Tanqeeh. Fadl Haqq Khairabadi (1212-1278 A.H.), one of the greatest Indian philosophers and author of the famous book ?al-Hadiyyatus-sayeediyyah? on wisdom literature, and so on. Arabic as well as the religious sciences had lost their position of pride because of the disgusting aggressive educational policy of the British government. Instead of Arabic, English overnight became the medium of higher education and particularly, of secular arts and sciences. As a result, the Muslims fell behind in all aspects of life. This, of course, may be considered to be a planned strategy of Macaulay's scheme of education. The Indian Muslim scholars, therefore, took farsighted attempt to establish Arabic and Islamic cultural learning centres across the country, with a view to reviving the glorious position of Arab Islamic culture. And thus, an oriental university in the Punjab, an oriental Department at Aligarh, Darul Uloom Deoband, Darul Uloom Nadwatul Ulama. etc. came into existence. Each of these institutions took great effort in countering the Christian challenges. Besides, they were able to give birth a new spirit in cultural as well as modern studies to a considerable extent. Consequently, Arabic language and literature, today, has been one of the important subjects of learning.

It is to be mentioned here that the Nadwis (scholars produced by Nadwa) took utmost

care in order to bringing out the Arabic language from the corner of obscurity and stagnation and proved with potency and lively activity. that Arabic is a living language having bright prospects. They are still on their noble efforts in enriching and developing Arabic language and Islamic culture in India. In the twentieth century, India has produced a good number of literary figures and writers who got world wide fame and their literary products are similar to that of the great Arab litterateurs. For instance, Abul Hasan Ali Nadwi (1914-1999 A.D), the author of the world famous book "ma za khasir al alam be in hetat -e-al-muslemeen, Abdul Aziz Maimoni (1888-1978A.D.) who formerly held the chair of Arabic in the universities of Aligarh and Karachi and since long has been recognized as one of the greatest living authorities on Arabic language and literature, Hamidud-din al Farahi (1280-1349A.H), who has written the famous tafsir "al-Imaan Fi Aqsamil- Quran? and so many others. These writers were greatly influenced by modern Arabic literature and its various art forms. Apart from that, they were impressed by western literatures. Some modern styles and themes like criticism, politics, etc., therefore, are visible in their popular writings. They are also followed by some later modern writers in these aspects to some extent. The scholars and writers who have been teaching in the modern colleges and universities have taken part mainly in translation. We note that a number of valuable works have been translated from Sanskrit, English, Urdu, etc. into Arabic by them. Likewise, they have translated hundreds of short stories, plays, novels as well as social, cultural, political and religious scholarly essays from English, Hindi and many other Indian languages into Arabic. In this way, the modern university teachers have played a great role in enriching Arabic literature and Islamic culture which can never be ignored. Some of the writers who have earned high popularity in contemporary universities through their erudite treatises are Dr. Abdul Halim Nadwi, Dr. Zubair Ahmad Faruqi, Dr. Masud Rahman Khan, Dr. Md. Rashid Nadwi. Dr. Shafiq Ahmad Khan Nadwi and Dr. Aslam al-Islahi. On the other hand, the scholars of the religious institutions have occupied leading position in compiling and producing books purely in Arabic on Islamic as well as various literary topics. Here mention may be made the names of Anowar Shah Kashmiri (1292-1352A.H), the author of the most authentic book on Hadith literature "Faidul Bari", Wahiduzzaman Kairanwi (1929-1996 A.D), the writer of the book

"al-Qira-atul -Wadihah?", Rabi Hasan Nadwi (b. 1929 A.D), the present Rector of Nadwa and the author of the outstanding book "al-Adabul Arabi Baina Ardin wa Naqdin". and so on. In reality, they have devoted themselves exclusively to the study of religious sciences and to the cultivation of high standard Arabic.

It is significant to note here in this context that like all other non-Arab states, in India too, the holy Qur'an has been one of the greatest factors which participated in developing the Arabic language, widening its scopes and strengthening its basic elements. The Muslims assumed the study of Arabic with great importance in order to appreciating the teachings of the divinely messages of the Qur'an. The most prominent madrasahs and Islamic learning centres which have been playing leading part in enriching Arabic literature and Islamic culture throughout the country are (1) Darul Uloom Deoband. (2) Darul Uloom Nadwatul Ulama, Lucknow. (3) Jamiah Salafiyah Benares. 4. Madrasa Mazahirul Uloom, Saharanpur, UP 5. Jamia Islamia Sanabil, New Delhi. 6. Madarsatul Islah, Saraimir, Azamgarh, UP. 7. Jamiatul Falah, Bilariaganj, Azamgarh, UP. 8. Jamiatur Rashad, Azamgarh, UP. 9. Jamia Darus Salam, Omerabad (Tamil Nadu). 10. Jamia Islamia Kashiful Uloom, Aurangabad, Maharashtra 11. Jamia Alia Arabia, Mau Nath Bhanjan, UP. 12. Al-Jamiatul Islamia, Tilkhana, Siddharth Nagar, Basti, UP. 13. Madrasa Riyazul Uloom, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi 14. Jamitus Salehat, Rampur, UP. 15. Jamia Mohammadia, Malegaon, Maharashtra. 16. Darul Uloom Ashrafia Misbahul Uloom, Azamgarh, UP. 17. Jamia Ibn Taimiya, Champaran-12, Bihar. 18. Tauheed Education Trust, Kishanaganj, Bihar. 19. Jamia Misbahul Uloom, Siddharth Nagar, U.P. 20. Darul Uloom Al-Islamia, Basti, U.P. 21. Darul Uloom Ahmadi Salafia, Darbha etc.

The most famous colleges in which Arabic language and literature have been taught are numerous in number located in various parts of the country. Now let's cast a fleeting look in the leading Indian universities which have been contributing much in various ways in the development of the Arabic language and literature to a large extent. Calcutta University established in 1857 A.D. Arabic study in this university was started from its very inception and it got new impetus since 1916 A.D. presently, the Department of Arabic and Persian has been taking utmost care in teaching Arabic with special attention in modern and func-

tional Arabic. Madras University established in 1857 A.D. Arabic was included in its offering courses in 1927 A. D. and was taught under the Department of Islamic studies which contained Arabic, Persian and Urdu languages. In these days, Here, Arabic is being taught in various levels of learning like M.A., M.Lit., Ph.D. and certificate courses. Aligarh Muslim University which was founded by Sayed Ahmad Khan as a college in 1875 A.D. and was recognized as a university in 1920 A.D. It has been offering courses on Arabic language and literature since its very inception through the orientalist. This university has a remarkable contribution in the development of Arabic literature in the Indian subcontinent. In addition to teaching, its concerned Department has been publishing a large number of Arabic books, journals, newspapers, magazines, etc. Some of them have already gained much popularity in the Arab world. Bombay University established in 1857 A.D. In this university too, Arabic language and literature has been taught in different stages of learning including doctorate. Jamiah Milliyyah Islamiyyah established in 1920. Although Arabic was introduced in its course list at the very beginning yet the Department of Arabic came into existence in 1982 A.D. The introduction of further prominent universities of the country are as under:

1- Assam University, Assam - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil., Ph.D., and D.Litt.

2- Aligarh Muslim University, U.P.- Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., M.Phil., Ph.D., Certificate and Diploma courses.

3- Banaras Hindu University, Varanasi - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., Ph.D., Certificate, Diploma and PG Diploma courses.

4- University of Allahabad, U.P. - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., M.Phil. and D.Litt.

5- The English and Foreign Languages University, A.P. - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., Ph.D., Certificate, Diploma and Advanced Diploma and Diploma in Translation.

6- Maulana Azad National Urdu University, A.P. - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., Ph.D., Certificate, Diploma and Diploma in Translation.

7- Indira Gandhi National Open University, Delhi - Courses offered in Arabic are: Ph.D., Certificate course.

8- Jamia Millia Islamia, Delhi - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., Ph.D., Certificate, Diploma and Advanced Diploma.

9- Jawaharlal Nehru University, Delhi - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., M.Phil. and Ph.D.

10- University of Delhi, Delhi - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil., Ph.D., Certificate, Diploma and Advanced Diploma in Arabic.

11- Pondicherry University, Pondicherry - Course offered in Arabic is: Certificate of Proficiency in Arabic.

State Universities

1- Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Bihar - Courses offered in Arabic are: Certificate & Diploma in Arabic.

2- Patna University, Bihar - Course offered in Arabic is: M.A.

3- Calicut University, Kerala - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil., Ph.D., Certificate in spoken Arabic, Diploma in commercial Arabic, and P.G. diploma in translation and secretarial practice. 4- Kerala University, Kerala - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A.,

5- Barkatullaah University, M.P. - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil., Certificate & Diploma in Modern Arabic.

6- Lucknow University, U.P. - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., Proficiency and Diploma.

7- Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, U.P. - Course offered in Arabic is: B.A.,

8- Aliah University, Bengal - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A. and Ph.D.,

9- Burdwan University, Bengal - Course offered in Arabic is: B.A.

10- Calcutta University, Bengal - Courses offered in Arabic are: M.A. and Ph.D.,

11- Cotton College State University, Assam - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A.,

12- Gauhati University, Assam - Courses offered in Arabic are: M.A. and Ph.D.,

13- Baba Ghulam Shah Badshah University, J&K - Courses offered in Arabic are: B.A., M.A., M.Phil. and Ph.D..

14- Islamic University of Sciences & Technology University, J&K - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil and Ph.D., Certificate Course in Modern Standard Arabic.

15- Kashmir University, J&K - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil. and Ph.D., Certificate & PG Diploma in modern spoken Arabic.

16- Bangalore University, Karnataka - Courses offered in Arabic is: Certificate course in Arabic of 8 months.

17- Karnataka University, Karnataka - Courses offered in Arabic is: Certificate course in Arabic.

18- Mysore University, Karnataka - Courses offered in Arabic are: Certificate & Diploma courses in Arabic.

19- Mumbai University, Maharashtra - Courses offered in Arabic are: Certificate, Diploma & Advanced Diploma courses in Arabic.

20- The Rashtasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Maharashtra - Course offered in Arabic is: M.A..

21- Madaras University, Tamil Nadu - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil. and Ph.D.

22- Osmania University, Telangana - Courses offered in Arabic are: M.A., M.Phil. and Ph.D., Certificate Proficiency in Arabic, Junior Diploma in Modern Arabic, Senior Diploma in Modern Arabic & P.G. Diploma in Translation in Arabic.

There are many more colleges extend over some states of India such as Kerala, Jammu & Kashmir, West Bengal and Tripura that have departments of Arabic. "The scholars and writers who have been teaching in the modern colleges and universities have taken part mainly in translation. We note that a number of valuable works have been translated from Sanskrit, English, Urdu, and so on into Arabic by them. Likewise, they have translated hundreds of short stories, plays, novels as well as social, cultural, political and religious scholarly essays from English, Hindi and many other Indian languages. In short arabic language has bright future in india.

References

- I. Qutbuddin, Tahera : Arabic in India: A survey and classification of its uses, compared Persian. Journal of the American Oriental Society 2007
- II. Zayat Ahmad Hassan : Tarekh-ul-adb-al-arabe, Itchad Book Depot, Deabond (U.P)
- III. Muhâmmad al farooq-e : Al-arabeyatu w adabha, Irshad Book Stall calcuit-4
- IV. <http://www.importanceoflanguages.com/LearnArabic/>
- V. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/listofislamicuniversitiesandcollegesinindia>

IMPORTANCE OF ARABIC IN INDIA

IMTIYAZ AHMAD WANI

S/o Noor Muhmmad Wani

Sallar Pahalgam, kashmir

Introduction

Arabic is an international language. It is the official language of about two dozen countries and there are about 400 million speakers of Arabic across the world. It is spoken in many countries both as native as well as a second or foreign language. It is one of the official languages of the UNO (United Nations Organization). Arabic is one of the six official languages at the United Nations and is also spoken by a large group of masses in Asia and Africa. In the middle ages, it was the leading language of the world and occupied an international position similar to that of English at the present time. It has left much influence over the European as well as Indian languages. Besides this, it is the holy language of Islam and as such it has been studied in every nook and corner of the globe as a language of a great religion and civilization.

It is worth mentioning here in this connection that, study of the Arabic language is essential from the viewpoint of socio-historical, cultural, job opportunities as well as Indo-Arab relationship. So this paper has made an attempt to analyze the significance of Arabic Language in India.

Arabic In India

Arabic, in India, has been taught in different ways for more than fifteen centuries. The relations between India and the Arab world date back to very ancient times, and the Arab

merchants appear to have played leading part in establishing as well as strengthening commercial and cultural links between the two nations. With the advent of Islam in the Indian subcontinent, these ties of friendship became stronger than ever before, particularly, for cultural and political reasons. Several Muslim empires were established on the soil of India which lasted for more than eight centuries. India became enriched with their treasures-of various sciences of knowledge, arts, culture and literatures. It is to be remarked here that India has been one of the most well-known non-Arab states where Arabic language and literature grew, developed and

flourished on a large scale. During the period of Arab rule in the Indian Territory, Arabic continued to be the official language of the government and administration and the unrivalled medium of sacred knowledge and literary achievement. Moreover, various Arabic madrasas and cultural institutions of higher learning under the personal guidance and scholarly interest of the Sultans were set up which produced a good number of poets, writers, Islamic thinkers, commentators of the holy Qur'an, scholars of the Hadith etc. Their noble works can be compared to any work of any great Arab scholar. There were many Arabic scholars during the medieval India, few of them are as :

- * Allamah Sighani Lahori (d. 1252A.H.), the author of the great book "al-'Ubabuz-Zakhir wa al-Lubabul-Fakhir" on grammar and lexicography.
- * Gulam Ali Azad Bilgrami (1116- 1200A.H.), who has penned many outstanding Arabic books on history and literature like "Subhatul-Marjan,
- * Shah Waliullah Dihlawi (1114-1176A.H.), who has produced the great book "Hujjatullahil-Balighah", on the science of Hadith.
- * Abdül Hai al-Hasani (1286-1341A. H.), the writer of the famous book "Nuzhatul-Khawatir" on the great Indian scholars in different fields from 622 .A.D.up to the time of the author.
- * Zainuddin bin Abdul Aziz who produced an authentic prose work entitled "Tuhfatul Mujahidin
- * Abu al-Faiz ibn Mubarak Faidi (1548-1595) - He is the poet laureate of Akbar's Court, who has written a number of books which include: Sawati al-Ilham and Mawaridul Kalam

(written without dotted letters).

* Abdul Haque of Delhi (1551-1642) - He is credited with spread of Hadith in India and wrote the famous book Lam'at al-Tanquih.

* Shaikh Ahmad Sarhindi (1564-1624) - He is known as Mujaddid-i-alf-i-thani (reviver of the second millennium) who has penned al-Risala al-Tahliliya.

* Ali ibn Husamuddin (d. 1480) - He has written the all-time famous book Kanzul Ummal.

There are about twenty thousand madrasas in our India where modern education is being offered in Arabic. They are playing active part in contributing of Arabic language and literature in India. Some of them are as :

1. Darul Uloom, Deoband, UP.
2. Darul Uloom Nadvatul Ulema, Lucknow, UP.
3. Al-Jamiatus Salafiah (Markazi Darul Uloom), Varanasi, UP.
4. Madrasa Mazahirul Uloom, Saharanpur, UP
5. Jamia Islamia Sanabil, New Delhi.
6. Madarsatul Islah, Saraimir, Azamgarh, UP.
7. Jamiatul Falah, Bilariaganj, Azamgarh, UP.
8. Jamiatur Rashad, Azamgarh, UP.

Besides this, there are more than 40 universities in India where Arabic language is being taught in addition to a number of colleges in some states such as Kerala, West Bengal, Assam and Kashmir.

Importance

Arabic is the official language of over 23 countries and there are well over 400 million native speakers of the language. These speakers are largely concentrated in the Middle East, but there are also other native speakers of Arabic throughout the world. There is a high demand and low supply of Arabic-speakers. With the growing importance of the Middle East in international affairs, and the extreme shortage of United Nations staff who are versed in the Arabic language and culture. Those who study Arabic might better their chances to work in the different missions and offices in the Arab world. It is a language of strategic importance. The US government has designated Arabic as a language of strategic impor-

tance. This is to speak about the growing need for proficient speakers of the language. Just think of how many offices and missions are now in The Arab country. Knowing Arabic can promote intercultural understanding. Events in the Middle East affect our daily lives and work at the United Nations. Being unaware of the language and culture might lead to mistrust and miscommunication, and to an inability to cooperate.

India has traditionally enjoyed close and friendly relations with Arab countries. These relations date back to ancient times. There are important Indian investments in countries stretching from Oman to Egypt, Sudan and beyond. There have been cultural ties with the region throughout history. Much of our external trade passes along the Suez. Arabic is the oldest foreign language in India today. The reason is that its entry into the country dated back to the seventh century of the Christian era. The language ,at present ,is no longer confined to the Islamic Institutions and seminars and is no longer considered to be the language of any religion only .With the globalization of business, the world becoming more and more a global village, the need for transactional knowledge languages has become very important in both private and govt. sectors .Keeping in view the demand of languages Arabic language has been adopted in many universities and colleges.

In day to days life ,Arabic language is of utmost importance due to the economic significance of the oil producing Arabian Countries in the global scenario . There is unemployment in our India .One of the major remedial measure to get rid of unemployment is to learn the language. Learning the language can open doors to employment in the oil producing countries .Knowing the language can help us to find a career in different fields such as journalism ,business, industry, education ,finance and banking ,translation and interpretation ,consulting, foreign service etc.so Arabic helps in international trade and industry .It leads to better understanding between the different nations of the world. A person knowing Arabic stands opportunities of employment in every Arabian country.

The language has played a key role in the Islamic faith .It is the language of the Holy Quran . The followers of the religion holds the importance of Arabic in very high esteem .The holy prophet Muhammad (S.A,W) says that Love Arabs for three reasons - I myself an Arab, the holy Quran is in Arabic, and the language of the inhabitants of paradise

is too Arabic. There are about twenty corer Muslims in our India so it has also great religious importance here in India .They considered it as the divine gift and a sacred part of their customs . All the primary sources of Islam are in Arabic language .So from Islamic educational point of view ,Arabic played a prominent role in the past .It was the medium of instruction .Higher education in science ,medical ,engineering ,philosophy, art and literature,hadith and Islamic jurisprudence was not possible without Arabic .Even now advanced studies of many areas of Islam are not possible without the knowledge of Arabic language .Good books of Islamic literature are available in Arabic only .many of them has been translated into Indian languages also but our languages have not been developed enough to meet the demands of the difficult subjects .So if Indian inhabitants decide to give up Arabic altogether ,they would cut themselves off from the living stream of ever growing knowledge.

There are many scopes for Arabic learners in both private and government sectors. The government sector may include, but is not limited to, Foreign Service, embassies, cultural attaches' and diplomatic services, intelligence, tourism and so on. The private sector may include jobs in international organizations, mass communication, publishing, entertainment, education, interpretation and translation, business and industry, finance and banking and such others. These days, the Arabic language is becoming an important language when it comes to operating an international business that is trying to break into foreign markets. Some businesses want Arabic speakers on-board specifically to contact local Arabic people and to obtain an edge when running a business that might otherwise end up being missed, using only English interpretation and discussions. Arabic speakers have also been in high demand by the CIA and FBI for those on-going conflicts in Iraq as well as Afghanistan .Apart from this, knowledge of Arabic can also augment career prospects in various other fields as a result of the expansion of markets and business outsourcing.

Conclusion

The study of the Arabic language should not become the monopoly of some people or of one section of the Indian people, but should be studied by all those who are interested in gaining a better knowledge of the social, economic or political conditions of the Arab world

today, or want to study its glorious past history and philosophy, or wants to wipe out unemployment. In nutshell I am of the opinion that Arabic should be taught as a living language in the country due to its vital role in the development of our India.

References

- (1) Allen Roger: The Arabic Literary Heritage, Cambridge University Press 2006
- (2) Ahmad, Dr. Ashfaq: Musahamatul-Hind Fi al-Nathr al-Arabi Khilala al-Qarn al-Ishreen, New Delhi, Makoff printers, 2000.
- (3) Deshai, Ziyauddin A: Centres of Islamic Learning in India, New Delhi, 1978.
[https://www.google.co.in/url?url=Study of the Arabic language is essential from the viewpoint of sociohistorical, cultural, job opportunities as well as Indo-Arab relationship. From cultural point of view learning Arabic to a limited extent is an obligatory duty for every Muslim in order to performing unavoidable religious \(1\)duty in day to day life.](https://www.google.co.in/url?url=Study%20of%20the%20Arabic%20language%20is%20essential%20from%20the%20viewpoint%20of%20sociohistorical,%20cultural,%20job%20opportunities%20as%20well%20as%20Indo-Arab%20relationship.%20From%20cultural%20point%20of%20view%20learning%20Arabic%20to%20a%20limited%20extent%20is%20an%20obligatory%20duty%20for%20every%20Muslim%20in%20order%20to%20performing%20unavoidable%20religious%20(1)duty%20in%20day%20to%20day%20life.)

THE IMPACT OF QURAN ON ARABIC LITERATURE

SYED MOHD AMIN SHAH BUKHARI.

Research Scholar (Dep. of Arabic)
Barkatullah University Bhopal. M.P.

Abstract: (The Quran has a great impact on Arabic language & literature. It refines expressions, united the various dialects and spreads the language East and West with the spread of Islam. Its eloquence is so fascinating that multitude of people had to commit it to memory and derive joy its recitation liturgically and for other purposes. Its style influenced Arab men of letters in other ways. These impacts are glaring in both their poetical and prose compositions most especially in oration).

Since the advent of Islam and the revelation of the Quran in the early years of the seventh century A.D., the muslim Holy Book has been the subject of many extensive analytical studies. The Quran is truly a unique expression of the Arabic language. Nothing has changed before or after it that can match its literary form and style. The Quran became the central work of study and recitation. Extra Quranic poetry underwent a decline from which it recovered in a far different form. The Quran has been the ultimate source of legal authority for muslims over the past fourteen centuries. Before the rise of Islam, Arabic was mainly a spoken language with an oral literature of elaborate poetry and to a lesser extent prose. The poets who did not accept Islam focussed on themes other than religion but they did not focus on paganism either since this theme lost its appeal to most of Arabs already.

One of the new themes according to H.A.R. Gibb, is the parallel theme, which is described as theatrical display of ingenuity and virtuosity, apart from a somewhat monotonous repertoire of personal taunts and indencies".

The Quran had a significant influence on the Arab language. The Quran contains elements of both prose and poetry, and therefore is closest to Saj or rhymed prose, the Quran is regarded as entirely apart from these classifications. As a literary monument the Quran thus stands by itself a production unique in Arabic literature, having neither forerunners nor successors in its own idiom. The influence of the Quran on the development of the Arabic literature has been incalculable, and exerted in many directions. Its deals, its language, its rhythms pervade all subsequent literary works in greater or lesser measure. The Quran has without doubt provided a level of linguistic excellence unparalleled in the history of Arabic language. Theologians explain this phenomenon as God's wisdom in addressing the articulate Arabs through the medium in which they were most adept and with which they felt most comfortable. The effortiveness of the Quran was thus ensured by the fact that it represented a level of elequence unattainable even by their most elequent speakers. The Quran remains a book of inimitable quality, not only from a linguistic, but also from an intellectual point of view.1

Following the writting of the Quran, the classical form of Arabic poetry were adapted to extol Islam and its rulers. One such form was panegeric, which praised important personages such as Caliphs, Theologians and Philosophers. Another was the Lampoon, which mocked and shamed enemies. A third was the elegy, which honored the dead. Though these literary forms exists before the advent of Islam, the revelation and transmission of the Quran changed the form and content of their expression.2

Thematically, the Quran very much influenced Islamic poetry. First especially, when it comes to praising Allah, the Prophet and the Sahabah....This is no more pronounced in poetry about the Prophet... in Surah al- Ahzab, the Quran says in meaning, Allah and his Angels say "Salat' on him ...The praising of Allah and his Angels of not only the Prophet but also of the Sahabah influenced the Islamic Poetry a lot... of course, the poets wrote a lot abiuot other topics... but, there developed a special type of poetry, called Na'at, dedicated

fully to praising the Prophet....³ Some Quran stories also became a common theme in Islamic Literature.... the most famous one is the story of yousf and zulaeykha, which became a folk tale...inspired by the Quran, this story is often described as the most beautiful story.

The most obvious reason why the Quran is considered important in Arabic literature is its contribution to a gradual increase in the number of themes. I.M.Filshtinsky noted that the poets who adopted Islam created poems glorifying the new faith. In this case, religion became one of the new themes in Arabic poetry. It is clear to see that with the help of Islam, Arabic literature was already progressing from its roots. Despite the fact that they were isolated from foreign cultures, the Arabs were able to develop Arabic literature on their own. The message of Islam is pragmatic one, which reaffirmed some ancient Arabian practices and totally condemned some others. Its claim to universality would naturally discourage tribalism, tribal pride and inter-tribal feuds for which the Arabs were well known. Similarly its insistence on decent speech discouraged indiscriminate use of satires which the seriousness of the message and the task of building a community of true believers discouraged making a living out of poetry through praise saying or lampooning of opponents.² The concepts, style and language of the Quran are all, in themselves, wonderful and inimitable. The style, language and literature of the Quran are all unparalleled; all beyond imitation; one all in their refined beauty, exquisite. The revelation of the Quran and the Prophetic expositions also introduced new words into the Arabic language and soften up the expressions of the language.

In the light of the above, it can be said that while Islam expanded the Arabic literary arts in one way, it also reduced the scope of some literary genres in another way. The Quran thus came in a language purer than any they had known, with a distinct style unmatched in the history of languages. It also challenged the Arabs to produce its like if they could. The Quran declares, in the surah Asr'a, 88:

" Say (O, Muhammad Sulla Iahoi alaihi wasalm), if mankind and Jin gathered together to produce the like of this Quran, they would not be able to produce the like thereof, even though they should help one another; Q.17:88.

The Quran states: " If you are in doubt of what we have revealed to our messenger, then

produce one chapter like it, call upon all your helpers, besides Allah, if you are truthful." Surah al-Baqarah (the Heifer) 2:23.

" Or do they say: " He (Prophet Muhammad) has forged it (this Quran)?" Nay! They believe not! Let them then produce a recitation like it (the Quran) if they are truthful." Surah al-Toor (the Mount) 52: 33-34.

According to the Quranic commentators such as Ibn Kathir, Suyuti and ibn Abas, these verses issue a challenge to produce a chapter that imitates the unique literary form of the Quran. 4

The artistic and semantic beauty of the Quran and its inimitability had been a subject of discourse from the early part of the Prophet's mission till today. The other impact on language is that the Arabic grammar was founded for its sciences, to guard against corruption in its recitation; Also, the science of Arabic rhetoric was formulated in search of the secret behind its inimitability. Islamic sciences emerged right after the introduction of the Quran to the people in the second half of the first century Hijra. The prose of the Islamic period drew its major impulse from the Quranic message and Prophetic utterances. So Arabic language is highly indebted to its literature and the Quran in its life. The Quran, however, is a book of relatively small bulk, and there are large areas of speech which simply do not happen to occur there, yet are of importance, as they constitute the linguistic matrix within which the Quranic text operates and has to be understood. To gain such an understanding, the grammarians turned to orally inherited traditions of the ancient poetry, and to speech of the bedouin with whom they could come into contact.⁵ Arabic grammar is considered to be the most significant of them all.

The Holy Quran helped promote the status and development of Arabic linguistics. Classical scholars such as al-Baqillani and al-Rumani view the Quran as having its own unique literary form. This view is also supported by western scholarship orientalisists such as Arthur J. Aberny, Professor Bruce Lawrence and D.J Stewart. Every expression of the Arabic language falls into the literary forms of prose and poetry.

References :-

1. Elsayed M. H. Omran,--- Islam, the Quran and the Arabic literature, vol. 14,

No.1-spring 1988.

2. Prof. A. F. Ahmad and team,--- Arabic literatures-1, National Open University of Nigeria. 2010.

3. UK essays, Islamic literary Poetry, published on 23rd March 2015.

4. Tafsir ibn Kathir, Tafsir ibn Qurtabi, Tafsir ibn Jalalyn and Mā'riful Quran.

5. A. F. L. Beeston, T. M. Johnson, R. B. Serjeant and G.R. Smith--- Arabic literature to the End of the Umayyad Period, Cambridge University Press-1983. p5

For further readings:-

i. M. S. Rafei--- History of Arab Literature. Beirut : Dar Books.

Scientific- 2000

ii. O, Faroukh,--- History of arab literature. Beirut : Dar al-Ilm of malaiin-1984

iii. M. F. Hijazi,--- Learning the Arabic Language . Cairo, Strange Library , 1992

iv. A. Mokram Salem ---The Arabic Language in the Holy Koran Rehab. Kuwait , the world of books -1995.

MAHMUD DARWISH, DISTINGUISHING FEATURES OF HIS POETRY

MUKHTAR AHMAD

Research scholar (Deptt. Of Arabic)
BU Bhopal

Abstract:-

Mahmud Darwish is one of the prominent contemporary poets who wrote about Palestine and intifada and protected his nation's identity. Palestine has given birth to poets in its soil but no one got the popularity in defending his nation except Darwish. He raised his voice internationally, particularly in Islamic countries, when he was residing in refugee camps in his own motherland. He participated in political struggle of Palestine in his early youth.

He was detained many a times and has written numerous books in detention. His poetry awakened people from slumber and negligence to struggle against occupying Zionist. His poetry is all revolving around the central motif of Palestinian yearning for independence and the Palestine issue.

Since many years I have been thinking over the occupation, the disaster, the tragedy, the mishap, the misfortune which afflict Muslims in occupied Palestine, I desire to study various books about the Palestine issue and Jews who usurp Al Qudus and implant malicious plants there. After participating in many territorial and international conferences, I plug to write an article about Palestine issue, even though my eyes captured a big name of a great poet

Mahmud Darwish, who declared his mission as the protection of Palestine identity and devoted his life for his occupied Palestine.

About Poet:-

Mahmud Darwish was born on 13th March 1941 in a small hamlet, which lies on the distance of 9 km's from eastern Uka called "Albirwa". The village with a population of 2000 has set a history by resisting against the occupation at earliest. His father Saleem Darwish was a simple farmer, had nothing in his possession. Mahmud Darwish described it in his poetic anthology in the poem "Identity Card".

Write down!

I am an Arab

My father... descends from the family of the plow
not from a privileged class
and my grandfather... was a farmer
neither well-bred, nor well-born!

Her mother was from a village called "Al-Dimwan" near Al-nasirah. Her father a regional writer and village chief left her illiterate. Darwish is a poet from a family which consists of 8 sons, children and three daughters and he is second son in the family who migrated to Lebanon.

His Literal life: - Mahmud Darwish achieved primary education from a school at Al-awnarwa in Al-Damwara Lebanon. He was reading in 2nd standard, when he returned back to his motherland Palestine and his new village, Dair-al-Asad. The poet says he was very affectionate to Arabic literature and had imitated post-Islamic poetry in his foremost poetic attempts.

He spoke about this topic in an interview of journalist with Majal-atilam.

I am influenced with many poets and I expressed it always, I am the son of jahli poetry and son of Abu Taaib Al Mutanabi and I am the son of poetry of twentieth century developed in the western world. During his presence in Palestine he lived in the region of Galel and worked as part-time in the editorial of daily magazine (ALITHAD) published by Hizb-Rakah in 1971. Darwish left Palestine and went to Beirut where he got enormous popularity

with the attribute of first resistance poet in numerous Arabic countries. After leaving Beirut in the year 1982, he visited Paris then Qubrus and took the charge of editorial of journal (Akermaal) in the years of eighties and in the beginning of nineties which stopped and later republished from Ram-ullah, Palestine in the beginning of the year 1997.

Political life: - Darwish lived as a refugee in his motherland and participated in the political struggle in his early youth and joined communist party of Israel, Rakah. Darwish faced harassment and continuous repression by the hands of Israeli authorities. He was imprisoned many a times. In 1961 he was first time detained when he moved from village (Al-Jadceah) to live alone in Hayfa city in 1960. He was arrested by Israeli police from his home without any reason. Darwish says about his first custody in jail "the first detention is like the love which cannot be forgotten". Mahmud Darwish was detained second time in 1965 for the reason of travelling to Al-Qudus from Hayfa without permit. It was the time when every Arab was incumbent to have special permission to move from one place to another in their homeland. He was again arrested when Arab students organized poetic evening in Hebrew university, where Darwish went to participate in this evening and delivered his famous poem "song for the man" which he later published in his poetic anthology "a lover from Palestine".

He speaks always about his detention in his poem "The Prison Cell".

It is possible...

It is possible at least sometimes...

It is possible especially now

To ride a horse

Inside a prison cell

And run away...

It is possible for prison walls

To disappear,

For the cell to become a distant land

Without frontiers:

His books:-He wrote various books in prose and poetry. His poetic work reached to 30

collections.

His struggle and poetry: - Mahmud Darwish is poet of love, poet of motherland, poet of nation, poet of occupied land and the poet of Palestine. He was the warrior in the vanguard of warriors. I believe the Jihad has many types and the jihad is not done only by carrying weapons but the pen and statement is more penetrating than liquidating pearls and callous swords and greater than destructive bombs. When he says in the praise of stretched shadow in a warm and catching voice.

Darwish loved his motherland, Palestine with all sentiments and emotions. His poetry represents a true artistic expression of poet's and his countrymen's tragedy is a heart touching expression which injury the body and appeals the mind of those who had never heard anything about Palestine turmoil.

Darwish says: - we are afflicted with crises, not only in our nation and in our dwelling places but we face crises in our graves. A Palestine doesn't know where he is to be buried. This is sufficient that we don't possess right to life in our nation and in exile and we don't have the address to our corpse.

I confess that Darwish has been everything in Palestine and described it all. The love of Palestine is engraved in his heart and mind which never died and weakened with changing circumstances and situations. He was forced to get segregated from his motherland but its love remained hidden in his heart wherever he lived. Palestine is his final beloved, he says-

Put it on record.

I am an Arab.

Color of hair: jet black.

Color of eyes: brown.

My distinguishing features:

On my head the 'iqal cords over a keffiyeh

Scratching him who touches it.

My address:

I'm from a village, remote, forgotten,

Its streets without name

And all its men in the fields and quarry.

What's there to be angry about?

Finally I would say Darwish is a poet of cause, a tragedy, a fiasco, a calamity. We feel his beloved and nation are twins in his poetry and he never thought them two. So the love is firmly connected with his land and cause

Bibliography:-

1. Prince of Poets", The American Scholar.
2. Mahmud Darwish Biography by Sameh Al-Natour.
3. Memory for Forgetfulness: August, Beirut, 1982 By Mahmoud Darwish; Ibrahim Muhawi
4. Darwish's Essentialist Poetics in a State of Siege By Sylvain, Patrick
5. Mahmoud Darwish: 1942-2008 By Arab Studies Quarterly (ASQ).
6. Mahmoud Darwish: Palestine's Poet of Exile By Handal, Nathalie
7. Ashiq min filastin (A lover from Palestine), 1966
8. Awraq Al-Zaytun (Leaves of olives), 1964 .
9. al-Nasheed al-jasadi (The bodily anthem), 1980
10. Habibati tanhad min nawmiha (My beloved awakens), 1969

ENVIRONMENT

D.N. YADAV

Asst. Professor

Govt. College Nasrullaganj M.P.

Environment is living things and what is around them. It can be living or non-living things. It includes physical, chemical and other natural forces. Living things do not simply exist in their environment. They constantly interact with it. Organisms change in response to conditions in their environment. In the environment there are interactions between plants, animals, soil, water, temperature, light, and other living and non-living things.

The word 'environment' is used to talk about many things. People in different fields of knowledge (like history, geography or biology) use the word differently. An electromagnetic environment is the radio waves and other radiation and magnetic fields. The galactic environment refers to conditions between the stars.

In psychology and medicine a person's environment is the people, physical things, places, and events that the person lives with. The environment affects the growth and development of the person. It affects the person's behavior. It affects the person's body, mind and heart.

• In biology and ecology, the environment is all of the natural materials and living things, including sunlight. This is also called the natural environment. Some people call themselves environmentalists. They think we must protect the environment, to keep it safe. Things in the natural environment that we value are called natural resources. For example, fish, sun-

light, and forests. These are renewable resources because they come back naturally when we use them. Non-renewable resources are important things in the environment that are limited for example, ores and fossil fuels. Some things in the natural environment can kill people, such as lightning.

Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. While all living elements- the birds, animals, plants, fisheries etc.-are biotic elements, abiotic elements include air, water, sunlight etc. A study of the environment then calls for a study of the inter-relationship between these biotic and abiotic components of the environment.

Historical environment

Environment is the events and culture that a person lived in. A person's beliefs and actions are dependent on his environment. For example, Thomas Jefferson and Julius Caesar owned slaves. Modern people mostly think it's wrong to own slaves. But in Jefferson's and Caesar's environments slavery was normal. So, their actions did not look as wrong in their societies.

The natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally. The term is most often applied to the Earth or some part of Earth. This environment encompasses the interaction of all living species, climate, weather, and natural resources that affect human survival and economic activity. The concept of the natural environment can be distinguished by components:

Complete ecological units that function as natural systems without massive civilized human intervention, including all vegetation, microorganisms, soil, rocks, atmosphere, and natural phenomena that occur within their boundaries and their nature

Universal natural resources and physical phenomena that lack clear-cut boundaries, such as air, water, and climate, as well as energy, radiation, electric charge, and magnetism, not originating from civilized human activity

In contrast to the natural environment is the built environment. In such areas where man has fundamentally transformed landscapes such as urban settings and agricultural land conversion, the natural environment is greatly modified into a simplified human environment.

Even acts which seem less extreme, such as building a mud hut or a photovoltaic system in the desert, modify the natural environment into an artificial one. Though many animals build things to provide a better environment for themselves, they are not human, hence beaver dams and the works of Mound-building termites are thought of as natural.

It is difficult to find absolutely natural environments on Earth, and naturalness usually varies in a continuum, from 100% natural in one extreme to 0% natural in the other. More precisely, we can consider the different aspects or components of an environment, and see that their degree of naturalness is not uniform. [2] If, for instance, in an agricultural field, the mineralogic composition and the structure of its soil are similar to those of an undisturbed forest soil, but the structure is quite different.

The Earth's crust, or lithosphere, is the outermost solid surface of the planet and is chemically and mechanically different from underlying mantle. It has been generated greatly by igneous processes in which magma cools and solidifies to form solid rock. Beneath the lithosphere lies the mantle which is heated by the decay of radioactive elements. The mantle though solid is in a state of rheic convection. This convection process causes the lithospheric plates to move, albeit slowly. The resulting process is known as plate tectonics. Volcanoes result primarily from the melting of subducted crust material or of rising mantle at mid-ocean ridges and mantle plumes.

An ocean is a major body of saline water, and a component of the hydrosphere. Approximately 71% of the Earth's surface (an area of some 362 million square kilometers) is covered by ocean, a continuous body of water that is customarily divided into several principal oceans and smaller seas. More than half of this area is over 3,000 meters (9,800 ft) deep. Average oceanic salinity is around 35 parts per thousand (ppt) (3.5%), and nearly all seawater has a salinity in the range of 30 to 38 ppt. Though generally recognized as several 'separate' oceans, these waters comprise one global, interconnected body of salt water often referred to as the World Ocean or global ocean. The deep seabeds are more than half the Earth's surface, and are among the least-modified natural environments. The major oceanic divisions are defined in part by the continents, various archipelagos, and other criteria: these divisions are (in descending order of size) the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian

Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean.

A river is a natural watercourse, usually freshwater, flowing toward an ocean, a lake, a sea or another river. In a few cases, a river simply flows into the ground and dries up completely before reaching another body of water. Small rivers may also be termed by several other names, including stream, creek and brook. In the United States a river is generally classified as a watercourse more than 60 feet (18 metres) wide. The water in a river is usually in a channel, made up of a stream bed between banks. In larger rivers there is also a wider floodplain shaped by waters over-topping the channel. Flood plains may be very wide in relation to the size of the river channel. Rivers are a part of the hydrological cycle. Water within a river is generally collected from precipitation through surface runoff, groundwater recharge, springs, and the release of water stored in glaciers and snowpacks.

A stream is a flowing body of water with a current, confined within a bed and stream banks. Streams play an important corridor role in connecting fragmented habitats and thus in conserving biodiversity. The study of streams and waterways in general is known as surface hydrology. Types of streams include creeks, tributaries, which do not reach an ocean and connect with another stream or river, brooks, which are typically small streams and sometimes sourced from a spring or seep and tidal inlets

A lake (from Latin lacus) is a terrain feature, a body of water that is localized to the bottom of basin. A body of water is considered a lake when it is inland, is not part of an ocean, and is larger and deeper than a pond.

Natural lakes on Earth are generally found in mountainous areas, rift zones, and areas with ongoing or recent glaciation. Other lakes are found in endorheic basins or along the courses of mature rivers. In some parts of the world, there are many lakes because of chaotic drainage patterns left over from the last Ice Age. All lakes are temporary over geologic time scales, as they will slowly fill in with sediments or spill out of the basin containing them.

A pond is a body of standing water, either natural or man-made, that is usually smaller than a lake. A wide variety of man-made bodies of water are classified as ponds, including water gardens designed for aesthetic ornamentation, fish ponds designed for commercial fish breeding, and solar ponds designed to store thermal energy. Ponds and lakes are distin-

guished from streams by their current speed. While currents in streams are easily observed, ponds and lakes possess thermally driven micro-currents and moderate wind driven currents. These features distinguish a pond from many other aquatic terrain features, such as stream pools and tide pools.

The atmosphere of the Earth serves as a key factor in sustaining the planetary ecosystem. The thin layer of gases that envelops the Earth is held in place by the planet's gravity. Dry air consists of 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% argon and other inert gases, such as carbon dioxide. The remaining gases are often referred to as trace gases, among which are the greenhouse gases such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. Filtered air includes trace amounts of many other chemical compounds. Air also contains a variable amount of water vapor and suspensions of water droplets and ice crystals seen as clouds. Many natural substances may be present in tiny amounts in an unfiltered air sample, including dust, pollen and spores, sea spray, volcanic ash, and meteoroids. Various industrial pollutants also may be present, such as chlorine (elementary or in compounds), fluorine compounds, elemental mercury, and sulphur compounds such as sulphur dioxide [SO₂].

The ozone layer of the Earth's atmosphere plays an important role in depleting the amount of ultraviolet (UV) radiation that reaches the surface. As DNA is readily damaged by UV light, this serves to protect life at the surface. The atmosphere also retains heat during the night, thereby reducing the daily temperature extremes.

Earth's atmosphere can be divided into five main layers. These layers are mainly determined by whether temperature increases or decreases with altitude. From highest to lowest, these layers are:

Exosphere: The outermost layer of Earth's atmosphere extends from the exobase upward, mainly composed of hydrogen and helium.

Thermosphere: The top of the thermosphere is the bottom of the exosphere, called the exobase. Its height varies with solar activity and ranges from about 350–800 km (220–500 mi; 1,150,000–2,620,000 ft). The International Space Station orbits in this layer, between 320 and 380 km (200 and 240 mi).

Mesosphere: The mesosphere extends from the stratopause to 80–85 km (50–53 mi;

262,000–279,000 ft). It is the layer where most meteors burn up upon entering the atmosphere. Stratosphere: The stratosphere extends from the tropopause to about 51 km (32 mi; 167,000 ft). The stratopause, which is the boundary between the stratosphere and mesosphere, typically is at 50 to 55 km (31 to 34 mi; 164,000 to 180,000 ft).

Troposphere: The troposphere begins at the surface and extends to between 7 km (23,000 ft) at the poles and 17 km (56,000 ft) at the equator, with some variation due to weather. The troposphere is mostly heated by transfer of energy from the surface, so on average the lowest part of the troposphere is warmest and temperature decreases with altitude. The tropopause is the boundary between the troposphere and stratosphere.

The ozone layer is contained within the stratosphere. It is mainly located in the lower portion of the stratosphere from about 15–35 km (9.3–21.7 mi; 49,000–115,000 ft), though the thickness varies seasonally and geographically. About 90% of the ozone in our atmosphere is contained in the stratosphere.

The ionosphere, the part of the atmosphere that is ionized by solar radiation, stretches from 50 to 1,000 km (31 to 621 mi; 160,000 to 3,280,000 ft) and typically overlaps both the exosphere and the thermosphere. It forms the inner edge of the magnetosphere.

The homosphere and heterosphere: The homosphere includes the troposphere, stratosphere, and mesosphere. The upper part of the heterosphere is composed almost completely of hydrogen, the lightest element.

The planetary boundary layer is the part of the troposphere that is nearest the Earth's surface and is directly affected by it, mainly through turbulent diffusion.

Effects of global warming

The Retreat of glaciers since 1850 of Aletsch Glacier in the Swiss Alps (situation in 1979, 1991 and 2002), due to global warming.

Main article: Effects of global warming

The potential dangers of global warming are being increasingly studied by a wide global consortium of scientists. These scientists are increasingly concerned about the potential long-term effects of global warming on our natural environment and on the planet. Of particular concern is how climate change and global warming caused by anthropogenic, or human-

made releases of greenhouse gases, most notably carbon dioxide, can act interactively, and have adverse effects upon the planet, its natural environment and humans' existence. It is clear the planet is warming, and warming rapidly.—This warming is also responsible for the extinction of natural habitats, which in turn leads to a reduction in wildlife population. The most recent report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (the group of the leading climate scientists in the world) concluded that the earth will warm anywhere from 2.7 to almost 11 degrees Fahrenheit (1.5 to 6 degrees Celsius) between 1990 and 2100.[13] Efforts have been increasingly focused on the mitigation of greenhouse gases that are causing climatic changes, on developing adaptive strategies to global warming, to assist humans, other animal, and plant species; ecosystems, regions and nations in adjusting to the effects of global warming. Some examples of recent collaboration to address climate change and global warming include:

The United Nations Framework Convention Treaty and convention on Climate Change, to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.[14]

The Kyoto Protocol, which is the protocol to the international Framework Convention on Climate Change treaty, again with the objective of reducing greenhouse gases in an effort to prevent anthropogenic climate change.[15]

The Western Climate Initiative, to identify, evaluate, and implement collective and cooperative ways to reduce greenhouse gases in the region, focusing on a market-based cap-and-trade system.

A significantly profound challenge is to identify the natural environmental dynamics in contrast to environmental changes not within natural variances. A common solution is to adapt a static view neglecting natural variances to exist. Methodologically, this view could be defended when looking at processes which change slowly and short time series, while the problem arrives when fast processes turns essential in the object of the study.

Map of world dividing climate zones, largely influenced by latitude. The zones, going from the equator upward (and downward) are Tropical, Dry, Moderate, Continental and Polar. There are subzones within these zones.

An ecosystem (also called as environment) is a natural unit consisting of all plants, animals and micro-organisms (biotic factors) in an area functioning together with all of the non-living physical (abiotic) factors of the environment.[26]

Central to the ecosystem concept is the idea that living organisms are continually engaged in a highly interrelated set of relationships with every other element constituting the environment in which they exist. Eugene Odum, one of the founders of the science of ecology, stated: "Any unit that includes all of the organisms (ie: the "community") in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic diversity, and material cycles (i.e.: exchange of materials between living and nonliving parts) within the system is an ecosystem." [27]

The human ecosystem concept is then grounded in the deconstruction of the human/nature dichotomy, and the emergent premise that all species are ecologically integrated with each other, as well as with the abiotic constituents of their biotope.

A greater number or variety of species or biological diversity of an ecosystem may contribute to greater resilience of an ecosystem, because there are more species present at a location to respond to change and thus "absorb" or reduce its effects. This reduces the effect before the ecosystem's structure is fundamentally changed to a different state. This is not universally the case and there is no proven relationship between the species diversity of an ecosystem and its ability to provide goods and services on a sustainable level.

The term ecosystem can also pertain to human-made environments, such as human ecosystems and human-influenced ecosystems, and can describe any situation where there is relationship between living organisms and their environment. Fewer areas on the surface of the earth today exist free from human contact, although some genuine wilderness areas continue to exist without any forms of human intervention.

Climate encompasses the statistics of temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, rainfall, atmospheric particle count and numerous other meteorological elements in a given region over long periods of time.[citation needed] Climate can be contrasted to weather, which is the present condition of these same elements over periods up to two weeks.[citation needed]

References :

Johnson, D. L.; Ambrose, S. H.; Bassett, T. J.; Bowen, M. L.; Crummey, D. E.; Isaacson, J. S.; Johnson, D. N.; Lamb, P.; Saul, M.; Winter-Nelson, A. E. (1997). "Meanings of Environmental Terms". *Journal of Environmental Quality*. 26 (3): 581–589. doi:10.2134/jeq1997.00472425002600030002x.

Symons, Donald (1979). *The Evolution of Human Sexuality*. New York: Oxford University Press. p. 31. ISBN 0-19-502535-0.

Earth's Spheres. ©1997-2000. Wheeling Jesuit University/NASA Classroom of the Future. Retrieved November 11, 2007.

Wordnet Search: Earth science[dead link]

"[1]". *The Columbia Encyclopedia*. 2002. New York: Columbia University Press

"Distribution of land and water on the planet Archived May 31, 2008, at the Wayback Machine.". *UN Atlas of the Oceans* Archived September 15, 2008, at the Wayback Machine.

River {definition} from Merriam-Webster. Accessed February 2010.

<http://ga.water.usgs.gov/edu/hydrology.html/> Archived August 13, 2009, at the Wayback Machine.

Brittanica online. "Lake (physical feature)". Retrieved 2008-06-25. "[a Lake is] any relatively large body of slowly moving or standing water that occupies an inland basin of appreciable size. Definitions that precisely distinguish lakes, ponds, swamps, and even rivers and other bodies of nonoceanic water are not established. It may be said, however, that rivers and streams are relatively fast moving; marshes and swamps contain relatively large quantities of grasses, trees, or shrubs; and ponds are relatively small in comparison to lakes. Geologically defined, lakes are temporary bodies of water."

HISTORY OF SCINDIA'S

D.S. PAWAR

Asst. Professor History

Govt. College Nasrullaganj M.P.

The Scindia dynasty was founded by Ranoji Scindia, who was the son of Jankojirao Scindia, the Deshmukh of Kanherkhed, a village in Satara District, Maharashtra. Peshwa Baji Rao's career saw the strengthening of the Maratha Empire. Ranoji was in charge of the Maratha conquests in Malwa in 1726. Ranoji established his capital at Ujjain in 1731. His successors included Jayajirao, Jyotibarao, Dattajirao, Jankojirao, Mahadji Shinde and Daulatrao Scindia. The Scindia state of Gwalior became a major regional power in the latter half of the 18th century and figured prominently in the three Anglo-Maratha Wars. They held sway over many of the Rajput states, and conquered north India.

After the defeat of the allied Maratha states by the British in the Third Anglo-Maratha War of 1818, Daulatrao Scindia was forced to accept local autonomy as a princely state within British India and to give up Ajmer to the British. After the death of Daulatrao, Maharani Baiza Bai ruled the empire, saving it from the British power, till the adopted child Jankoji Rao took over the charge. Jankoji died in 1843, and his widow Tarabai Raje scindia successfully maintained the position and adopted a child from close lineage named Jayajirao.

The Scindia family ruled Gwalior until India's independence from the United Kingdom in 1947, when the Maharaja Jivajirao Scindia acceded to the Government of India. Gwalior

was merged with a number of other princely states to become the new Indian state of Madhya Bharat. George Jivajirao served as the state's rajpramukh, or appointed governor, from 28 May 1948 to 31 October 1956, when Madhya Bharat was merged into Madhya Pradesh.

In 1962, Rajmata Vijayaraje Scindia, the widow of Maharaja Jiwajirao, was elected to the Lok Sabha, beginning the family's career in electoral politics. She was first a member of the Congress Party, and later became an influential member of the Bharatiya Janata Party. Her son Madhavrao Scindia was elected to the Lok Sabha in 1971 representing the Congress Party, and served until his death in 2001. His son, Jyotiraditya Scindia, also in the Congress Party, was elected to the seat formerly held by his father in 2004.

Vijayaraje's daughters have supported the Bharatiya Janata Party. Vasundhara Raje Scindia contested and won five parliamentary elections from Madhya Pradesh and Rajasthan. Under the Vajpayee government from 1998 onwards, Vasundhara was in charge of several different ministries. In 2003 she led the Bharatiya Janata Party to its largest majority in Rajasthan, and became the state's Chief Minister. In 2013 again, she led Bharatiya Janata Party to a thumping win in the state of Rajasthan, winning over 160 out of the 200 seats in the assembly elections. Her other daughter, Yashodhara Raje Scindia, contested assembly elections from Shivpuri in Madhya Pradesh and won in 1998, 2003 and 2013 and also lokshabha 2004, 2009 from Gwalior. Upon the BJP's win in the state, she became the state's Minister for Tourism, Sports and Youth Affairs. Vasundhara's son Dushyant Singh entered the Lok Sabha in 2004 from Rajasthan.

In the course of their military service, the Shinde were bestowed numerous titles by the British Empire, which grew more elaborate with the passage of time:[citation needed]

1745: Shrimant Sardar (name) Shinde Bahadur (Brave Chief of the Shinde)

1745–1787: Meherban Shrimant Sardar (name) Shinde Bahadur (High and Brave Chief of the Shinde)

1787–1790: His Highness Maharajadhiraj Maharaja Sahib Subadar Shrimant (name) Shinde Bahadur Maharaja Shinde of Gwalior (His Highness the Great King over Kings, High and Brave Lord of the Shinde, Shinde King of Gwalior)

1790–1794: His Highness Ali Jah, Umdat ul-Umara, Farzand-i-Arjumand, Maharajadhiraj

Maharaja Sahib Subadar Shrimant (name) Shinde Bahadur, Shrinath, Mansur-i-Zaman, Naib ul-Istiqlal-i-Maharajadhiraj Sawai Madhav Rao Narayan, Maharaja Shinde of Gwalior (His Highness the Exalted Dignity, Pillar of the Nobility, Worthy Son, Great King over Kings and Lord Chieftain of the Brave Shinde, Lord of Fortune, Victorious of the Age, Permanent Deputy of the Peshwar, Shinde King of Gwalior)

1794–1827: His Highness Ali Jah, Naib Vakil-i-Mutlaq, Amir ul-Umara, Mukhtar ul-Mulk, Maharajadhiraj Maharaja Shrimant (name) Shinde Bahadur, Maharaja Shinde of Gwalior (His Highness the Exalted Dignity, Deputy Agent, Amir of Amirs, Agent of the Kingdom, Great King over Kings of the Brave Shinde, Shinde King of Gwalior)

1827–1845: His Highness Ali Jah, Umdat ul-Umara, Hisam us-Sultanat, Mukhtar ul-Mulk, Maharajadhiraj Maharaja Shrimant (name) Shinde Bahadur, Shrinath, Mansur-i-Zaman, Maharaja Shinde of Gwalior (His Highness the Exalted Dignity, Pillar of the Nobility, Sword of the Kingdom, Agent of the Kingdom, Great King over Kings of the Brave Shinde, Lord of Fortune, Victorious of the Age, Shinde King of Gwalior)

1845–1861: His Highness Ali Jah, Umdat ul-Umara, Hisam us-Sultanat, Mukhtar ul-Mulk, Azim ul-Iqtidar, Rafi-us-Shan, Wala Shikoh, Muhtasham-i-Dauran, Maharajadhiraj Maharaja Shrimant (name) Shinde Bahadur, Shrinath, Mansur-i-Zaman (His Highness the Exalted Dignity, Pillar of the Nobility, Sword of the Kingdom, Agent of the Kingdom, Chief of the Highest Authority, High in Prestige, Exalted in Dignity, Great Prince over Princes of the Brave Shinde, Lord of Fortune, Victorious of the Age)

1861–1901: His Highness Ali Jah, Umdat ul-Umara, Hisam us-Sultanat, Mukhtar ul-Mulk, Azim ul-Iqtidar, Rafi-us-Shan, Wala Shikoh, Muhtasham-i-Dauran, Maharajadhiraj Maharaja Shrimant (name) Shinde Bahadur, Shrinath, Mansur-i-Zaman, Fidvi-i-Hazrat-i-Malika-i-Mua'zzama-i-Rafi-ud-Darja-i-Inglistan (His Highness the Exalted Dignity, Pillar of the Nobility, Sword of the Kingdom, Agent of the Kingdom, Chief of the Highest Authority, High in Prestige, Exalted in Dignity, Great Prince over Princes of the Brave Shinde, Lord of Fortune, Victorious of the Age, Vassal of Her Majesty the Honoured and Exalted Queen of England)

1901–1952: His Highness Ali Jah, Umdat ul-Umara, Hisam us-Sultanat, Mukhtar ul-

Mulk, Azim ul-Iqtidar, Rafi-us-Shan, Wala Shikoh, Muhtasham-i-Dauran, Maharajadhiraj Maharaja Shrimant (name) Shinde Bahadur, Shrinath, Mansur-i-Zaman, Fidvi-i-Hazrat-i-Malik-i-Mua'zzam-i-Rafi-ud-Darjat-i-Inglistan (His Highness the Exalted Dignity, Pillar of the Nobility, Sword of the Kingdom, Agent of the Kingdom, Chief of the Highest Authority, High in Prestige, Exalted in Dignity, Great Prince over Princes of the Brave Shinde, Lord of Fortune, Victorious of the Age, Vassal of His Majesty the Honoured and Exalted King of England)

1952–1969: His Highness Ali Jah, Umdat ul-Umara, Hisam us-Sultanat, Mukhtar ul-Mulk, Azim ul-Iqtidar, Rafi-us-Shan, Wala Shikoh, Muhtasham-i-Dauran, Maharajadhiraj Maharaja Shrimant (name) Shinde Bahadur, Shrinath, Mansur-i-Zaman, Fidvi-i-Hazrat-i-Malika-i-Mua'zzama-i-Rafi-ud-Darja-i-Inglistan (His Highness the Exalted Dignity, Pillar of the Nobility, Sword of the Kingdom, Agent of the Kingdom, Chief of the Highest Authority, High in Prestige, Exalted in Dignity, Great Prince over Princes of the Brave Shinde, Lord of Fortune, Victorious of the Age, Vassal of Her Majesty the Honoured and Exalted Queen of England)

Shrimant Ranoji Scindia (1731-45) CE

Ranoji Scindia is considered by all accounts as the founder of the present house of Gwalior. He was a personal aide to the Peshwa Balaji Baji Rao but rose rapidly in his favour by his soldiery qualities. In 1726 he along with Malhar Rao Holkar and Udaji Pawar was given the right to collect Sardeshmuk in the Malwa districts and Ujjain became the capital of dominions of Ranoji scindia. Ranoji Rao's sons were Jayapa, Dattaji, Jotiba, Tukoji and Mahadji.

Shrimant Mahadji Scindia (1761-94) CE

Mahadji Scindia the last surviving male member of the line of Ranoji, was heavily wounded in the battle of Panipat. Mahadji Scindia took a leading part in many campaigns; for instance against Jats of Bharatpur and Rohillas and consolidated his powers. Mahadji Scindia realized the advantages of a European trained army over the native ones and this was made possible with the genius of the French Commander Benoit de

Boigne who had now joined the services of Mahadji Scindia. In 1784 Shah Alam sought Mahadji Scindia's help and he joined the Emperor with a large force and restored the Em-

peror to full sovereignty after the latter was relegated to the position of a puppet by Afrasiab Khan the Minister at the court. Soon enough Afrasiab was murdered and Shah Alam conferred the title of Vakil-ul-mutlaq on Mahadji making him virtually the master of the Mughal dominions.

In 1788, Mahadji again had to intervene in Delhi when the court of Mughals fell to a Rohilla adventurer Ghulam Kadir and Shah Alam was imprisoned and blinded. Mahadji Scindia restored the throne to Shah Alam and in return for his services the emperor conferred on him the dignities of Vakil-ul-mutlaq and Naib-vakil, also the order of Mahi Maratib was conferred on him. Mahadji Scindia died in 1794 in Poona.

Shrimant Daulat Rao Scindia (1794-1827) CE

Daulat Rao Scindia succeeded to the throne at the young age of 15. In 1810 Daulat Rao pitched his standing camp near Gwalior at a place which henceforth became known as Lashkar and became the new chief town superseding the former capital of Ujjain. On March 21, 1827 Daulat Rao died at the age of forty-eight.

He had not named his successor and hence a boy named Mugat Rao belonging to another branch of family was adopted and succeeded as Jankoji Rao Scindia on June 27, 1827. The Regency was entrusted to Baiza Bai the widow of Daulat Rao. Jankoji Rao died on 7th February 1843. A young boy of eight years of age named Bhagirath Rao was adopted and named Jayaji Rao Scindia.

Shrimant Jayaji Rao Scindia (1843-86) CE

Jayaji Rao was still very young when the 1857 revolt broke out. In 1861 Jayaji Rao was conferred a G.C.S.I and in 1877 he was granted a personal salute of 21 guns and made a Councilor of the Empress and later on became a G.C.B. and C.I.E.

Maharaja Jayaji Rao died on 20th June 1886 and was succeeded by his son

Madhav Rao Scindia I a boy of ten years of age. A council of Regency was appointed which conducted the affairs of the State till 1894, when the Maharaja was granted powers. The Maharaja became G.C.S. I. in 1895 and in 1901 Aide-de-Camp to the King Emperor.

The marriage of Madhav Rao Scindia I with Maharani Chinkoo Raje, daughter of Madho Rao Mohite was solemnized in 1891. The sisters of Madhav Rao Scindia I were Tara Raje,

Gunwanta Raje and Mannu Raje

Daulat Rao Scindia

He is known as the 'Father of modern Gwalior' and did a great deal to encourage the development of modern industry and improve farming methods. He was also enlightened enough to introduce the democratic government to Gwalior for e.g. the directly elected Municipal councils in 1903, the panchayati system of government in 1907.

He is the author of 'Policy Darbar' an authoritative work on administration.

He died in Paris in 1925 while on his way to England and was succeeded by his young son George Jiwaji Rao Scindia on 27th September 1925

Shimant Jiwaji Rao Scindia (1925-61)CE

Jiwaji Rao Scindia was born in 1916 and succeeded his father in 1925. He ruled up to 1947 as the last ruler of Gwalior state and up to 1956 as a Raj Pramukh or the head of Madhya Bharat Government. He was instrumental in furthering the good work pioneered by his father and brought in administrative reforms to strengthen the revenue, judicial, education and planning in the state

leading to its all round prosperity. In 1941 the marriage between Maharaja George Jiwaji Rao Scindia and Lekha Divyeshwari Devi (renamed as Vijayaraje Scindia) was solemnized. He died in 1961. He lived up to his death in Nau Talav Palace (present Usha Kiran Palace), Gwalior.

Shrimant Madhav Rao Scindia II

Shrimant Madhav Rao Scindia was born to the last ruling Maharaja of Gwalior, Jiwaji Rao Scindia. He was educated at the Scindia School, endowed by his family in Gwalior, Winchester School and then at Oxford University. After India's independence in 1947, his father acceded to the Indian government and the kingdom of Gwalior became part of the new state of Madhya Bharat, which in 1956 was merged into Madhya Pradesh.

He followed the political tradition laid down by his mother Rajmata Vijayaraje Scindia, who was elected to the Lok Sabha (Lower house in the Indian Parliament) in 1971. A charismatic leader & nine-term member of the Lok Sabha, Madhavrao Scindia never lost an election since 1971, when he won for the first time from Guna at the age of 26. He contested

as an independent with the support of the Jan Sangh, a party that his family had for long patronised. In 1977, he switched to the Congress Party despite resistance from his larger family, and won the seat a second time. In order to avoid a direct contest with his mother, he ran from the neighbouring constituency of Guna. But in 1984, he was nominated the Congress candidate in Gwalior as a last-minute manoeuvre to defeat the Bharatiya Janata Party's Atal Behari Vajpayee, and won by a massive margin. Since then he contested from either Gwalior or Guna and won on each occasion.

The 1984 election brought Scindia his first experience as a Minister. He made his mark as an excellent administrator during his stint as Railways Minister in the Rajiv Gandhi Ministry. He is credited with the modernisation and computerisation of India's Railways and with maintaining the most cordial and professional relationship with his managerial cadres.

He was also the Minister for Civil Aviation but resigned in 1992. Shrimant Madhav Rao Scindia was later reinducted into the Cabinet in 1995 as Minister for Human Resource Development. He is also accredited with setting up of Indian Institute of Information Technology and Management (IIITM) at Gwalior as an institution of repute, which got renamed after Shri Atal Behari Vajpayee as ABV-IIITM. Scindia's political role and influence within the Congress party grew rapidly and he was seen as a potential Prime Ministerial candidate. His tragic demise in what was reported as a plane "crash" demolished many hopes. His son, Jyotiraditya Scindia was formerly a Member of Parliament to the seat that he held. He was formerly a minister in Dr. Manmohan Singh government as Minister of State, Ministry of Commerce and Industry. His daughter Chitrangada Raje Singh is married to the Crown Prince of Kashmir. He was the President of the Board of Control for Cricket in India from 1990 to 1993.

Shrimant Jyotiraditya Madhav Rao Scindia (2001-present)

Shrimant Jyotiraditya M Scindia was born on 1st January 1971 in Mumbai to Shrimant Madhav Rao Scindia and Shrimant Madhavi Raje Scindia. He studied at Champion School, Mumbai before going on to The Doon School in Dehradun. He received a B.A. in Economics in 1993 from Harvard University in the United States and an M.B.A. in 2001 from the Stanford Graduate School of Business, United States. He worked as an investment banker

for Merrill Lynch and Morgan Stanley and also gained some development experience working as an intern with the UN Economic Development Cell. He in fact has the distinction of being the only under graduate intern there. He was elected to the Lok Sabha (Lower House of the Indian Parliament) in February 2002 from Guna District - formerly represented by his father. He was re-elected to the 14th Lok Sabha when he won the elections in May 2004. He retained the seat in the 2009 general elections and was inducted in the Cabinet for the first time as Union Minister of State for Commerce & Industry Government of India. He was re-elected in 2014 from the same constituency of Guna'. He is married to Priyadarshini Raje Gaekwad of Baroda and has two children, Yuvraj Maharyaman Scindia (born in 1995) and Ananya Raje Scindia (born in 2002).

Yuvraj Shrimant Mahanaaryaman Scindia

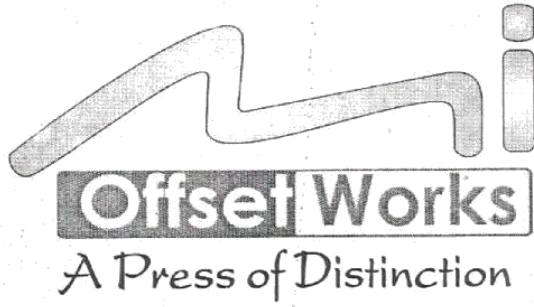
Yuvraj Shrimant Mahanaaryaman Scindia was born on 17th Nov 1995. he has completed his school education from Doon School, Dehradun.

References :

Ramusack, Barbara N. (2004). The Indian Princes and their States. The New Cambridge History of India. Cambridge University Press. p. 35. ISBN 9781139449083.

Edwardes, Michael (1975) Red Year. London: Sphere Books; p. 124

Richard M. Eaton (19 December 2005). A social history of the Deccan, 1300-1761: eight Indian lives. Cambridge University Press. pp. 188-. ISBN 978-0-521-25484-7. Retrieved 16 July 2011.



9893086017
9993673675
8085556284

एम.आई.आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल
प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल

mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com



TAKSHSHILA COLLEGE

Gram - Jhirniya, Post-Mugalia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bioara Road, Bhopal

SINCE 1996

Recognised by NCTE New Delhi, Govt. of Madhya Pradesh & Affiliated to Barkatullah University Bhopal, M.P Board of Sec. Education (M.P)

Admission Through
Online Counseling



Courses Offered

Under Graduate Programs

B.Com. (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)

B.Sc. (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)

B.C.A. (Computer Application)

B.A. (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)

B.B.A.

Post Graduate Programs

M.Sc. (Computer Science, Chemistry)

M.Com. (Tax, Management)

M.C.M.

P.G.D.C.A.

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.



Facility

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching faculty (Hindi, English).
- Well Experience & Qualified staff.
- College Bus facility.
- Well Equipped Laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level
Scholarship for
Deserving Students

M.P. Online
Kiosk Facility
Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449



SINCE 1996

तक्षाशिला कॉलेज

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त तथा वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध)

Courses Offered

Under Graduate Programs

B.Com. (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)

B.Sc. (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)

B.C.A. (Computer Application)

B.A. (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)

B.B.A.

Post Graduate Programs

M.Sc. (Computer Science, Chemistry)

M.Com. (Tax, Management)

M.C.M.

P.G.D.C.A.

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

विगत 19 वर्षों
से उच्च शिक्षा के
क्षेत्र में प्रतिष्ठित
महाविद्यालय

रचना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल नवीन एवं विशाल भवन में स्थानांतरित

प्रवेश
Online Counseling



Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449